हरियाणा विधान सभा

की कार्यवाही

16, मार्च, 1988

खण्ड 1, अंक 3

अधिकृत विवरण

विषय सूची

बुधवार, 16 मार्च, 1988

पृष्ठ संख्या

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(3)1
नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	(3)26
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव	
जिला सोनीपत में ओलावृष्टि से नष्ट हुई रबी फसल संबंधी	(3)27
नियम 121 के अधीन प्रस्ताव–	
समितियों के गठन संबंधी नियमों का निलम्बन	(3)27
राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)	(3)30

हरियाणा विधान सभा

बुधवार, 16 मार्च, 1988

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर 1, चण्डीगढ़ में प्रातः 9.30 बजे हुई। अध्यक्ष (सरदार हरमोहिन्दर सिंह चट्ठा)ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्षः मैम्बर साहेबान, अब क्वैश्कन्ज होंगे।

तारॉंकित प्रश्न संख्या 203

यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि माननीय सदस्य, कामरेड हरपाल सिंह, इस समय सदन में उपस्थित नहीं थे।

Purchase of sugarcane by Sugar Mills

***210. Shri Lachhman Singh Kamboj :** Will the Minister of State for Co-operation be pleased to state—

(a) whether Government is aware of the fact that payment for the purchase of sugarcane except C.O.J. 64 variety is being made by the Sugar Mills in the State @ Rs. 28 per quintal instead of Rs. 32 as announced by the Government; and

(b) if so, the reasons therefor ?

Minister of State for Cooperation (Dr. Raghuvir Singh) :

a) & (b) : Haryana Government has fixed the per quintal rate of sugarcane at Rs. 32 for C.O.J. 64, Rs. 30 for C.O. 7717 and C.O. 7314 and Rs. 28 for general varieties for the current crushing season. All the seven Cooperative Sugar Mills are making regular payment of sugarcane in accordance with the, rates fixed by the Government.

श्री लछमन सिंह कम्बोजः अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने अपने जवाब में बताया है कि सी०ओ० 7717, 7314 और सी०ओ० जे० 64 जोकि अर्ली वैरायटीज हैं उनका रेट 30 व 32 रुपए पर क्विंटल है। मैं उन से यह जानना चाहता हू कि 767 और 768 ये दो गन्ने की अर्ली वैरायटीज हैं इनके रेट्स पर–क्विंटल जिन किसानों के पास बहुत थोड़ा गन्ना है उनको यह सतोष नहीं हो रहा है कि उनको पर्चियां मिल जाएंगी। मैं मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जिन किसानों के पास थोड़ा गन्ना है क्या उनको समय पर पर्चियां मिल जाएंगी?

डा० रघुबीर सिंह : स्पीकर साहब, जो पर्चियों की डिस्ट्रीब्यूशन है वह गन्ने की वैरायटीज के हिसाब से है। गन्ने की जो अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी है उसको पहले पर्ची दी जाती है, जो मिड वैरायटी है उसको बीच में पर्ची दी जाती है और जो लेट वैरायटी है उसको बाद में पर्ची दी जाती है। इस तरह से अर्ली, मिड और लेट वैरायटी के हिसाब से पर्चियां दी जाती हैं। इसमें गमे की क्यालिटी का सवाल नहीं है।

श्री हरनाम सिंहः स्पीकर साहब, यह आम शिकायत सुनने में आ रही है कि कांटे पर जो कर्म चारी बैठे हैं वे ज्यादा गन्ना तोलते हैं। मैं मन्दी जी से जानना चाहूंगा कि कांटों पर कितनी चौकिंग होती है और शूगर मिक्स के मेन कांटे पर कितनी चौकिंग होती है और ऐसी चौकिंग करने के बाद उनके रिजल्ट क्या रहे हैं और उन पर क्या ऐक्शन लिया गया है?

डा० रघुबीर सिंहः स्पीकर साहब, जो हमने चौकिंग की थी उसमें किसी तरह का कोई फाल्ट नहीं मिला। यह अखबार में एक दफा जरूर आया था कि ऐन्टी क्रप्शन बोर्ड की तरफ से एक छापा मारा गया था, उसमें यह बात अवश्य आई थी जो मैम्बर साहब कह रहे है। उस पर हम ऐक्शन ले रहे हैं। हमने हरेक एम० डी० को हिदायतें दी हुई हैं कि वे महीने में कम से कम 5– 1० बार अवश्य रोजाना कांटों पर जा कर चौकिंग करें। जहां तक ये पूछ रहे हैं कि कितनी चौकिंग की गई और क्या ऐक्शन हुआ, यह डैटा इनको बाद में सप्लाई कर दिया जाएगा।

श्री टेक चन्दः मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि कितने शूगर मिल्ज घाटे में और कितने शूगर मिल्स फायदे में चल रहे हैं और जो मिल फायदे में चल रहे हैं उन में से किसानों को कितना हिस्सा दिण गया है। क्या मन्त्री जी मिल वाईज यह जानकारी बताने की कृपा करेंगे?

डा० रघुवीर सिंहः जहां तक लाभ या हानि का संबंध है इस बारे में मैं अपने साथी को बताना चाहूंगा कि ऐसी पैलेस शीट तो सीजन समाप्त होने पर बनती है। एक बात मैं इन्हें बताना चाहूंगा कि अब की बार कल तक पिछले साल के मुकाबले 2 लाख क्विंटल गन्ना अधिक पीड़ा जा चुका है इसलिए घाटे का कोई सवाल ही नहीं उठता। जहां तक किसानों को मुनाफे में हिस्सा देने की बात है वह भी उसी रेशो

प्रो० सम्पत सिंहः उस टाईम पर कानून व व्यवस्था वाली बारत नहीं थी। जो मांग उन्होंने की उस पर सिम्पैथेटिक कशिड्रेशन हुआ और गवर्नमैंट की बाकायदा यह नीति है कि जायज मांग पूरी की जाए।

सिंचाई तथा बिजली मन्त्री (श्री वीरेन्द्र सिंह): स्पीकर साहब, डा० मंगल सैन जी ने अपने सवाल में स्पैसिफिकली पूछा है कि वहां पर लाठी चार्ज हुआ या नहीं, उनका सामान उठा कर ले गए या नही? उसका मन्त्री जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में जवाब दिया है कि लाठी चार्ज नही और हुआ और न ही उनका सामान उठाया गया। डिप्टी कमिश्नर ने उनकी फरियाद सुनी या न सुनी? इसका जवाब यह है कि डिप्टी कमिश्नर ने फरियाद सुनी और जहां तक ऐक्शन वाली बात है, उस बारे में उसने यह भी देखना था कि फरियाद जायज थी या नाजायज थी, इस बारे में हम क्या कह सकते. हैं। वहां पर नौ वर्क रों ने धरना दिया हुआ है। वह इसलिए दिया हुआ है कि नौ मजदूरों को निटहाल दिया था।

पहले फैक्टरी बड़े अच्छे ढंग से चल रही थी। जब उन्होंने लायल वर्करों को भड़काया तो मैनेजमैंट ने उनकी सर्विस टरमिनेट कर दी। इस बिनाह पर वे धरना दे कर बैठे हुए हैं।

श्री रघु यादवः अभी मन्त्री महोदय ने कहा है कि किसी की भी फरियाद 24 घण्टे सुनी जाती है। क्या मन्त्री जी के नोटिस में यह बात है कि पुलिस वाले बाजारों में घूमते रहते हैं तथा थानों में शराब पी कर बैठे रहते हैं?

श्री अध्यक्षः यह कोई सवाल नही है, आप बैठें।

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, मेरे दोस्त श्री वीरेन्द्र सिंह ने होम मिनिस्टर साहब की मदद के लिए फरमाया कि फरियाद कैसी थी, हमें पता नहीं वह जायज थी या नाजायज थी। मैंने तो बडी सिम्पल बात पूछी थी कि क्या वे लाठी से घायल होने के बाद डी० सी० के पास गए थे, ये कहते हैं कि लाठी चार्ज हुआ ही नहीं। तो स्पीकर साहब, मैं अपने मन्दी जी से कहूंगा कि लाठी चार्ज हुआ शै। यहां पर श्री लछमन दास बजाज बैठे हुए हैं, उन से पूछा जा सकता है कि लाठी चार्ज हुआ या कि नहीं?

Mr. Speaker : Please have your seat. It is not the question. You are arguing your case. You can only put the question.

Shri Mangal Sein : I am putting the question slowly Sir,क्योंकि अपने प्यायंट को डिवैल्प करने में मुझे थोड़ा सा टाईम लगता है। मैं सिंचाई तथा बिजली मन्दी श्री वीरेन्द्र सिंह जी से

जानना चाहता हूं कि वे लोग डी० सी० के पास क्या फरियाद ले कर गए और डी० सी० ने उस के ऊपर क्या ऐक्शन लिया?

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, मैंने अभी बताया कि ऐसे लोगों की फरियाद क्या हो सकती है? जो नौर्मल ढंग से फैक्टरी काम कर रही थी, 8–9 वर्कर्ज ने वहां के वर्कर्ज क्रो भड़काया और उस फैक्टरी को बन्द करवाना चाहा। इंडस्ट्री की डिवैल्पमैंट में रुकावट डालनी चाही। ऐसे लोगों की क्या फरियाद हो सकती है? वे लोग किस–किस्म की फरियाद करने गए उसका अन्दाजा आप खुद लगा लें। मैं डाक्टर साहब से प्रार्थना करना चाहता हूं कि अगर ये उन लोगों को धरने से उठवा सकते हैं तो उठवा दें?

Old Age Pension

***391. *Shri Yogesh Chand Sharma and Shri Hazar Chand :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the number of cases detected where pension has been drawn by ineligible persons in the State under the Old Age Pension Scheme during the period from December, 1987 to-date:

(b) the number, out of those as referred to in part (a) above, where such persons have voluntarily paid back the pension amount;

(c) the number of such persons against whom criminal proceedings have been launched for obtaining

pension fraudulently; and

(d) whether any officer/official has been found responsible for the lapse, as stated in part (a) above; if so, the number thereof and the action taken against them ?

Industries Minister(Dr. . Kir pa Ram Punia) :

(a) 11,783,

(b) 2,945.

(c) F.I.R.s have been registered against 569 persons.

(d) The work of checking of ineligible beneficiaries is continuing. It would be possible to fix responsibility only after the completion of checking.

श्री योगेश चन्द शर्मा: स्पीकर साहब, मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि जिन लोगों को पैशन मिलनी रह गई है, उनकी पैंशन कब तक सैक्शन हो जाएगी?

डा० किरपा राम पुनिया: स्पीकर साहब, 6 लाख 41 हजार लोगों की पैशन मन्जूर हो चुकी है। इस बारे में सभी जिलों में दो–दो बार सर्वे किया जा चुका है। इसके बावजूद भी कई जगह से शिकायत मिली है जहां 5– 7 आदमियों को पैंशन मिलनी रह गई है। इसके लिए डी० सीज० को हिादायत दी गई है। स्कीम के शुरु में प्रोग्राम यह बना था कि चुनाव वाले दिन यानी 17 जून, 1987 को जिन लोगों की उम्र 65 साल हो गई है, उनको 17 जून,

1987 से पैशन मिलेगी। उसके बाद 31 मार्च, 1988 तक जिन की उम्र 65 साल की हो जाएगी उनकी 1–4–88 से पैंशन मन्जूर हो जाएगी। जो लोग मार्जिनल ग्रुप में आते हैं यानी जिन की उम्र 62–63 साल की है वे भी कोशिश कर रहे हैं कि उनको भी 17 जून, 87 से पैशन दी जाए। लेकिन हमने यह फैसला लिया है कि जिन की उम्र 31 मार्च, 1988 को 65 साल की हो जाएगी उनकी पैंशन सैंक्शन कर दी जाएगी।

श्री योगेश चन्द शर्मा: स्पीकर साहब, मैं तो यह जानना चाहता हूं कि जिन ऐलिजिबल लोगों को पैशन मिलनी चाहिए वे कितने रह गए हैं?

Mr. Speaker : How can he say this? Applications continue to pour in and some of the applicants may not be eligible.

Shri Yogesh Chand Sharma : Sir, I want to know how many persons have applied for pension ?

डा० किरपा राम पुनिया: स्पीकर साहब, इस में ऐसा है कि 31– 10–87 तक हमारे पास टोटल 6 लाख 7 छ हजार ऐप्लीकेशन्ज आई थीं। उन में से 6 लाख 8 हजार के करीब व्यक्तियों को पैन्शन सैक्शन कर दी गई थी और 70 हजार ऐप्लीकेशन्ज रिजैक्ट कर दी गई थीं। उसके बाद अब दिसम्बर, 1987 तक हमारे पास 6 लाख, 93 हजार ऐप्लीकेशन्न आई हैं। उसके बाद प्राप्त ऐप्लीकेशन्ज की इन्फर्मेशन हमारे पास उपलब्ध

नहीं है। इन 6 लाख 93 हजार ऐप्लीकेशन्ज में से दिसम्बर, 1987 तक 6 लाख, 23 हजार की पैशन सैक्शन कर दी गई थी और अब छः लाख इकतालिस हजार छः सौ तीन व्यक्तियों की पैशन सैक्शन हो चुकी

श्री जगन नाथः स्पीकर साहब मन्त्री जी ने अभी कहा कि जिन की उम्र 31 मार्च, 1988 को 65 साल की हो जाएगी उनको पैंशन मजूर की जाएगी। अगर किसी आदमी की उम्र 1–4–88 को 65 साल की होती है तो उसका केस ग्यारह महीने के लिए और पैंडिंग पड़ जाएगा। तो क्या 31 मार्च की शर्त को वे हटाएंगे?

डा० किरपा राम पुनियाः स्पीकर साहब, ग्यारह महीने नहीं बल्कि बारह महीने पैंडिंग पड़ जाएगा। स्पीकर साहब, ऐसा है कि किसी सिस्टम को एडौप्ट करने के लिए कोई न कोई डेट तो लेनी पड़ती है। 31 मार्च को फाइनैंशियल इयर क्लोज होता है इसलिए यह निर्णय लिया गया था कि 31 मार्च की डेट रखी जाए। अगर हम कोई बीच की डेट रख देते तो लोग धक्के खाते फिरते रहेंगे। इसलिए निर्णय लिया गया कि हर साल इसी तरह से सिस्टम एडौप्ट किया जाएगा और लोगों को एक अप्रैल से पैशन सैक्शन हो जाएगी।

श्री हीरा नन्द आर्यः स्पीकर साहब, अभी मन्त्री जी ने जवाब में बताया कि 569 आदमियों के खिलाफ एफ० आई० आर०

दर्ज की गई हैं जिन्होंने बुढ़ापा पैंशन लेने के लिए गलत ऐप्लीकेशन्ज दी थीं। मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि जिन अधिकारियों ने उनकी गलत पैशैन सैक्शन की क्या उनके खिलाफ भी कोई कार्यवाही की जाएगी?

डा० किरपा राम पुनिया: स्पीकर साहब, क्वैश्चन के पार्ट (डी)के रिप्लाई में मैंने स्पष्ट किया है कि अभी तक चौकिंग की कार्यवाही जारी है और यह कार्य– वाही पूरी तसल्ली के साथ की जाएगी। जहां कहीं कोई सरकारी कर्मचारी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

श्री मनी राम: स्पीकर साहब, जिन लोगों ने नाजायज पैंशन ली थी, और वे सरकार से रिक्वैस्ट कर रहे हैं कि उन्हें माफी दी जाए, क्या उनके केसिज पर सरकार विचार कर रही है?

10.00 बजे।

डा० किरपा राम पुनिया: पिछले दिनों हमारे आदरणीय मुख्य मन्त्री जी का अखबारों में भी ब्यान आया था कि जिन्होंने जान–बूझकर या गलती से ओल्ड एज पैंशन ले ली है वे 15 फरवरी तक पैशन सरैंडर कर दें। 4 हजार के करीब लोगों ने यह पैंशन सरैडंर भी की है। हमारी ऐसी कोई इन्टैशन नहीं है कि जो वोलैटैरिली या हमारी अपील पर सरैंडर कर रहे हैं उनको कोई सजा दी जाए। अगर कोई आदमी पैशन सरैडर कर देता है तो उसके केस में सहानुभूतिपूर्वक कार्यवाही की जाएगी।

श्री महा सिंहः स्पीकर साहब, इस पैशन को देने के बारे में हमारे सदन के नेता ने कहा है कि वृद्धावस्था में बुढ़ापा पैंशन देकर उनका सम्मान करना है। कहने का मतलब यह है कि उनको सम्मान देने के लिए यह पैशन दी गयी है। जब यह बुढ़ापा पैशन के लिए फार्म भरवाने के लिए टीम तहसील हैडक्वार्टर्ज से गांवों में गयी तो बदकिस्मती से कुछ ऐसे लोग गांवों में नहीं थे। इस तरह से कुछ ऐलिजिबल लोग अभी पैशन से वंचित रह गए हैं। मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि वृद्धावस्था को सम्मान देने वाली भावना को बरकरार रखने के लिए क्या दोबारा अपनी टीम गांवों में भेजने के लिए सरकार तैयार है?

डा० किरपा राम पुनियाः स्पीकर साहब, इस बात का जवाब तो मैंने दे दिया है लेकिन मैं एक बार फिर आदरणीय सदस्य की जानकारी के लिए उसको दोहरा देता हूं कि इस के लिए दो बार मौका दिया जा चुका है। सरकार की तरफ से यह हिदायत गयी हुई है कि अगर कोई केस डी०सी०, एस०डी०एम० या डिस्ट्रिक्ट सोशल वैल्फेयर औफिसर के नोटिस में आता है, तो उसको कंसिडर किया जाए और बुढ़ापा पैशन सैक्शन की जाए। अभी तक यानीं पिछले महीने में ही करीब 10–11 हजार इस तरह की पैशन्ज डी० सीज० ने सैक्शन की हैं और हमें सूची भेजी है।

श्री परमा नन्दः स्पीकर साहब, मन्त्री महोदय ने यह बताया है कि 31– 10–1987 तक 6 लाख 77 हजार ऐप्लीकेशन्ज आयी थीं और उनसे 6 लाख 41 हजार 603 को पैशन दे दी गयी

है। बाकी जो 35,397 केसिज रह गए हैं, क्या उनको इन–एलीजीबल डिक्लेयर कर दिया या वह अभी अंडर कसिड्रेशन हैं। अगर अंडर कसिड्रेशन हैं तो उनका फैसला कब तक हो जाएगा क्योंकि 6–7 महीने तो बीत चुके हैं।

डा० किरपा राम पुनियाः स्पीकर साहब, मैंने यह बात पहले भी स्पष्ट कर दी थी कि टोटल ऐप्लीकेशन्ज 6 लाख 93 हजार के करीब आयी थी और 6 लाख 41 हजार 603 व्यक्तियों को पैंशन मन्जूर कर दी गयी है और बाकी की दरख्वास्ते रिजैक्ट हो चुकी है।

चौधरी तैयब हुसैनः जनाब स्पीकर साहब, मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जितने लोगों के खिलाफ एफ० आई०आर० दर्ज हुई हैं, उनमें से कितनों के खिलाफ एफ० आई० आर० अब तक वापिस हो गयी हैं।

डा० किरपा राम पुनियाः स्पीकर साहब, इस समय तक वापिस तो कोई नहीं हुई है। अभी सारा मामला ही पुलिस के पास अन्डर इन्वैस्टीगेशन है। कानून के मुताबिक उनमें कार्यवाही की जाएगी। अभी तक एक भी केस में चूंकि अदालत में चालान पेश नहीं किया गया है इसलिए वापिस लेने का कोई सवाल ही पैदा नही होता।

श्री जगन नाथः अध्यक्ष महोदय, यह तो रिकार्ड की बात है कि प्री–पार्टीशन के डेज का रिकार्ड अवेलेबल नही है। पहले

जींद और दादरी, पटियाला के साथ लगता था। इसी तरह भिवानी और बहादुरगढ़ भी औरों के साथ लगता था। इन इलाकों के रिकार्ड अवेलेबल नहीं हैं। इस वजह से वहां के लोगों की एज वैरीफाई नहीं की जा सकती। क्या मन्दी जी ऐसा कोई क्राइटेरिया बनाने के लिए तैयार है कि जहां का रिकार्ड अवेलेबल नही है, वहां के लोगों का चेहरा देखकर उनको पैशन दी जाए? (व्यवधान व शोर)

डा० किरपा राम पुनियां: स्पीकर साहब, यह ठीक बात है कि एज के बारे में डाकुमैंटरी ऐवीडैस होनी चाहिए। चौकीदारा रजिस्टर होना चाहिए। ज्यादातर केसिज में यह नहीं मिलता। औथैटिकेटिड रिकार्ड इसको माना जाता है। इसी तरह का अगर दूसरा रिकार्ड अवेलेबल है जैसे राशन कार्ड है या वोटर्ज लिस्ट है, उनको औथैटिकेटिड टूटि नहीं किया जा सकता क्योंकि उनमें काफी गलतियां रह जाती हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए जब यह स्कीम फ्रेम की गयी थी, उस वक्त यह निर्णय लिया गया था कि चेहरा देखकर अगर आदमी 65 साल से ऊपर का दिखता है तो उसको मौके पर ही पैंशन मंजूर कर दी जाए। ब्लौक लैवल पर जो सीनियर औफिसर्ज की एक कमेटी बनी हुई है, उसने ज्यादातर सैंक्शन इसी आधार पर की है। जहां कही पर मार्जिनल प्वायंट है या डिसप्यूटिड केस है, उसमें डिस्ट्रिक्ट लैवल पर एक कमेटी बनी हुई है, उसमें सी० एम० ओ० भी होता है। उसमें एज असर्टेन करके फैसला किया जाता है।

श्री महा सिंहः स्पीकर साहब, पहले गांवों में बूढ़ों की वैरीफिकेशन के लिए एक टीम गई थी लेकिन उस समय कुछ लोग रह गए क्योंकि गांव में से कुछ लोग बाहर किसी काम से गए थे और उनकी वैरीफिकेशन नही हो सकी। इस वजह से उनको पैन्शन नहीं मिल रही है। सरकार ने ऐसे लोगों को कहा कि वे लोग सी०एम०ओ० के पास जाकर अपनी वैरीफिकेशन करवाएं। क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि ऐसे लोगों को गांव में ही टीम भेजकर दुबारा चांस दिया जाएगा जिससे कि वे अपनी वैरीफिकेशन करवा सकें और उनको सी० एम० ओ० के पास न आना पड़े?

डा० किरपा राम पुनियांः इस का जवाब मैं दे चुका हूं।

श्री हजार चन्दः पिछले सैशन में यह विश्वास दिया गया था कि नाजायज पैन्शन लेने वालों की इंक्वायरी की जाएगी और उनके नाम काट दिए जाएंगे और जो लोग पैन्शन के हकदार हैं उनको पैन्शन दी जाएगी और उनसे फार्म भरवाए जाएंगे। क्या मन्दी महोदय बताने की कृपा करेंगे कि पिछले सैशन से इस सैशन तक कितने और नए फार्म भरकर आपके पास आए हैं?

श्री० किरपा राम पुनियाः स्पीकर साहब, यह सूचना तो देना संभव नहीं है कि पिछले सैशन और इस सैशन के बीच में कितनी ऐप्लीकेशंज और आई हैं। लेकिन मैं यह बता सकता हूं कि पिछले सैशन के समय तक 6 लाख 23 हजार पैन्शन्ज सैक्शन

हुई थीं और जो लेटेस्ट इंफरमेशन है उसके मुताबिक 6 लाख 41 हजार 603 पैन्शन्न मन्जूर की जा चुकी हैं। इससे यह अन्दाजा लगाया जा सकता है कि करीब 18 हजार पैन्शन्ज पिछले सैशन से इस सैशन तक मन्जूर की गई हैं।

श्री कैलाश चन्द शर्मा: क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जो महिलाएं विधवा पैन्शन प्राप्त कर रही थी और अब उनकी आयु 65 साल से ऊपर हो गई है उनकी राशि पचास रुपए से बढ़ाकर सौ रुपए कर दी जाएगी क्योंकि अभी तक उनको पचास रुपए के हिसाब से ही पैन्शन भेजी जा रही है?

डा० किरपा राम पुनिया: स्पीकर साहब, जिनकी आयु 65 साल से ऊपर हो गई है उनके बारे में कोई गड़बड़ नहीं है। उनको सौ रुपए के हिसाब से पैन्शन मिल रही है। जहां तक विडोज की पैन्शन पचास रुपए से बढ़ाने का सवाल है यह मामला विचाराधीन है। इस बारे में शीघ्र ही फैसला ले लिया जाएगा।

Number of I.A.S., I.P.S. & H.C.S. Officers in the State

***305. Shri Hira Nand Arya :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the number of I.A.S./I.P.S./H.C.S. officers on the cadre of the Haryana State at the time of its formation on 1-11-1966 togetherwith the cadre of the posts of Financial Commissioners/Commissioners/Secretaries to Government/ I. Gs. P./D. I. Gs. P., separately; and

(b) the number of such officers togetherwith cadre of such posts, as referred to in part (a) above, at present ?

Irrigation and Power Minister (Shri Verender Singh) :

(a) and (b) : The requisite information is placed on the Table of the House.

Statement

(a) (i) The number of I.A.S./I.P.S./H.C.S. Officers on the cadre of Haryana State at time of its formation on 1-11-1966 was as under :—

I.A.S.	63
I.C.S.	7(including one I.C.S. officer permanently seconded to I.F.S.)
Total	70
I. P. S.	35
H. C. S.	118

(ii) The authorised cadre strength of Financial Commissioner/Commissioners/Secretaries to Govt./I.Gs.P./ D.I.Gs.P. in Haryana State on 1-11-1966 was as under :-

Financial Commissioner	1
Commissioners of Divisions	1

Secretaries to Govt. in Commissioner's rank	2
Other Secretaries to Govt.	4
I.Gs. P.	1
D.I.Gs.P.	2

(b) (i) The strength of I.A.S./I.P.S./H.C.S. Officers in Haryana State at present is as follows :—

I.A.S.	187
I.C.S.	Nil
I.P.S.	82
H.C.S.	164

(ii) The break up of authorised cadre strength of Financial Commissioners / Commissioners / Secretaries to Govt./ I.Gs.P./D.I.Gs.P. in Haryana State is as under :—

Financial Commissioner	3
Commissioner of Divisions	2
Secretaries to Govt. in Commissioner's rank	7
Other Secretaries to Govt.	Nil
I. Gs. P.	1
D. I. Gs. P.	8

श्री हीरा नन्द आर्यः स्पीकर साहब, अगर हम स्टेटमैंट देखें तो पता लगता है कि जब हरियाणा बना था उस समय 7० आई० ए०एस० थे और अब 187 हैं। एच० सी० एस० 118 थे और अब 164 हैं। पिछले सालों में बहुत भारी भरकम ऐडमिनिस्ट्रेशन हो गया है और इस टौप हैवी ऐडमिनिस्ट्रेशन पर बहुत पैसा खर्च हो रहा है। क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि इस भारी भरकम ऐडमिनिस्ट्रेशन को कम किया जाएगा और पैसा बचाकर नौन प्लान ऐक्सपैडीचर कम किया जाएगा तथा डिवैल्पमैंट के कामों पर पैसा खर्च किया जाएगा?

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, माननीय सदस्य ने आकड़े देखकर यह अन्दाजा लगा लिया कि भारी भरकम ऐडमिनिस्ट्रेशन है। स्पीकर साहब, 1966 में हरियाणा का बजट 125 करोड़ या 150 करोड का था और आज हमारा बजट 1500 करोड़ रुपए का है। जब हरियाणा बना था उस वक्त न तो कोई बोर्ड था और न ही कोई कारपोरेशन थी। डिवैल्पमैंट ऐक्टीविटीज न के बराबर थीं। 1966 से आज हम 1988 में आ गए है। इन 22 साल में बहुत से बोर्डज बन गए हैं और कारपोरेशन्ज बन गई हैं और बजट दस गुणा हो गया है। डिगर्टमैंट्स बहुत ऐड हो गए हैं। इन सारी बातों को देखकर मैं महसूस करता हूं कि ऐड– मिनिस्ट्रेशन को कम करने की कोई बात नही है।

श्री हीरा नन्द आर्यः अध्यक्ष महोदय, अभी मन्त्री महोदय ने जवाब देते हुए बताया कि जब 1966 में हरियाणा बना उस वक्त

हमारा बजट कोई लगभग 125– 150 करोड़ के करीब था और आज हमारा बजट 1500 करोड़ के लगभग शै। मैं उन से यह जानना चाहता हूं कि उस वक्त प्रशासन का कितना खर्चा था और अब प्रशासन का कितना खर्चा है?

Shri Verender Singh : This is not relevant here

Mr. Speaker : It is not possible to give answer to this supplementary. Moreover, this supplementary does not relate to the main question.

श्री हीरा नन्द आर्य: अध्यक्ष महोदय, जब भी बजट में कटौती की जाती है तो क्लास 3 और क्लास 4 के कर्मचारियों पर ही इसका असर पड़ता है। ऐसा करने से सरकार की इकौनौमी में कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। मैं इनसे जानना चाहता हूं कि क्लास 1 पर इस तरह की कटौती क्यों नहीं लगाई जाती ताकि सरकार को इस से काफी फायदा हो? क्लास 3 और क्लास 4 की बजाए क्लास 1 पर इस तरह की कटौती लगाई जानी चाहिए।

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, अब तो हर जगह ही कट लगी हुई है।

Styer make bearings

***343. Chaudhri Shiv Lal :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) whether any order for the purchase of `Styer make bearings' was placed by the Superintending Engineer

(Electricity), Yamuna Nagar with any firm during the year 1987-88; and

(b) if so, the name of the firm on. which the said order had been placed ?

Irrigation and Power Minister (Shri Verender Singh) :

(a) Yes.

(b) M/s. Kothari Brothers, Calcutta.

चौधरी शिव लालः अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि यह फर्म खुद मैनुफैक्चरर्र है या इमकी कोई और आगे एजेन्सी मैनुफैक्चरर्र

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, ये आइटमज श्म्पोर्टिड हैं और इम्पोर्ट की जाती हैं।

श्री सुरेन्द्र कुमार मदानः अध्यक्ष महोदय, अभी मिनिस्टर साहब ने बताया कि ये इम्पोर्ट की आइटमज थीं। अगर ये इम्पोर्ट की आईटम थीं तो सरकार ने खुद इम्पोर्ट क्यों नहीं किया और अगर किसी दूसरी पार्टी ने इम्पोर्ट क्रिया है तो क्या इसके लिए टैण्डर काल किए गए थे, अगर टैण्डर काल किए गए थे तो उनका आपस में कितना डिफरैन्स था?

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, बोर्ड के पास इम्पोर्ट लाइसैन्स नहीं था इसलिए ये आइटमज इम्पोर्ट नहीं की गयी थीं। बाकायदा इसके लिए कोटेशन्ज मांगी गई थीं जिनकी कोटेशन

लोयेस्ट थीं, उनको यह काम सौंप दिया गया था। हाइयेस्ट कोटेशन थी 16,745 और लोयेस्ट थी 5,911। 5,911 वाली फर्म को लोयेस्ट होने के नाते आर्डर प्लेस किया गया।

Setting up of Sugar Mills in Tehsil Naraingarh

***253. Shri Jagpal Singh Chaudhri :** Will the Minister of State for Cooperation be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to set-up a Sugar Mill in Tehsil Naraingarh; and

(b) if so, the time by which the aforesaid Sugar Mill is likely to be set up ?

Minister of State for Cooperation (Dr. Raghuvir Singh) :

(a) There is no proposal to set-up a Cooperative Sugar Mill in Tehsil Naraingarh at present.

(b) In view of reply to part (a), question does not arise.

श्री रणजीत सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हू कि नई शूगर मिल्क लगाने की सरकार की क्या पालिसी है और उसके लिए क्या कंडीशन्ज हैं?

श्री रघुवीर सिंहः स्पीकर साहब, तीन नई शूगर मिल्ज लगाने के लिए ऐप्लीकेशन्ज आई थीं उनको हमने मिनिस्टरी आफ फूड, भारत सरकार के पास भेज रखा है और वे अन्डर कसिड्रेशन हैं। We are hopeful for the clearance.

The broad guidelines for licensing of new and expansion of existing sugar factories during 7th Five Year Plan are as under :-

1. The policy followed during the Sixth Plan period viz. grant of licences for the establishment of new sugar factories in the Cooperative sector followed by the public sector, will continue in the 7th Plan. However, in areas where proposals from these two sectors are not received, the proposals from the private sector would be considered.

2. The basic criterion for establishment of a new sugar unit would be the adequate availability of sugarcane in a compact area around the proposed factory site. The potential for cane cultivation would be only an additional factor.

3. Where there are a large number of sugar factories located in one district, State Governments should make proper zoning of sugar cane areas for each existing sugar factory before a request for expanding the capacity of any existing factory or installation of any new sugar factory in that district is considered. State Governments have been delegated with powers to regulate reservation of such areas under the sugarcane (control) order, 1966.

4. To ensure supply of adequate availability of

sugarcane for existing capacity as well as for future expansion, no licence would normally be granted for the establishment of new sugar factories within a radius of 40 Kms. of an existing unit.

5. In regard to the initial licensed capacity of new sugar units and expansion of existing units to be licenced during the 7th Plan period, the new units would be licenced for an initial capacity of 2500 TCD, expansion of existing units would be allowed upto 3500 TCD subject, however, to the availability of adequate sugarcane.

Expansion of capacity of existing units would be permitted upto a maximum of 5000 TCD provided that the additional requirements of sugarcane above 3500 TCD accrue through increased productivity and not by expansion of area under sugarcane.

6. Licensing of new sugar units in backward areas will be given priority subject to adequate availability of sugarcane and techno-economic viability.

7. Industrial licence application for the establishment of new sugar factories as well as expansion of existing units should be submitted to the State Government for onward transmission to the Secretariat for Industrial Approvals in the Department of Industrial Development. The State Government, while forwarding the applications, should give their specific recommendations alongwith clear and comprehensive details of sugarcane availability position in the proposed factory area.

These are seven necessary conditions which should

be fulfilled before forwarding application with no objection certificate for the new sugar mill.

श्री आत्मा राम गोदाराः स्पीकर साहब, अभी मन्त्री जी ने बताया कि तीन शूगर मिल लगाने के लिए तीन ऐप्लीकेशन्ज भारत सरकार के पास पैंडिंग पड़ी हैं। मैं मल्टी जी से यह जानना चाहता हूं कि वे तीनों ऐप्लीकेशन्ज पब्लिक सैक्टर की हैं या प्राइवेट सैक्टर की हैं। अगर वे प्राइवेट सैक्टर की हैं तो उन शूगर मिल्ज को पब्लिक सैक्टर में लाने के लिए सरकार ने कोई प्रयत्न किए हैं, अगर किए हैं तो वे क्या हैं?

डा० रघुबीर सिंहः स्पीकर साहब, वे तीनों ऐप्लीकेशंज कोआप्रेटिव सैक्टर की हैं।

श्री हरनाम सिंहः स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा मन्दी जी से जानना चाहूंगा कि कोआप्रेटिव सैक्टर में जो पहले शूगर मिल चल रहे हैं, क्या उनकी कैपेसिटी इनक्रीज करने के लिए सरकार ने कोई प्रयत्न किए हैं, अगर प्रयत्न किए हैं तो वे क्या है?

Dr. Raghuvir Singh : Sir, separate notice is required for this.

श्री जगपाल सिंह चौधरीः स्पीकर साहब, भारत वर्ष आजाद होने के बाद अम्बाला जिले में कोई शूगर मिल नही लगा है। एक प्राइवेट पार्टी अम्बाला जिले में एक शूगर मिल लगाने के लिए तैयार है लेकिन उस प्राइवेट पार्टी को शूगर मिल लगाने के

लिए नो–औब्जैक्शन सार्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा है। मैं मन्त्री जी से जानना चाहता, हूं कि उस प्राइवेट पार्टी को शूगर मिल लगाने के लिए नो–औब्जैक्शन सर्टिफिकेट क्यों नहीं दिया जा रहा है जबकि अम्बाला जिले में गन्ना काफी मात्रा में पैदा होता है।

डा० रघुबीर सिंहः स्पीकर साहब, माननीय सदस्य ने कहा कि इनके जिले की किसी प्राइवेट पार्टी ने शूगर मिल लगाने के लिए ऐप्लीकेशन दी हुई है वह ऐप्लीकेशन मैसर्ज यूनाइटिड बनास्पति ने दी हुई है। This application is still pending with Government for decision.

Rural Housing Scheme

***277. Shri Maha Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to give money direct to the villagers holding a minimum of 100 metre plots for construction of houses under the Rural Housing Scheme in the State ?

Minister of State for Housing (Shri Subhash Chand Katyal) : Yes, Sir.

श्री महा सिंहः अथ्यक्ष महोदय, पिछली सरकार ने इन्दिरा आवास कालोनीज बसाने के नाम से गांवों में मकान बनाए थे। इन मकानों में पैसा भी काफी लगा दिया गया लेकिन मकान किसी काम के नहीं बनाए गए थे। उन मकानों को कोई भी लेने के लिए तैयार नहीं हुआ। मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि

गांवों में जिन गरीब लोगों के पास 100 गज का प्लौट है था जिनके पास प्लौट नही है, क्या उन्हें प्लौट देकर मकान बनाने के लिए बोर्ड की तरफ से वित्तीय सहायता दी जाएगी? यदि आधा पैसा बोर्ड की तरफ से दे दिया जाए और आधा पैसा वह गरीब आदमी स्वयं लगा ले तो वह अपनी जरूरत के अनुसार अच्छा मकान बना सकता है। मैं साथ ही साथ यह भी जानना चाहूंगा कि ऐसे मकान बोर्ड की तरफ से बनाने की बजाए वे खुद बनाए, इस बारे में सरकार कब तक फैसला कर देगी?

श्री सुभाष चन्द कटियालः हमने इस काम के लिए 2 करोड़ 50 लाख रुपए इस चालू वर्ष में रखे हुए है। अब यह शर्त नहीं है कि 100 गज प्लौट जिसके पास है उसको ही लोन मिलेगा। जो भी व्यक्ति मकान बनाने के लिए लोन लेना चाहेगा उसको लोन मिल जाएगा स

चौधरी सतबीर सिंह कादियानः क्या मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगें कि पिछले 7–8 सालों से जो मकान बने पड़े हैं, उनमें लोग रहने के लिए गए हैं, अगर नहीं गए तो उसके क्या कारण हैं?

श्री सुभाष चन्द कटियालः ऐसे मकान पिछली सरकार ने 3033 बनवाए थे। पिछली सरकार की वह स्कीम डिफैक्टिव थी। इन 3033 मकानों में से सिर्फ 970 मकानों का ही कब्जा लोगों ने लिया था। इसका एक कारण तो यह था कि ये मकान एक–एक

कमरे के बनाए हुए थे जिन्हें लोगों ने पसन्द नही किया क्योंकि वे रिहायश के काबिल नही थे। दूसरे ये मकान गांवों से भी दूर बनाए गए थे।

चौधरी सतबीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री जी के नोटिस में लाना चाहूंगा कि मेरे हल्के के सिवाह गांव में ऐसे ही काफी मकान बने हुए पड़े हैं। वे अभी तक लोगों नें नही लिए, जिसकी वजह से वे खराब होते जा रहे हैं और गिरने शुरू हौ गए हैं। मैं मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि उनमें लोग जाने के लिए तैयार क्यों नहीं हैं?

श्री सुभाष चन्द कटियालः इसका उत्तर मैं पहले ही दे चुका हूं।

श्री हीरा नन्द आर्यः मैं मन्त्री जी से जानना चा हूंगा कि जो राशि गरीब लोगों को मकान बनाने के देने हेतु रखी गई है, उससे इस साल कितने तोरा लाभान्वित होंगे और अगले साल के लिए कितने लोगों को लाभ पहुंचाने का विचार है?

श्री सुभाष चन्द कटियालः इस साल के लिए 2 करोड़ 5० लाख रुपए रखे गए हैं। हम एक आदमी को 5 हजार रुपया देते हैं। जितनी ऐप्लीकेशन्ज आएंगी उसी हिसाब से यह अमाउंट उनमें बांट दी जाएगी।

श्री महा सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री जी को यह बताना चाहूंगा कि 5000 रुपए की राशि मकान बनाने के लिए बहुत

कम है। यदि यही राशि रखी गई तो पिछली सरकार ने जो स्कीम ऐसे मकान बनाने के लिए बनाई थी, और जो फेल हो गई थी, यह स्कीम भी उसी तरह से फेल हो जाएगी। मेरा मन्दी जी से यह निवेदन है कि इस राशि को कम से कम 15 हजार रुपए किया जाए ताकि वे लोग आसानी से अपने रहने लायक बना मकान बना सकें।

श्री अध्यक्षः यह कोई सवाल नहीं है।

श्री मंगल सैन : अभी मंत्री महोदय ने बताया है कि ग्रामीण अंचलों में मकान बनाने के लिए अढ़ाई करोड़ रुपए रखे गए हैं। क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि शहरों में जो गरीब लोग रहते हैं, उनको भी मकान बनाने के लिए कुछ राशि दी जाएगी?

श्री सुभाष चन्द कटियालः इस वक्त तो कोई विचार नही है।

श्री टेक चन्दः अभी मन्त्री महोदय ने बताया है कि किसी पिछली सरकार की जो स्कीम थी उसके तहत 3033 मकान बनाए गए थे और उनमें से सिर्फ 970 मकानों के आसपास ही लोगों ने लिए और साथ यह भी कहा है कि वह स्कीम ठीक नहीं थी। मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि मौजूदा सरकार ने इस स्कीम में क्या अमैडमैंट की है?

श्री सुभाष चन्द कटियालः मौजूदा सरकार का यह फैसला है कि सरकार मकान बनाने की बजाए लोगों को लोन दे ताकि वे अ पनी सुविधानुसार मकान बना सकें।

श्री परमानन्दः स्पीकर साहब मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जो लोग शहरों के रहने वाले हैं और गरीब लोग हैं, जिनके पास कोई भी प्लाट नहीं है, क्या इन्हें भी कोई प्लाट देने पर विचार करेंगे?

श्री सुभाष चन्द कटियालः आपकी बात पर विचार कर लेंगे।

सिंचाई तथा बिजली मन्त्री (श्री वीरेन्द्र सिंह): स्पीकर साहब, गांवों में हाउसिंग बोर्ड ने मकान बनाने की योजना बीस सूत्री प्रोग्राम के तहत शुरू की थी। यह स्कीम केवल गांवों के लिए है। यह पैसा सैन्टर से आता है। सरकार ने यह सुविधा दी कि वे मकान खुद बना लें क्योंकि पहले हाउसिंग बोर्ड खुद मकान बना कर देता था। अभी सतबीर सिंह कादियान ने कहा कि मकान बने पड़े हैं लेकिन लोग लेने के लिए तैयार नहीं हैं। अब मौजूदा सरकार ने फैसला किया है कि मकान हाउसिंग बोर्ड नहीं बनाएगा, वह लोन देगा। लोगों को यह सुविधा दी जाएगी कि लोन ले लें और अपना मकान खुद वना लें।

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, मन्त्री महोदय ने बताया कि हाउसिग बोर्ड गांवों मे मकान बनाने के लिए लोन देगा और

लोन उसको दिया जाएगा जिसके पास जमीन है। इसलिए क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि कम से कम कितना लोन दिया जाएगा और अधिक से अधिक कितना दिया जाएगा?

श्री सुभाष चन्द कटियालः पांच हजार रुपए लोन दिया जाएगा और अगर कोई कम लेना चाहे तो उस पर सोचा जा सकता है। हरिजनों के लिए दो हजार सबसिडी भी है।

श्री जगन नाथः स्पीकर साहब यह पैसा तो सैन्टर से आया है लेकिन जमीन अपने प्रान्त की है। हाउसिंग बोर्ड ने छोटे–छोटे मकान बनाए हैं। मेरे हल्के में जाटां लुहारी, रतेरा और बडवा वगैरह गांवों में मकान बनाए गए हैं लेकिन उन मकानों को लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। वे सारे टूटे–फूटे पडे हैं।

Construction of Metalled Road in Rural Areas by Haryana Agricultural Marketing Board

***336. Shri Tek Chand Nain :** Will the Minister of State for Agriculture be pleased to state—

(a) the total amount earmarked by the Haryana Agricultural Marketing Board for the construction of metalled roads in rural areas during the year 1987-88; and

(b) whether any change has been made in the policy of construction of roads in rural areas by the said Board in the recent past; if so, the details thereof ?

Interim Reply

Mr. Speaker : Extension has been demanded in respect of this question, which has been graved. The communication received from the Minister concerned in this connection reads as under :—

तत्काल

विधान सभा कार्य

विषय –विधान सभा तारांकित प्रश्न सं० 336 जो श्री टेक चन्द नैन, विधायक, द्वारा पूछा गया है, के बारे में उत्तर देने बारे।

हरियाणा विधान सभा तारांकित प्रश्न संख्या 336 जो कि श्री टेक चन्द्र नैन, विधायक द्वारा पूछा गया है, का उत्तर दिनांक 16–3–88 को हरियाणा विधान सभा अधिवेशन में देय है किन्तु वांछित उत्तर बारे पूर्ण सूचना प्राप्त न होने के कारण उत्तर तैयार नहीं है। अतः उनसे अनुरोध है कि इस प्रश्न का उत्तर तैयार करने हेतु रूल्ज आफ प्रोसीजर एण्ड कण्डक्ट आफ बिजनैस इन दी हरियाणा विधान सभा के नियम 41 के परंतुक (2)के अनुसार कम से कम एक सप्ताह की बढ़ौतरी दे।

हस्ता०

राज्य मन्त्री, कृषि

हरियाणा।

सेवा में,

अध्यक्ष,

हरियाणा विधान सभा

चण्डीगढ़।

अशः० क्रमांक 802—कृ०अ० (1)ऐ—88/ 818 चण्डीगढ़, दिनांक 15—3—88

Primary, High Schools and 10+2 system Schools in the State

***397. Shri Jai Narain Khundia : Will** the Minister for Education be pleased to state—

(a) the District-wise total number of Primary schools, High schools and 10+2 system schools, separately, in the State at present;

(b) the number of schools, out of those as referred to in part(a) above, proposed to be upgraded from Primary to Middle and Middle to High Schools during the year 1988-89; and

(c) the criteria adopted for upgrading High Schools to 10+2 system schools ?

शिक्षा मंत्री (श्री खुरशीद अहमद):

(क)प्राथमिक, उच्च तथा 10+ 2 शिक्षा प्रणाली के विद्यालयों की पृथक–पृथक जिलावार संख्या बारे सूचना 30–9–87 की स्थिति अनुसार सदन के पटल पर अनुबन्ध–ए में रखी जाती पैं।

(ख)वर्ष 1988–89 के दौरान किसी प्राईमरी विद्यालय को माध्यमिक तथा माध्यमिक विद्यालय को उच्च स्तरोन्नत करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग)उच्च विद्यालय के स्तर को 10 + 2 शिक्षा प्रणाली हेतु बढ़ाने बारे माप–दण्ड अनुबन्ध बी में दिया नया है।

अनुबन्ध–ए

जिला	प्राथमिक स्कूल	उच्च स्कूल	10 + 2 शिक्षा प्रणाली स्कूल
अम्बाला	741+ 7*	212	19+ 5*
भिवानी	349	143	16+ 1*
फरीदाबाद	364	138	15+ 12*
गुडगांव	599	114+ 1*	12+ 1*
हिसार	334	230	17+ 1*
जींद	287	132	13

करनाल	468	167	17+ 1*
कुरुक्षेत्र	579	142	11+ 1*
महेन्द्रगढ़	563+ 1*	149	11+ 1*
रोहतक	275	236+1*	18+ 2*
सिरसा	271	90	9
सोनीपत	210	142	12+ 2*
योगः	5040+8*	1895+ 2*	170+ 27*

अनुबन्ध बी

राजकीय उच्च विद्यालय को सीनियर सैकेण्डरी स्कूल बनाने का माप–दण्ड

1. केवल ऐसे राजकीय हाई स्कूलों को ही अपग्रेड, करने पर विचार किया जा सकता है, जिनमें पर्याप्त भवन, फर्नीचर, खेल का सामान, विज्ञान प्रयोगशाला इत्यादि की सुविधा उपलब्ध हौं।

2. जमा 2 स्तर की कक्षाओं के लिए पर्याप्त संख्या में विद्यार्थी उपलब्ध हों। इसके लिए जिस स्कूल को अपग्रेड किया जाए, उसके आसपास के उच्च विद्यालयों की छात्र संख्या को देखकर ही अपग्रेड करने बारे विचार करना होगा।

3 नगरों और शहरी क्षेत्रों मे राजकीय हाई स्कूल को अपग्रेड न किया जाए, विशेषकर जहां पहले ही कालेज अथवा सीनियर सैकेण्डरी स्कूल हों।

4. जमा 2 स्तर की शिक्षा में किसी प्रकार की यदि असमानता हो तो उसे दूर किए जाने का प्रयास किया जाए।

5. मान्यता प्राप्त हाई स्कूलों को अपग्रेड करने के लिए अब ऐसी नीति हो जिसके अधीन केवल ऐसे स्कूल ही अपग्रेड करने बारे विचारा जाएं, जिन की मैनेजमैंट यह आश्वासन दे कि वे अप ग्रेडेशन के फलस्वरूप राज्य सरकार से वित्तीय सहायता की मांग नहीं करेंगे और जमा 2 स्तर पर दाखिल होने वाले विद्यार्थियों को सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करेंगे। साथ ही सुयोग्य टीचिंग स्टाफ भी सुनिश्चित किया जाएगा।

श्री जयनारायण खुडिया: स्पीकर साहब, मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि यह जो 10 + 2 की प्रणाली सरकार ने लाए की है, इसके मुताबिक रोहतक जिले में कितने स्कूलों को अपग्रेड करने का प्रावधान गै और मेरे हल्के कलानोर में कितने स्कूल अपग्रेड किए जाएंगे?

श्री खुर्शीद अहमद: इस साल कोई अपग्रेड नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष: अब क्वैश्चन आवर खत्म होता है।

नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारॉंकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Textile Mills Hissar

***265. Shri Hari Singh and Shri Harnam Singh :** Will the Minister for Industries be pleased to state—

(a) whether the Government is aware of the fact that the Textile Mills Hissar is lying closed as at present; and

(b) if so, the steps, if any, taken or proposed to be taken by the Government to re-start the said Mills ?

उद्योग मन्त्री (डा० किरपा राम पुनिया):

(क)हां जी।

(ख)केन्द्रीय सरकार को इस इकाई के राष्ट्रीयकरण के लिए निवेदन कर दिया गया है। हरियाणा सरकार ने एक समिति का गठन किया है जो कि टैक्सटाईल उपक्रमों के पुनर्जीवित करने की संभावनाओं बारे अन्वेषण, जांच तथा प्रस्तावना करेगी। हिसार टैक्सटाईल मिल भी इस समिति के कार्यक्षेत्र में आता है।

Setting up of a Spinning Mill at Asha Khera

***309. Shri Mani Ram :** Will the Minister of State for Cooperation be pleased to state—

(a) whether there was any scheme under the consideration of the Government to set up a Spinning Mill at Asha Khera in district Sirsa during the year 1978-79; if so,

whether the said scheme is still under consideration of the Government; and

(b) if the reply to part (a) above be in the affirmative, the time by which the said Mill is likely to be set up ?

सहकारिता राज्य मन्त्री (डा० रघुवीर सिंह):

(क)हां, आशा खेड़ा जिला सिरसा में एक कताई मिल वर्ष 1978–79 में स्थापित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन था। अब सरकार के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख)उपरोक्त क में दिए गए उत्तर को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, मैंने आज रूल 84 के तहत एक मोशन का नोटिस दिया था।

श्री अध्यक्ष: वह मुझे मिल गया है और मैं उसको स्टडी कर रहा हूं।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव–

जिला सोनीपत में ओलावृष्टि से नष्ट हुई रबी फसल संबंधी

श्री अध्यक्ष: आनरैबल मैम्बरज, मुझे श्री देवी दास और डा० महा सिंह, विधायकों की ओर से डैमेज आफ रबी क्रौप बाई हेल स्टोर्म इन सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के बारे में काल अटैन्शन

मोशन्ज नं० 1 और 2 के नोटिस मिले हैं। मैं इन्हें ऐडमिट करता हूं। श्री देवी दास जी अपना मोशन पढ़ें और उसके बाद यदि मन्त्री महोदय जवाब आज देना चाहें तो दे दें।

श्री देवी दासः अध्यक्ष महोदय, मैं इस महान सदन का ध्यान एक अत्यावश्यक लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं कि जिला सोनीपत में कल दिनांक 12–3– 1988 को भारी ओलावृष्टि से रबी की गेहूं, चना, सरसों और सब्जियां तथा हरे चारे की फसल को हानि हुई है। इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए जा रहे पगों से इस महान सदन को सूचित किया जाए।

श्री महा सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं इस महान सदन का ध्यान एक अत्यावश्यक लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं कि जिला सोनीपत में जो भारी ओलावृष्टि हुई है, उस के कारण करोड़ों रुपए की हानि हुई है। इसलिए मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि सरकार किसानों को शीघ्र राहत दे।

राजस्व मन्त्री (श्री सूरज भान): अध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों ओलावृष्टि के कारण सोनीपत, कुरुक्षेत्र, अम्बाला तथा महेन्द्रगढ़ जिलों में फसलों को बहुत भारी नुकसान हुआ है। आदरणीय मुख्य मन्त्री जी कल सोनीपत जिले में फसलों की हालत देखने के लिए गए थे और आज वे महेन्द्रगढ़ जिले में गए हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि मुख्य मन्त्री जी जब वापिस आ जाएंगे

और अपना इम्प्रैशन हमें बता देंगे तो इस का जवाब हम सोमवार को दे देंगे।

नियम 121 के अधीन प्रस्ताव

समितियों के गठन संबंधी नियमों का निलम्बन

श्री अध्यक्ष: अब पार्लियामैंटरी अफेयर्ज मिनिस्टर रूल 121 के तहत प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

Irrigation and Power Minister (Shri Verender Singh) : Speaker Sir, I beg to move—

That the provisions of Rules 228, 230, 230B and 260A of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly in-so-far as they relate to the constitution of the-

(i) Committee on Public Accounts;

(ii) Committee on Estimates;

(iii) Committee on Public Undertakings; and

(iv) Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes,

for the year 1988-89 be suspended.

Sir, I also move—

That this House authorises the Speaker, Haryana Vidhan Sabha, to nominate the Members of the aforesaid Committee for the year 1988-89, keeping in view the

proportionate strength of various parties/groups in the House.

Mr. Speaker : Motion moved-

That the Provisions of Rules 228, 230, 230B and 260A of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly in-so-far as they relate to the constitution of the-

(i) Committee on Public Accounts;
(ii) Committee on Estimates;
(iii) Committee on Public Undertakings; and

(iv) Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes, for the year 1988-89 be suspended.

That this House authorises the Speaker, Haryana Vidhan Sabha. to nominate the Members of the the aforesaid; Committees for the Year 1988-89, keeping in view the proportionate strength of various parties/ (groups in the House.

श्री मंगल सैन(रोंहतक): स्पीकर साहब, मैं मन्त्री महोदय की बात समझ नहीं पाया। आपने एक सर्कुलर जारी किया हुआ है कि नौमिनेशन दि जाएं और इधर से यह मोशन आया है।

श्री अध्यक्ष: यह हाउस के सामने आया है।

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, यह मोशन इस लिए मूव किया गया है क्योंकि यह जो इलैक्शन का प्रोसीजर है जैसे नौमिनेशन, स्क्रूटनी, विदड्राल और फिर इलैक्शन उस में काफी

टाईम लग जाता है। एक कमेटी में जहां 9 सदस्य बनने चाहिएं उसके लिए 40–50 नौमिनेशन आ जाती थीं। पिर सैशन के टाईम में वेरियस ग्रुप्स के लीडर्ज उनकी छंटनी करते थे। इतना टाईम नहीं होता था कि मैम्बर्ज से सही ढंग से विदड्राल करवा ली जाए। कई बार ऐसी भी गड़बड़ हो जाती थी कि इलैक्शन का पूरा प्रोसैस हो जाता था। हमारे बीच में कांग्रेस के पांच भाई बैठे हैं। अगर इलैक्शन का प्रोसैस अपनाया जाए तो इनकी स्ट्रैगथ के हिसाब से इनका एक भी मैम्बर इलैक्ट नही हौ सकता। हम नही चाहते कि किसी कमेटी में कोई पार्टी अन–रिप्रेजैन्टिड रह जाए। इसलिए यह मोशन लाया गया है। स्पीकर साहब, आप इस हाउस मे सबसे इम्पार्शल व्यक्ति हैं, इसलिए हम आपको अथोराईज कर रहे हैं जि वेरियस ग्रुप्स के लोगों की स्ट्रैंगथ के हिसाब से आप मैम्बर्ज को कमेटियों मे नौमिनेट कर दें। इस मन्शा से हम ने यह मोशन मूव किया है।

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, मैंने इस बात को कन्टैस्ट नहीं करना है कि आपको अथोराईज क्यों किया जा रन है, आप तो इस हाऊस के क्स्टोडियन हैं। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हू। कि यह रौंग प्रोसीजर हैं। इतनी देर से इलैक्शन का प्रैसिडैन्ट चला आ रहा है। अगर ऐसा करेंगे तो यह अनडैमोक्रेटिक प्रोसैस हो जाएगा। बाकी आप देख लीजिए।

श्री हीरा नन्द आर्य (लोहारू): अध्यक्ष महोदय, जैसे डाक्टर साहब ने कहा, हमें आपकी इम्पार्शलिटी पर सन्देह नहीं है।

लेकिन हम इलैक्शन वाली बात को कई सालों से देख रहे है लेकिन काग्रेस के मिस–रूल में भी कभी इस प्रकार का काम नहीं हुआ है। जो प्रोविजन रूल में कर रखा है आप उसके मुताबिक चलें वरना उन रूल्ज को सक्रैप कर दें। यह अच्छी परम्परा नही है। मेरी प्रार्थना है कि इस मोशन को विदड्रा कर लिया जाए।

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, बड़े अफसोस के साथ कहना पड रहा है कि इतने पुराने और सीनियर मैम्बर्ज भी सरकार की भावना कों नहीं समझ सके। मैंने कहा है कि अगर इलैक्शन करवाए जाएं तो कांग्रेस का एक भी मैम्बर किसी कमेटी में इलैक्ट नहीं हो सकता। हम यह चाहते हैं किं कमेटियों में कांग्रेस और दूसरे ग्रुप्स के भी मैम्बर्ज हो। इस लिए हम आपको यह अख्तियार दे रहै हैं।

Mr. Speaker : Question is-

That the provisions of Rule 228, 230, 230B and 260A of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly in-so-far as they relate to the constitution of the-

(i) Committee on Public Accounts;

(ii) Committee on Estimates;

(iii) Committee on Public Undertakings; and

(iv) Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes,

for the year 1988-89 be suspended.

That, this House authorises the Speaker, Haryana Vidhan Sabha, tc nominate the Members of the aforesaid Committees for the year 1988-89, keeping in view the proportionate strength of various parties/groups in the House.

The motion was carried

राज्यपाल के अभि भाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)

श्री अध्यक्षः अब गवर्नर ऐड्रैस पर डिस्कशन रिज्यूम की जाती है।

श्री जगपाल सिंह चौधरी (नारायणगढ़): स्पीकर साहब, मैं गवर्नर ऐड्रैस पर धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस ऐडैरस का पैरा नम्बर 7 ड्राउट के बारे में है। हमारी कालका तहसील का क्षेत्र पंजाब के साथ लगता है। पंजाब में डेरा बसी के इलाके में सूखा राहत के लिए 733 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मिल रहे हें लेकिन हरियाणा में नहीं मिल रहे है। इस– लिए मेरी दरखास्त है कि हरियाणा में भी ऐसी राहत देने की कोशिश की जाए ताकि हमारे इलाके के लोग यह महसूस न करें कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है। पैरा नं० 11 इरीगेशन एण्ड पावर सैक्टर के बारे में है। इस में रावी ब्यास के बारे में जिक्र आया है। मेरे क्षेत्र में सडौरा तथा छछरोली के क्षेत्र ऐसे हैं जो सब– माऊंटेनियस हैं। इन की इरीगेशन के लिए हथनी कुण्ड बैरेज की स्कीम थी जो कि काफी आगे बढ़ चुकी है। मेरा निवेदन

है कि इस स्कीम को जल्दी कम्पलीट कर दिया जाए।. अगर ऐसा हो जाता है तो हमारे इलाके को भी नहरी पानी से फायदा मिल सकता है। जब तक यह स्कीम पूरी नहीं हो जाती तब तक छोटे–छोटे डैम बना दिए जाए जैसे कि टांगरी में एक प्रोपोजल है और जिस का चार करोड़ रुपए का एस्टिमेट बना हुआ है। उसके बाद हथनी कुण्ड बैराज को भी ऐक्सपी– डाईट किया जाए।

जहां तक पैरा नं० 12 का संबंध है, इसमें नहरों द्वारा पौंडों को और जोहड़ों को भरने के इन्तजाम के बारे में जिक्र किया गया है 1 मेरा अम्बाला जिला है! इसमें सिर्फ ट्यूबवैल्ज ही हैं, नहरे नहीं हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना यह है कि एम०आई०टी०आई० को यह हिदायत की जाए कि वह ट्यूबवैल्ज से हमारे क्षेत्र में पींडज को और जोहड़ों को भरे। आगे पैरा नं० 13 है। यह पावर की बाबत है। शहजादपुर में 33 के०वी० स्टेशन मंजूर हो चुका है लेकिन एक साल से वहां पर काम शुरू नहीं हुआ है। मैं यह चाहूंगा कि इस को जल्दी बनाने की ओर ध्यान दिया जाए। इससे आगे पैरा नं० 15 है। यह ऐग्रीकल्चर की बाबत है। इस दफा खरपतवार दवाई की बाबत काफी दिक्कत हुई थी। मेरा कहना यह है कि इसके लिए अभी से टैंडर काल कर लिए जाएं ताकि मौके पर लोगों को यह दवाई मिल सके। जहां तक 18 नं० पैरे का ताल्लुक है, यह ऐनीमल हस्वैडंरी के बारे में है। हमारे इलाके में चौधरी लाल सिंह ने बहुत पत्थर लगा रखे हैं कि यहां पर बैटर्नरी हस्पताल बनेंगे। मुझे उम्मीद शै कि सरकार इस बात

का भी ध्यान रखेगी कि वहां पर भी कुछ इस तरह की सुविधा दी जाए और जल्दी ही वहां पर भी अस्पताल बनना शुरू हो जाएगा। इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बाबत पैरा नं०21 है। इसमें नारायणगढ़, छछरौली या अम्बाला क्षेत्र में कोई भी बड़ा उद्योग नही है जैसे और दूसरी जगहों पर हैं। एक तो जैसे शूगर मिल का जिक्र आया था वह वहां पर बन सकती है। दूसरे वहां पर मोरनी हिल्ज में छेरने में जो मिन्नी स्टील प्लांट लग रहा है, वह वहां पर न होकर अगर नारायणगढ़ में लग जाए तो इससे एक तो ट्रकों को जो हिल्ली एरिया में आने–जाने में दिक्कत होती है, वह नहीं होगी, दूसरे हमारे इलाके की तरक्की हो जाएगी। यहां पर जी०सी०डब्ल्यू० है। मल्ले की क्वैरी से जो स्टोन यहां पर आता है, उसके लिए सूरजपुर में एक फैक्ट्री लगी हुई है। ऐसा करने से दोनों ही क्षेत्रों यानी मोरनी हिल्ज और नारायणगढ़ के क्षेत्रों को फायदा हो जाएगा और इकौनोमीकली और हर तरीके से यह ठीक रहेगा। इस तरह से उद्योग के मामले में भी इस इलाके को काफी फायदा हो जाएगा। पैरा नं० 28 रोजगार की बाबत है। ऐम्पलायमैंट की हालत काफी खराब है। जो अनऐम्पलायमैट अलाउन्स देने की तजवीज थी, जब स्टेट की फाइनैशीयल पोजीशन कुछ ठीक हो जाए तो वह सिरे चढ़ा दी जाए और यह अलाउन्स दे दिया जाए। पैरा नं० 29 के बारे में मेरा यह कहना यह है कि पिछले सत्र में एक जे०बी०टी० स्कूल नारायणगढ़ क्षेत्र के लिए मंजूर किया गया था। अभी तक वह वहां पर खुला नहीं है। मैं ऐजूकेशन मिनिस्टर महोदय से यह दरख्वास्त करूंगा कि

उसको वह एक्सपीडाईट करवाएं। पैरा नं० 30 के बारे में मेरा निवेदन यह है कि नवोदय विद्यालय खोलने की जो स्कीम है, उसके अन्तर्गत अम्बाला जिले में नारायणगढ़ या सढौरा क्षेत्र में कही पर यह विद्यालय खोल दिया जाए क्योंकि कालका, अम्बाला और यमुना नगर में पहले ही काफी स्कूल हैं। मेरा कहना यह है कि नारायणगढ़ जोकि एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, यहां पर यह स्कूल खोल दिया जाए। इसके लिए हमने 30 एकड़ जमीन औफर भी की है। इसी तरह से पैरा नं० 36 के बारे में भी मैं कुछ कहना चाहता हूं। सारा ही अम्बाला डिस्ट्रिक्ट सब–माउनटेनियस एरिया है। इसमें नदियां नाले बहुत ज्यादा हैं। थोड़े से नाले के एरिया को क्रौस करने के लिए हमें 20– 20 किलोमीटर का चक्कर लगाकर जाना पड़ता है। यह जो मिनी बसें हैं, यह ऐसे क्षेत्रों के लिए हैं जहां पर नदियां नाले हों और उनको यह आसानी से कोस कर सकती हैं। मेरा कहना यह है कि जो मिनी बसिज खरीदी जा रही हैं, उनमें से ज्यादा से ज्यादा इस क्षेत्र को दी जाएं ताकि लोगों को सुविधा हो सके। इस इलाके की पैकुलीयर सिचुएशन है। सब–माउनटेनियस एरिया में नदियां और नालें काफी हैं। ऐसा करने से लोगों को ज्यादा सुविधा मिल सकेगी। पैरा नं० 38 टूरिस्ट काम्पलैक्सिज के बारे में है। चण्डीगढ़ से लेकर यमुना नगर तक अभी तक एक भी टूरिस्ट काम्पलैक्स नहीं है। नारायणगढ सब–डिवीजनल हैडक्यार्टर भी है। नारायणगढ़ में जो मंत्रीगण या अफसर जाते हैं, उनको खाने की काफी दिक्कत होती है। अगर वहां पर भी एक टूरिस्ट काम्पलैक्स खोल दिया जाए तो

जो वहां पर जाएंगे एक तो उनको सुविधा होगी दूसरे आपकी बड़ी कृपा होगी। पैरा 43 मोरनी हिल्ज डिवैल्पमैंट के बारे में है। कल भी मैंने जिक्र किया था। मन्त्री श्री भारद्वाज जी ने यह कहा है कि हम डायरैक्टरी विलेजिज को कवर कर रहे हैं।

मोरनी हिल्ज की खास सिचुएशन है। यहां पर एक गौज होता है जिसमें पन्द्रह गांव होते हैं। रैवेन्यू डायरैक्टरी में एक गांव है लेकिन गौज में पन्द्रह या उससे भी ज्यादा गांव होते हैं। इस तरह मे गौज में तकरीबन सात सौ गांव हैं जिनके नाम रैवेन्यू डायरैक्टरी में नहीं हैं। इन गांवों की थोड़ी–थोड़ी आबादी है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि इनको भी लिया जाए। केवल डायरेक्टरी विलेजिज कों ही न लिया जाए। पहाड़ी क्षेत्र में ऐसा नहीं चल सकता। आखिरी आइटम कर्मचारियों के बारे में है। यह बहुत अच्छी बात है कि सरकार ने फोर्थ पे कमिशन की रिकमैन्डेशंज को स्वीकार कर लिया है लेकिन अभी तक पैन्शनर्ज को कुछ नहीं दिया गया है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि पे–कमिशन की रिकमैन्डेशज पैन्शनर्ज पर भी लागू की जाए।

श्री रणजीत सिंह (रोडी): स्पीकर साहब, डा० साहब ने गवर्नर महोदय के अभिभाषण पर मोशन आफ थैंक्स का प्रस्ताव मूव किया था, मैं उसके समर्थ न के लिए खड़ा हुआ हू। यह सरकार बनने के बाद यह पहला बजट सैशन है। गवर्नर महोदय के इस अभिभाषण में इस सरकार की पिछले आठ नौ महीने की कार्यवाही को दर्शाया गया है, सरकार द्वारा की गई कारगुजारी को

हाड–लाइट किया गया शै। कुल भीं बहुत से आनरेबल मैम्बर्ज ने बातें की थी और बताया था कि पिछले आठ नौ महीने में गवर्नमैंट की क्या अचीवमैट्स रही हैं। मैं उन सारी बातों में न जाकर कुछ बातों पर ही चर्चा करूंगा। कल यहां पर ओल्ड एज पैन्शन की बात की गई। मैं कहना चाहता हूं कि देश में यह पहली सरकार है जिसने ओल्ड एज पैन्शन सभी बूढ़ों को दी है। सूखा राहत के क्षेत्र में भी इस सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। कल तैयब हुसैन जिक्र कर रहे थे कि सरकार ने पैसा कम मांगा और सरकार को मांगना नहीं आया। स्पीकर साहब, 37 करोड़ रुपए से इस सरकार ने सूखा राहत में जितना अच्छा काम किया है, लोगों की आवश्यक्ताओं को इस 37 करोड़ रुपए से मीट आउट किया है देश के अन्दर किसी भी सरकार ने बहुत ज्यादा पैसा लेकर भी नहीं किया। मैं तैयब हुसैन को बताना चाहता हूं कि जिस सरकार को 37 करोड़ रुपए से इतना अच्छा काम करना आताहै उसको पैसा मांगना भी आता है।

जहां तक फोर्थ पे कमिशन की रिकमैन्डेशंज को लागू करने की बात है, मैं यह कहना चाहता हूं कि देश के अन्दर हरियाणा सरकार पहली सरकार थी जिसने फोर्थ पे कमिशन की रिकमैन्डेशज को लागू किया है। स्पीकर साहब, इस सरकार ने एक और अच्छा काम किया है कि जो लडके इंटरव्यू के लिए जाते हैं उनके लिए फ्री बस पास जारी किए हैं.। देश के अन्दर यह पहली सरकार है जिसने यह काम किया है। इससे बेरोजगार लड़कों को

बहुत फायदा दरोगा। स्पीकर साहब, चुनाव घोषणापत्र के अन्दर जो कुछ शी लिखा गया था इस सरकार ने बनने के सात आठ महीने के अन्दर ही सत्तर–अस्सी परसैटं वायदे पूरे कर दिए हैं और मैं समझता हूं कि सरकार जिस मुस्तैदी से काम कर रही है मुझे आशा है कि बाकी जो बीस परसैटं वायदे रह गए हैं अगले साल तक वे भी पूरे हो जाएंगे। इस तरह से इलैक्शन मैनीफैस्टो में किए गए वायदे अगले साल तक पूरे कर दिए जाएंगे।

स्पीकर साहब, इसके बाद पानी और बिजली के बारे में चर्चा की गई है। बहुत से सदस्यों ने इन दोनों चीजों की काफी चर्चा की है और मैं भी यह समझता हूं कि हर प्रदेश के लिए पानी और बिजली का बहुत महत्व है और खासकर हरियाणा के लिए तो इन दोनों चीजों का बहुत ही महत्व है। स्पीकर साहब, मैं पानी के बारे में कहूंगा कि इस सरकार ने पानी के लिए बहुत प्रयास किया है और कर रही है। यह सरकार संघर्ष से, आन्दोलन से बनी है और मैं कह सकता हूं कि यह पहली सरकार है जो आर्थिक मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ी और जीतकर आई। मुख्य मन्त्री महोदय पानी के मामले में खास दिलचस्पी ले रहे हैं। वे एस०वाई०एल० पर हो रही प्रगति को खुद देखने गए। चौधरी वीरेन्द्र सिंह और श्री बनारसी दास गुप्ता भी एस०वाई०एल० को देखने गए। इससे पता लगता है कि हमारे कैबिनिट मिनिस्टर एस०वाई०एल० पर हो रहे काम के बारे में कितनी दिलचस्पी ले रहे हैं और वे कितने चिन्तित हैं। चौधरी बंसी लाल और चौधरी भजन लाल ने कभी

एस०वाई०एल० को विजिट नहीं किया और न कभी सैन्टर से इस मामले को टेक–अप किया। इस सरकार ने पानी के लिए इतना बड़ा लम्बा संघर्ष किया और जब भी पानी के लिए जरुरत पड़ी, सैन्टर के साथ संघर्ष किया। एस०वाई०एल० का विजिट किया। लेकिन जो पिछली सरकारें थीं, उस समय लोग सड्कों पर खड़े गोलियां खा रहे थे, उसके नेता लोग दिल्ली में बैठकर दस्तखत कर रहे थे, हरियाणा बेच रहे थे और तैयब साहब तावडू के पहाड़ों पर खड़े गोलियां चला रहे थे। आज वें लोग यह कह रहे हैं कि इस सरकार ने कुछ नहीं किया। हम इस सरकार से मांग कर रहे हैं लेकिन इस सरकार ने कुछ नहीं किया। मैं तैयब हुसैन से यह कहूंगा। (शोर एवं व्यवधान)

चौधरी तैयब हुसैनः स्पीकर साहब, ये गोलियां चलाने वाली बात किस सिलसिला में कह रहे हैं? एक आनरेबल मैम्बर के बारे में ऐसी बातें कहना इनको शोभा नहीं देता। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणजीत सिंहः स्पीकर साहब, बिछल गोलियां चलाते थे यह तो रिकार्ड की बात है।

पशु पालन राज्य मन्त्री (श्री अजमत खां): स्पीकर साहब, क्या फिरोजपुर झिरका के अन्दर गोलियां नहीं चलीं? क्या वहां का सरपंच बेकसूर नहीं मारा गया? क्या हजारों बेकसूर लोगों के हाथ पांव नहीं तोड़े गए? (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणजीत सिंहः तो स्पीकर साहब, मैं यह कहना चाहता हूं कि पानी के बारे में दिल्ली में एक मीटिंग हुई थी उसमें हरियाणा की ओर से चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी उस मीटिग में हरियाणा के केस को प्लीड करने के लिए गए थे। उस कमेटी के चेयरमैन श्री साठे केन्द्रीय मन्त्री थे। श्री वीरेन्द्र सिंह जी ने कहा कि सब से पहले लोगों को बिजली और पानी दो बातें मुहैया करो। अगर लोगों को पूरा पानी व पूरी बिजली मुहैया की जाएगी तो मैं समझता हूं कि 80 प्रतिशत डिवैल्पमैंट होगी। साथ में श्री वीरेन्द्र सिंह जी ने यह कहा कि बाकी के सब मुद्दे छोड़ दो। इन्हीं दो बातों पर जोर दिया जाना चाहिए। श्री साठे जोकि उस कमेटी के चेयरमैन थे, उन्होंने कहा कि वीरेन्द्र जी ने जो सुझाव दिए हैं वे बहुत ही बेहतरीन हैं और इस तरह के सुझाव आज तक पहली बार ही किसी मन्दी ने दिए होंगे। इतना फोरसीबली किसी केस को किसी मन्त्री ने पहली बार ही प्लीड किया होगा जैसा कि इन्होंने किया। स्पीकर साहब, यह रिकार्ड की बात है। मेरा कहने का मतलब यह है कि सरकार ने इन्हीं सब बातों को मद्देनजर रखते हुए किसानों को आवश्यकता के अनुसार बिजली और पानी मुहैया किया है और आज बिजली 24 घण्टे मिलती है। तैयब साहब को शायद इस बात का पता नहीं। उनको चाहिए कि वे महेन्द्रगढ़ और कुरुक्षेत्र में जाकर देखें जहां कभी फसलें हुआ नहीं करती थीं वहां आज सरकार ने जितनी बिजली मुहैया की एं जिस कारण से वहां पर लोगों में खुशहाली आयी है। जो जरुरत की चीजें पहले लोगों को नहीं मिल पा रही थीं, वे आज मिल रही हैं।

इसके साथ साथ मैं इंडस्ट्रीज के मुताल्लिक कुछ सुझाव देना चाहता हूं। किसी प्रदेश का रैवेन्यू का बड़ा भाग इडस्ट्रीज से आया करता है। मिनिस्टर महोदय ने बताया कि हमारा बजट 1500 करोड़ का है। मैं बताना चाहता हूं कि जितना बजट आया है उसमें इंडस्ट्रीज डिपार्टमैंट कितना दे रहा है। अकेला मारुति उद्योग ही 70 करोड़ रुपया दे रहा है। ऐसी ही दूसरी इंडस्ट्रीज हैं वे भी काफी पैसा दे रही हैं। इंडस्ट्रीज जितनी अच्छे ढंग से चलेंगी उतना ही अधिक रैवेन्यू स्टेट को आएगा। मैं समझता हू कि खेती में इतना पैसा नहीं। ऐग्रीकल्चर सैक्टर में तो हम पहले से लग रहे हैं और बहुत जोर से लग रहे हैं। अगर हरियाणा के अन्दर पानी और बिजली पूरी मात्रा में मुहैया होगी तो फिर हरियाणा के फार्मर्ज को कोई दिक्कत नहीं होगी। हरियाणा के फार्मर्ज के पास लेटैस्ट टैक्नीक है। वे सब समझते हैं कि किस ढंग से खेती की जाए।

स्पीकर साहब, इंडस्ट्रीज के मुताल्लिक मैं आपको बताता हूं। फरीदाबाद कभी नार्दर्न इंडिया में सब से बड़ा इंडस्ट्रियल टाउन हुआ करता था। कानपुर के बाद सब से बड़ा इंडस्ट्रियल टाउन फरीदाबाद ही था। पिछले दस सालों मे दो मुख्य मन्त्री चौधरी बंसी लाल और चौधरी भजन लाल थे तथा श्री तैयब हुसैन होम मिनिस्टर हुआ करते थे और हर महीने इंडस्ट्रीज में जाकर ये डेरे लगा लिया करते थे। रैस्ट हाउसिज और बड़खल में जाकर बैठा करते थे कि पैसा दो। कलकत्ता की फैक्ट्रीज से

बहुत पैसा लिया जाता था। कभी किसी नाम से और कभी किसी नाम से इंडस्ट्रीज से पैसा ऐंठा जाता था और हरियाणा की इंडस्ट्रीज की डिवैल्पमैंट की ओर कभी कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। इसी कारण से पिछले 9 सालों में जितना डाऊन ट्रेन्ड इंडस्ट्रीज में आया उतना कभी नही आया था। सारी इंडस्ट्रीज हरियाणा से चली गयीं। मैं नोयडा, जोकि एक बहुंत छोटा सा एरिया है और उत्तर प्रदेश के अन्दर है, के बारे में आपको बताना चाहता हूं। 1991 में, लगभग आज से तीन साल बाद वहां की इंडस्ट्रीज से जौ रैवेन्यू आएगा वह 2 हजार करोड़ के लगभग होगा और यह सारा पैसा उत्तर प्रदेश सरकार को जाएगा। उस एरिया की डिवैल्पमैंट वहां की सरकार कर रही है। लोगों को हर तरह से इसैनटिव दिया जा रहा है। वन विन्डो सर्विस है। अगर इंडस्ट्रीज वालों को लाईसैन्स मिल जाता है तो फायनैंशियल कारपोरेशन और इंडस्ट्रियल डिवैल्पमैंट कारपोरेशन जो उस स्टेट की हैं, वे भी उनसे सव प्रकार का सहयोग करता हैं जिससे लोगों को कोई विशेष दिक्कत नही होती है। इसलिए मेरा इंडस्ट्रीज मिनिस्टर को यी सुझाव है कि इंडस्ट्रीज लगाने के लिए लोगों को कोई नए इंसैनटिव्ज दिए जाएं और लोगों को बाहर से ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहां पर इंडस्ट्रीज लगाने के लिए बुलाया जाए। ज्योग्राफिकली हरियाणा दिल्ली के तीन तरफ बसा हुआ है और जो लोग बाहर से आएंगे वे नौन रैजीडैन्ट इंडियन होंगे तथा मैं नहीं समझता कि दे बड़ौदा, गुजरात, कानपुर, लखनऊ और अहमदाबाद जा करके इंडस्ट्रीज लगाएंगे। अगर हरियाणा सरकार

ठीक ढंग से उनको इसैंटिव दे, उन लोगों को बुला करके ठीक सर्विस दे तो बहुत बढ़िया काम होगा। चौधरी तैयब हुसैन मेरी तरफ देख रहे हैं इसलिए यह बात मैं उनको बता रहा हूं। चौधरी देवी लाल जी के साथ मुझे भी अमरीका जाने का मौका मिला था और हम न्यूयार्क में ठहरे थे। वहां पर इंडियन इनवैस्टमैंट सैंटर में जो इंडियनज थे उनको चौधरी साहब ने इनवाइट किया था कि आप हरियाणा में आओ और इंडस्ट्रीज लगाओ हम आपको सारी फैसि– लिटीज देंगे। उनमें से एक इंडस्ट्रीयलिस्ट कहने लगे कि चौधरी साहब हमें कह तो जाते हैं, चौधरी भजन लाल जी भी पहले दो बार अमरीका में आए थे और वह भी यही बात कह कर गए थे। लेकिन जब हम हरियाणा में इंडस्ट्रीज लगाने के लिए जाते हैं तो हमारे जूते लगते हैं। हमें वहां पर खड़ा ही नहीं होने दिया जाता। हम इंडस्ट्रीज मिनिस्टर के औफिस के आगे 6– 6 घंटे बैठे रहते हैं, कोई हमारी बात ही नहीं सुनता। जब हमारे साथ इस ढंग का व्यवहार होता है तो हम उस समय यह समझते हैं कि वापिस ही चलें। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। उन इंडस्ट्रीयलिस्टस में से एक कहने लगे कि एक मन्त्री थे उन्होंने मुझे कहा कि आप दो लाख रुपए यहां पर रख दें आपका काम अभी हो जाएगा। हमें तो वहां जाने पर इस बात का पता लगा कि वहां पर हमारे हरियाणा का नाम किस ढंग से लिया जा रहा है। मैं सरकार से कहूंगा कि इंडस्ट्रीज लगाने के लिए आप उन्हें इंसैटिव दें। जो बाहर के लोग हैं उन्हें बुलाए। हरियाणा दिल्ली के तीन तरफ है इसलिए सरकार को रैवेन्यू मिलने में बहुत मदद

मिलेगी। इसके अलावा मैं एस०वाई०एत० नहर का जिक्र करना चाहूंगा। जब मैं छोटा था उस समय यह बात सुनता था कि एस०वाई०एल० नहर के पानी में हरियाणा का इतना हिस्सा है। यह बहुत बड़ी नहर है, बहुत बड़ा प्रोजैक्ट है। इस नहर के साथ हरियाणा की सारी समृद्धि जुड़ी हुई है। आज साईंस और टैक्नोलाजी का जमाना है इस जमाने में यहां से सैटेलाइट द्वारा दुनिया के कम्युनिकेशन पर कंट्रोल है। आप यहां बैठे टैलीफोन घुमा लें, जर्मनी, जापान, आस्ट्रेलिया और कहीं पर भी घुमा लें पहले ही डायल में मिल जाएगा। डिफैस सिस्टम में आज जो एडवांस्ड कंट्रीज हैं जैसे अमरीका और रसिया उनके जो कंट्रोल रूर। हैं, जो अंडरग्राउंड बेसमैंट में बने हुए हैं उन्होंने उनको इस ढंग से डिवैल्प कर लिया है कि अगर पूरे वर्ल्ड में कहीं भी आर्मी की मूवमैंट होती है तो हर दो मिनट में स्क्रीन पर आ जाता है कि कहां पर कितने ग्रुप हैं और किस दिशा में जा रहे है और कौन सी कन्ट्री किस पर अटैक कर रही है। आज राकेट लौच करके 60 घंटे में आदमी चांद पर जा सकता है। इस जमाने में साईंस और टैक्नोलोजी इतनी एडवांस है। मैं समझता हूं कि नहर का पानी न तो लांच करके लाया जा सकता है और न ही जम्प करा करके लाया जा सकता है। पानी लाने का केवल यही तरीका है जो आज से एक हजार साल पहले था यानी नहर खोद कर ही पानी लाया जा सकता है। नहर खोदने के लिए हमारी सरकार ने, हमारे मुख्य मन्त्री जी ने, हमारी सारी कैबि– नेट ने, मैं तो यह कहूंगा कि हाउस के सारे मैम्बर्ज ने इस मुद्दे पर संघर्ष करके जनता के

सामने यह कहा था कि हमारे लिए पानी अहम है। इसलिए मैं यह कहूंगा कि सरकार का जोर इस बात पर लगना चाहिए कि एस०वाई०एल० नहर कम्पलीट हो। जिस तरह से दिल्ली में हमारी रैली हुई थी उसमें लोगों का यही ओपीनियन सरकार पर प्रैशर डालने के लिए था कि हम यहां पर पानी लेने के लिए आए है। इसलिए मैं तो यही समझता हूं कि हमारी सरकार को एस० वाई० एल० नहर को कम्पलीट करवाने के लिए जोर देना चाहिए। अब मैं इस सरकार के कार्यों की और उस सरकार के कार्यो की तुलना करना चाहता हूं कि क्या फर्क था। अध्यक्ष महोदय आपके बराबर में वी०आई० आईज० गैलरी है। इस गलरी में जितने आदमी बैठे हैं उनको देखने से पता लगता है कि ये सारे देहाती आदमी हैं और सारे वे आदमी हैं जिन्होने हमें चुनकर यहां भेजा है। सारे हरियाणा की झलक नजर आ रही है। जब पिछली सरकार थी उस समय आप देखते थे कि इस गैलरी में सप्लायर बैठा करते थे, या बीच के जो ब्रोकर हुआ करते थे, वे बैठा करते थे। वे कलकत्ता, अहमदाबाद या मद्रास को फर्म्ज हुआ करती थी और चौधरी भजन लाल जी उस समय यह तय किया करते थे कि उनसे क्या खरीदा जाए। मैं उस समय की परचेज कमेटी का जिक्र करना चाहूंगा। उस समय जो परचेज कमेटी हुआ करती थी, वह इसलिये हुआ करती थी कि स्टेट के लिए जो करोड़ो रुपए की खरीदो–फरोख्त हो उसकी परचेज कमेटी में चर्चा हो। उस कमेटी में चीफ मिनिस्टर चेयर करते थे और उसके अन्दर इंडस्ट्रीज मिनिस्टर, दूसरे कंसंर्ड मिनिस्टर और कंसर्न्ड सैक्रेटरीज हुआ करते थे। एक

बार पुलिस की युनिफार्म के लिये कपडा लिया जाना था। उस कमेटी में होम मिनिस्टर भी आ जाते हैं। मैं यह नहीं कहता कि उस समय तैयब साहब होम मिनिस्टर थे। ये दूसरी सरकार में होम मिनिस्टर होंगे मैं तो केवल होम मिनिस्टर कह रहा हूं, किसी का नाम नहीं ले रहा। जो कपड़ा लिया जाना था, उस समय सब ने अपना अपना कपड़ा निकाल कर दिखाया कि यह डी० सी० एम० का है, यह ग्वालियर सूटिंग का है। अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूं तो वह कपड़ा 87 लाख मीटर के लगभग खरीदा जाना था। जब कपड़ा लेने की बात आई तो कोई सैक्रेटरी कहने लगा कि साहब यह कपड़ा डी०सी०एम० का है ओर कोई कहने लगा कि साहब यह ग्वालियर सूटिंग का हे लेकिन चौधरी भजन लाल जी ने कपड़ा खींच लिया और कहने लगे कि कपड़े के बारे में मेरे से ज्यादा जानने वाला कौन होगा। वे कहने लगे कि सबसे बढ़िया कपड़ा यह है और उस समय 9 या 10 रुपए मीटर के हिसाब से भाव देना तय हुआ था। तो पहले वाली सरकार इस ढंग की थी। मैं यह नहीं कहता कि हम सारे ही देवता हैं। हम भी आदमी हैं। हम भी एम०एल०एज० हैं, हम भी जनता में से ही चुन कर आते हैं। लेकिन इस सरकार का और उस सरकार का यह फर्क है। आप किस ढंग से कम्पैरीजन करेंगे?

11.00 बजे।

हरियाणा की सरकार का आप कम्पैरिजन करें, यू०पी० की सरकार से, बिहार की सरकार से, आन्ध्र प्रदेश की सरकार से,

कर्नाटक की सरकार से या और दूसरी सरकारों से। पहले लोगों को पैसे देकर नौकरी लेनी पड़ती थी लेकिन अब लोगों में यह बात णै कि पैसे से नौकरी नहीं मिलती। लोग नौकरी के लिये पैसे लेकर चण्डीगढ़ में आते हैं लेकिन पैसे लेने वाला कोई नहीं है। इसी प्रकार से पहले ट्रांसफर भी पैसे देकर होते थे। अब ट्रांस्फर भी बगैर पैसे के होते हैं। कम होते हैं या ज्यादा होते हैं, यह सरकार की पौलिसी है। लेकिन लोगों में यह भावना हो गई है कि ट्रांस्फर और नौकरी इस सरकार में पैसे से नहीं मिलती। इन दोनों बातों के लिये हमारी सरकार की छवि लोगों में अच्छी बनी है। अब मैं अपने मुख्य मंत्री जी के बारे में कहना चाहूंगा। कल हमारे मुख्य मन्त्री जी सदन में नहीं थे। मैम्बरों को भी इस बात का पता नहीं था कि सी० एम० साहब कहां पर हैं। कल हमारे सी० एम० साहब सोनीपत गए थे क्योंकि वहां पर फसलों का ओलों की वजह से काफी नुकसान हुआ है। इस बात का न तो सोनीपत जिले के डी० सी० को पता चल पाया और न ही एस० पी० या एस० डी० एम० को पता लगा कि मुख्य मैली महोदय सोनीपत में आये हैं। यहां तक कि गांवों के किसी सरपंच को भी पता नहीं चल पाया। मुख्य मती जी किसी एक गांव में गए और उन्होंने चौकीदार से जा कर बात की। चौकीदार ने सरपंच को जा कर बताया कि सी० एम० साहब आये हैं। सी०एम० साहब ने वहां के लोगों की बातों को ध्यान से सुना और जिन को उचित मुआवजा दिया जाना था, उनको उसी समय मुआवजा दिए जाने के आदेश दिए गए। पहले भी बंसी लाल और चौधरी भजन लाल

चीफ मिनिस्टर रहे है। उनकी सरकार के कामकाज के बारे में सभी को अच्छी तरह से पता है। बंसी लाल जी की जब सभाएं होती थी तो पुलिस का क्या प्रबंध होता था, वह भी मे आपको बताना चाहुंगा। एक बार 9 जुलाई को रोहतक में एक ही दिन एक सभा को चौधरी देवी लाल जी ने भी संबोधित करना था और चौधरी बंसी लाल जी ने भी संबोधित करना था। उस समय चौधरी तैयब हुसैन होम मिनिस्टर थे। इन्हें इन सारी बातों का अच्छी प्रकार से पता होगा। उस समय रोहतक को एक छावनी की तरह बना दिया गया था। वहां पर 28–30 हजार पुलिस के और सी०आर०पी० के कर्मचारी डयूटी पर लगा दिए गए थे। इसके बावजूद भी रोहतक में बंसी लाल जी ने कैसे सभा की और कैसी की वह सभी को पता ही है। एक तो वे चीफ मिनिस्टर थे जिसकी सुरक्षा के लिये 30–30 हजार पुलिस कर्मचारी लगाये जाते थे और एक आज के चीफ मिनिस्टर चौधरी देवी लाल जी हैं जो आम जनता तक बगैर पुलिस की सहायता के अचानक जाते हैं। मैं समझता हूं कि इससे बढ़िया सरकार जनता की नुमायन्दगी करने के लिये और नहीं हो सकती। एक बात मैं और चौधरी तैयब हुसैन के बारे में कहना चाहूंगा। कल तैयब साहब, एऐक्साइज पालिसी जो शराब के ठेका के बारे में है, बोलते हुए कुछ कह रहे थे (विघ्न)। कल ये कह रहे थे कि इस पालिसी के तहत लोगों के घर उजड़ जायेंगे दार लोगों के घर बर्बाद हो जाएंगे। मैं इनको बताना चाहूंगा कि यह प्रथा हमने शुरु नहीं की। पिछली सरकारों से यह प्रथा चली आ रही है। किसी भी सरकार की सबसे अधिक

आमदनी इसी पालिसी से होती है। आगे भी जो सरकारें आएंगी उनको भी इसी प्रकार की पालिसी चालू रखनी होगी क्योंकि स्टेट के काम करने के लिये सबसे ज्यादा रैवेन्यू ऐक्साइज पालिसी से ही आता है। ऐसी भी सरकार रही हैं जिसके चीफ मिनिस्टर खुद ब्रीवरीज का लाइसैंसं अपने नाम से लेते रहे हैं। चौधरी भजन लाल ने ऐसा किया है। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो हिसार में जा कर देख लें। भजन लाल के समय में कालांवाली और नरवाना में जहरीली शराब पीने से एक एक रात में 300– 300 आदमी मरे हैं। हमारी सरकार के समय में ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। यह हमारी मजबूत सरकार है और बड़े अच्छे तरीके से काम कर रही है। कल तैयब साहब की और खुर्शीद साहब की आपस में कुछ चौलेंजबाजी हो रही थी। यह बात तो तब देखी जाती है जब जन आदेश लेने की बात हो। मैं यह समझता हूं कि 7 महीने पहले हरियाणा के लोगों ने क्या किया था, वह सभी को पता है। उस समय 3 बाई इलैक्शंज हुए थे। उनमें हमारे उम्मीदवार 30–30 हजार से अधिक वोटों से जीते थे। अगर हम अपनी रेशो को देखें तो वह हमारे हक में कम नहीं हुई हैं बल्कि बढ़ी है। वैस्टर्न कन्ट्रीज में तो गैल्प पोल हो जाता है तथा पता लग जाता है। ओपिनियन पोल होता है कि सरकार कैसी है और सरकार की पापुलैरिटी कितनी है। हमारे यहां देश में या प्रदेश में इलैक्शन ही एक सबसे बढ़िया तरीका है जिसमें जोर आजमायश हो सकती है और हर आदमी को पता लग सकता है कि तेरी जाति क्या है और जमीर क्या है। मैं तैयब साहब से निवेदन करूंगा कि फरीदाबाद में

पार्लियामैट का बाई इलैक्शन अभी होना है। वहां पर पार्लियामैंट का इलैक्शन करवाने के लिये हमारी सरकार ने केन्द्र को लिख कर भी दिया हुआ है। जब वह बाई इलैक्शन हो तो उस समय ये अपनी ताकत आजमाइश कर लें कि किस में कितनी ताकत है। ताकत आजमाइश खुर्शीद भाई करें या हमारा और कोई भाई करे, किसी को कोई एतराज नही है। अगर इन्होंने असैम्बली में लड़ना हो तो सोनीपत, रोहतक, जीन्द और गोहाना की बात तो छोड़ो वहां के लोग तो इनको (कांग्रेस पार्टी को)बिलों दिया करते है, यहां तो वाकई जनता ने इनको छोड़ा ही नहीं है, ये फरीदाबाद जिले से लड़ कर देख लें। तावडू की तो इनकी अपनी सीट है, जिसका ये बड़ा चर्चा करते हैं, अब वहां से भी लड़ कर देख लें। तावडू और नूह से अब इलैक्शन लड़ कर देखें, तब पता चलेगा कि हमारी क्या पोजीशन है? हमारे अजमत खां बैठे हुए हैं। वे सारे लोक दल की अजमत लिए बैठे हैं।

चौधरी तैयब हुसैनः तावडू में लोक दल के कैन्डीडेट की इस चुनाव मैं जमानत जब्त हुई थी।

श्री रणजीत सिंहः स्पीकर साहब, मेरा कहने का मतलब यह है कि यह सरकार किसानों, मजदूरों की सरकार है। हरियाणा के लोगों को इस सरकार पर गर्व है। यह सरकार किसी पिछली सरकार से पीछे नहीं है। जो पिछली सरकार ने नही किया, उसके करने की इस सरकार में तड़प है। देहात के लोगों ने मैसिव मैंडेट दिया है इसलिये यह सरकार देहात के लोगों के लिये अधिक से

अधिक कार्य करेगी। इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करते हुए और एक शेर पढ़ते हुए अपना स्थान लेता हूं–

हजारों हैं ख्वाहिश ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले।

बहुत निकले मेरे अरमां लेकिन फिर भी कम निकले।

श्री जगन नाथ (बवानी खेड़ा–अनुसूचित जाति): अध्यक्ष महोदय, दो दिन से राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बहस हो रही णै, मैं भी उस पर बोलने के लिये खड़ा हुआ हू। चौधरी देवी लाल की सरकार का अभिभाषण समाजवादी अभिभाषण था। समाजवाद तब आता है जब बेसहारा, गरीब, मजदूर, छोटे दुकानदार और छोटे कर्मचारियों को बराबर की सहायता दी जाये। जैसे–जैसे उनको दु:ख तकलीफ होती है वैसे–वैसे चौधरी देवी लाल कदम उठा रहे हैं। समय–समय पर जितने भी कदम उठाये हैं, चाहे वह कर्जा माफी का है और चाहे पैन्शन का है, वे बडे हो समाजवादी कदम हैं। सोशीलुस्ट कन्ट्रीज में ये कदम उठाये जाते हैं लेकिन दूसरी सरकारों ने नही उठाये। रोजाना बात होती शै कि जो अमीर आदमी है उसको नीचे लाना चाहिये और जो गरीव आदमी पाताल में बैठा हुआ है उनको ऊपर लाना चाहिए। यह जो असमानता है गरीब और अमीर में यह बहुत ज्यादा है। इस असमानता को बराबर किया जाये। टोटल असमानता को खत्म न किया जा सके तो कुछ हद तक बराबर कर दिया जाये। इसलिये

गवर्नर साहब ने जो अभिभाषण दिया है, यह समाजवादी विचारों का है।

यहां पर पैन्शन की भी बात कही गई। अध्यक्ष महोदय बड़े सीनियर मिनिस्टर गुप्ता जी भी यहा बैठे हुए हैं। उनके नोटिस में एक–दो बातें लाना चाहता हूं। बुढ़ापा पैन्शन का जब मनीआर्डर जाता है तो उस पर पांच रुपए फीस लगती है और दस पैसे मनीआर्डर फार्म के हो जाते हैं और एक रुपया पचास पैसे कम्प्यूटर का खर्चा हो जाता है। मनीआर्डर करने की बजाए यह पैसा कोआप्रेटिव बैकों को सीधा भेज दिया जाये तो वे वहां से ले लें। यह पांच रुपया मनीआर्डर का भी बच जायेगा क्योंकि यह पांच रुपया भी सैन्टर को ही जाता है। ऐसा करने से सरकार को बचत होगी। एक रुपया पचास पैसे कम्प्यूटर का खर्चा आता है। अगर इसे भी इस्तेमाल न किया जाये तो सीधा फार्म ने कर और भर कर भेज दिया जाये तो एक रुपया पचास पैसे भी बच जायेंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि गुप्ता जी इस बात पर ध्यान दें। दूसरे जो सब से ज्यादा समस्या है वह विधवाओं की पैन्शन की है। उनकी पैन्शन 50 साल की उम्र तक की है। बुढ़ापा पैन्शन 65 साल की उम्र वालों की है। इस प्रकार 50 और 65 साल में 15 साल का अन्तर हो गया। उस गैप में उन विधवाओं को कुछ नहीं मिल सकेगा क्योंकि आपने बुढ़ापा पैन्शन की उमर 65 साल कर दी है इस बात को पुनिया साहब नोट कर लें। यह बहुत जल्द गौर करने वाली बात है। विधवाओं की पैन्शन 50 साल के बाद

बन्द हो जाती है और बुढ़ापा पैन्शन 65 साल से शुरु होती है तो वे बेचारी 15 सारा क्या करेंगी? अब मैं शिक्षा के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। शिक्षा प्रणाली के बारे में सारे देश के अन्दर बड़ी भारी समस्या बनी हुई है। सारे ऐजूकेशनिस्ट्स तथा स्टेट्समैन इस बारे में चिन्तित हैं कि शिक्षा का सुधार कैसे किया जाए। भिवानी के अन्दर ऐजूकेशन बोर्ड है जहां पर एक फंक्शन हुआ था जिस में हमारे मुख्य मन्त्री चौधरी देवी लाल जी तथा दूसरे चेयरमैन वगैरा भी थे। वहां पर हमने कहा कि जव तक ये पब्लिक स्कूल रहेंगे, जब तक गरीब और अमीर बच्चे अलग–अलग पढ़ते रहेंगे, असमानता रहेगी। अमीरों के बच्चों की पढ़ाई वहां होती हैं जहां बडे–से–बडा स्कूल होता है और उन स्कूलों में किसी प्रकार की कमी नहीं होती। साइंस तथा ड्राईंग वगैरा का सारा सामान होता है लेकिन जहां हमारे बच्चे पढ़ते है, उन स्कूलों में या तो मास्टर पूरे नहीं होते अगर कहीं पर मास्टर पूरे होते हैं तो वहां साईंस और ड्राईंग का सामान नहीं होता। इस प्रकार हमारा बच्चा अमीर बच्चे के मुकाबले में कभी नही आ सकता। जब कभी कम्पीटीशन होते है तो हमारे बच्चे पीछे रह आते हैं और मजबूर हो कर उनको नकल मारनी पड़ती है। उनको नकल मारने का चाव नहीं होता वे तो इस लिए नकल मारते हैं ताकि थोड़े बहुत नम्बर मिल जाएं। हमारे मुख्य मन्त्री जी ने वहां पर कहा कि इस व्यवस्था को बदलना पड़ेगा और सारे बच्चे एक ही जैसे स्कूलों में पढ्ने चाहिएं। अब आप देखें कि एक बच्चा तो कार में वैठ कर स्कूल जाता है और साथ में उसको छोड़ने वाला आता है

और दूसरी तरफ ग्रीव वच्चे के पास बस्ता तक नहीं होता या फीस देने के लिए नही होती और खाने के लिए रोटी नही होती। वह बच्चा अमीर बच्चे का मुकाबला कैसे करेगा इसलिए उस में हीन भावना आ जाती है। चौधरी देवी लाल जी ने वहां पर कहा था कि ऐजूकेशन सब के लिए एक जैसी होनी चाहिए। लेकिन हमारे में से ही 2– 4 आदमी कहते हैं कि ऐसा करना असम्भव है। हर पार्टी में दो विचारधाराओं के आदमी होते हैं। कुछ समाजवादी होते हैं और कुछ प्रतिक्रियावादी होते हैं। मैं चौधरी देवी लाल जी को कहना चाहता हूं कि जो लोग कहते है कि ऐसा करना असम्भव है, वे उनके रास्ते में रोड़ा अटकाते हैं। मैं चाहता हूं कि जितनी जल्दी यह ढांचा बदले उतना ही अच्छा है। दो किस्म की तालीम नही होनी चाहिए। सब के बच्चे एक ही जगह पढ़ाए जाने चाहिएं। यहां कुछ आदमी कह देते हैं कि गरीब बच्चे के भाग्य में ही ऐसा लिखा है, यह बात गलत है। स्पीकर साहब, आप किसान हैं। आप देखें कि जमीन के एक जैसे दो किल्लो के अन्दर आप एक जैसा बीज डालें लेकिन एक किल्ले को अच्छा पानी मिले और अच्छी खाद मिले और दूसरे किल्ले को अच्छी खाद और पानी न मिले तो उनकी उपज बराबर कैसे हो. सकती है। इसलिए मैं इन बच्चों के बारे में यही कहना चाहूंगा कि अगर हमें इनका विकास करना है तो सब को एक समान भिक्षा मिलनी चाहिए। इस के बाद मैं खेल–कूद के बारे में कहना चाहता हूं चौधरी देवी लाल जी एक अच्छे खिलाड़ी रहे हैं। मैं भी किसी जमाने में थोड़ा बहुत काम चलाया करता था। चौधरी देवी लाल जी ने स्कूलों तथा कालेजों

में अलग–अलग स्पोर्टज नर्सरीज शुरु की हैं। छोटे–छोटे बच्चों के कैम्प लगाए जाते हैं और उनके इन्ट्रैस्ट के अनुसार ही उनको अलग–अलग गेम्ज खिलाए जाते हैं और ट्रेनिंग दी जाती है। आजकल छोटे–छोटे गांवों में भी स्टेडियम बनाए जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि हमारे खिलाड़ी कामन वैल्थ गेम्ज तक तो चले जाते हैं लेकिन ओलम्पिक में नही जा सके। इस बात को देखते हुए ही हम ने स्पोर्टस नर्सरी–स्कूल खोले हैं। एक बात मैं हरिजन और बैकवर्ड क्लासिज के बारे में भी कहना चाहता हू। हमारी सरकार इनके लिए काफी कुछ कर रही है। इनकी रिजर्वेशन के हिसाब से, 20 प्रतिशत तो रिजर्वेशन हरिजनों के लिए है और 10 प्रतिशत बैकवर्ड क्लासिज के लिए है। लेकिन मोस्टली डिपार्टमैंट्स में इनकी रिजर्वेशन पूरी नहीं होती। इसलिए मैं चाहुंगा कि सभी महकमे इस बारे में ध्यान दें।

(इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए)

इस के बाद में कहत के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। इस सरकार ने चारे के बारे में तकावी के बारे में बहुत कुछ किया है लेकिन पिछले 5– 7 दिनों से सबसिडी बन्द सी कर रखी है। मैं चाहता हू कि जब तक अच्छी बारिश न हो जाए, उस टाईम तक यह अनुदान वगैरा जारी रहना चाहिए वरना लोगों के पशु कुछ तो पहले ही कम हो गए हैं और जो बाकी बचते हैं, वे भी मर जाएंगे। अब मैं ला एण्ड आर्डर की बात कहना चाहता हूं। बन्सी लाल जी के टाईम में तैयब हुसैन जी होम मिनिस्टर थे, वे

देखें कि इनके समय में ला एण्ड आर्डर की क्या स्थिति थी और आज क्या है। उन दिनों में मुझे तथा श्री धर्म वीर को दस दिन में दो बार गिरफ्तार करवाया गया। तैयब साहब अभी आपने चौधरी वीरेन्द्र सिंह की बात सुनी होगी। उन्होंने कहा था कि चूंकि यह लोग इन चुनावों में साफ हो गए थे इसलिए इन को भी कमेटियों में प्रतिनिधित्व दिया जाए। मैं तैयब साहब को बताना चाहता हूं कि एक तो यह सरकार है और एक इनके वाली सरकार थी।

डिप्टी स्पीकर साहब, अब मैं एस०वाई०एल० के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। जैसे चौधरी रणजीत सिंह जी ने बताया पानी के बारे में बहुत सी स्टेटों में आपस में लड़ाई–झगड़े हैं। आज केन्द्र सरकार ने यह नीति अपना रखी है कि एक–दूसरी स्टेट को आपस में झगड़ा करने दो ताकि उनका ध्यान उधर ही बंटा रहे और वे मूल समस्याओं के बारे में सोच ही न सकें। इस के बारे में हमारे नेता श्री ओम प्रकाश चौटाला ने सारे हरियाणा में घूम कर कहा था कि नदियों के पानी का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए और इनके ऊपर सैन्टर का कन्ट्रोल होना चाहिए। ऐसा करने से सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। यहां पर श्री गुप्ता जी बैठे हैं। ये हमारे जिले से संबंध रखते हैं। जून, 1977 से पहले ये चीफ मिनिस्टर थे और अब उप–नेता हैं। अग्रोहा डिवैल्पमैंट ट्रस्ट बना हुआ है। पहली बात तो यह है कि उनको सरकार से लोन लेने की कोई जरुरत नही क्योंकि उनके पास पहले ही बहुत पैसा है। लेकिन फिर भी उन्होंने इस बात के लिए सी०एम० साहब को

किसी प्रकार मना लिया और उनसे पचास लाख ले लिया। उपाध्यक्ष महोदय, 1977 के अन्दर हम सारे के सारे जेलों के अन्दर थे लेकिन उस इम्प्रूवमैंट ट्रस्ट के कौन–कौन मैम्बर बने उनके नाम हैं, घनश्याम दास गोयल, ओम प्रकाश जिन्दल, वासुदेव वगैरह यानी सारे के सारे ..... उस समय ठेकेदार थे। डिप्टी स्पीकर साहब, या तो उनको हटा दिया जाए वरना हम मुख्य मन्त्री जी की परमिशन ले कर उनका घेराव करेंगे।

श्री उपाध्यक्षः यह जलील आदमी वाले शब्द रिकार्ड न किए जाएं।

श्री जगननाथः इन शब्दों के साथ उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करते हुए अपना स्थान लेता हूं।

श्री सीता राम सिंगला (गुड़गांव): उपाध्यक्ष महोदय, 14 मार्च को इस लोक प्रिय सरकार का बजट अधिवेशन शुरु हुआ है। उसके प्रारम्भ में राज्यपाल महोदय ने भाषण दिया था और 15 मार्च को डाक्टर मंगल सैन जी ने उसके लिए धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया था और रण सिंह जी ने उसका समर्थन किया था। उसी के समर्थन के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। सब से पहले तो राज्यपाल महोदय ने हिन्दी में भाषण किया। मुख्य मन्त्री जी ने उनकी तकलीफ को देखते हुए उनको यह निवेदन किया कि आप अंग्रेजी में बोलो, लेकिन फिर भी वे हरियाणा की भूमिका को देखते हुए हिन्दी में बोले। इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, जिस वक्त चौधरी देवी लाल जी ने इस सरकार को संभाला तो एक तरफ तो सूखा पड़ा हुआ था और दूसरी तरफ चौधरी बंसी लाल करोड़ों रुपयों का कर्जा इस सरकार पर छोड़ गया था। ऐसी स्थिति में सत्ता संभालने के बाद भी उन्होंने विकास के कामों को उसी प्रकार से जमकर करके कर दिखाया.। जो प्रोग्राम उन्होंने 5 साल के लिए अपने चुनाव मैनीफैस्टो में रखा था, उसका 80 प्रतिशत पिछले 9 महीने के अन्दर ही पूरा कर चुके हैं। हरियाणा एक कृषि प्रधान प्रदेश है। यहां की 82 प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर करती है। बिजली की बहुत अधिक कमी थी। किसान कई सालों से बिजली के लिए परेशान था। लेकिन अब हम जब गांवों के अन्दर जाते हैं तो किसान हमको यह कहते हैं कि भई लगातार इतने टाईम तक आप बिजली देते हो, कि कुएं पानी को नाट जाते हैं। आप बिजली थोड़ा ठहर–ठहर कर दिया करो। इस प्रकार का बिजली का आजकल प्रबन्ध है। इस सरकार ने आगे क्या किया। बुढ़ापा पैशन मंजूर कर दी, कर्जे की माफी की बात है। किसानों को 32 रुपए क्विंटल गन्ने की कीमत दी है जो किसी भी दूसरे प्रान्त ने नहीं दी है। बेरोजगार नवयुवकों को इन्टरव्यू के लिए की पास की सुविधा दी है। किसानों को सड्कों के साथ लगते खेतों में लगे दरख्तों की आमदनी का 50 प्रतिशत हिस्सा दिया गया है। सूखा ग्रस्त क्षेत्र के अन्दर रोजगार योजना के तहत रोजगार उपलब्ध करवाया है। आप किसी भी हरियाणा के गांव में चले जाएं, किसी भी जिले में चले जाएं, कोई भी ऐसा गांव नहीं है जहां पर विकास का कार्य न हो रहा होगा। चाहे

गांवों की गलियों को पक्का करने की बात हो, या भवन निर्माण की बात हो, हर तरफ मजदूरों को मजदूरी उपलब्ध हो, इस बात की हमारी सरकार ने व्यवस्था की है। मुझे बड़े खेद के साथ एक बात कहनी पड़ रही है कि जब हरियाणा के अन्दर इतना जबरदस्त सूखा पड़ा, उस वक्त हिन्दुस्तान के अन्दर सबसे ऊपर गद्दी पर बैठने वाले व्यक्ति राजीव गांधी ने यह घोषणा कर दी कि हम इसके लिए 403 करोड़ रुपया हरियाणा सरकार को देंगे लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद अभी तक केवल 37 करोड़ रुपया हरियाणा सरकार को दिया गया है जबकि हमारे साथ लगी हुई स्टेट राजस्थान को 403 करोड़ रुपए की सहायता दी गयी है। इससे बड़ी दुःख की एक और बात है। तीन–तीन बार प्रधान मन्त्री महोदय ने हरियाणा के सूखाग्रस्त इलाकों का दौरा करने के लिए समय दिया। हमने तैयारियां कीं, उनको दिखाने के लिए लेकिन वह हमारी छाती से लांघकर राजस्थान के अन्दर जा सकते हैं लेकिन हरियाणा के अन्दर तीनों दफा उन्होंने अपने प्रोग्राम कैंसिल कर दिए। कई बातें ऐसी हैं जिनसे यह पता चलता है कि सरकार किस प्रकार से काम कर रही है। उपाध्यक्ष महोदय, अभी तक देश के अन्दर ऐसे लोगों का शासन रहा है जिन्होंने पैदा होते ही चांदी के चम्मच में टूध पीया था। जिनके कपड़े पैरिस से धुल कर आते थे। उनको यह पता नहीं है कि गरीबी क्या होती है। गरीबी तो उनसे सैकड़ों मील दूर रहती थी। उनको गरीबी की स्थिति का पता नहीं बै लेकिन हरियाणा की जनता ने ऐसे हाथों में हकूमत सौंपी है जो खुद किसान का बेटा है जिसने यह सब कुछ देखा

है। उन्होंने कुछ ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं जो सारे देश के लिए और दूसरे प्रान्तों के लिए एक उदाहरण हैं। उदाहरण के तौर पर कांग्रेस सरकार के टाईम पर किसान बेचारा फरियाद लेकर जिलाधीश, एस०पी० या तहसीलदार के पास अगर जाता था तो वह उसके दफ्तर के बाहर घंटों खड़ा रहता था। चपड़ासी की हिम्मत नहीं होती थी कि वह अन्दर जाकर चिट भी दे दे। इस सरकार ने यह आदेश दिया है कि अधिकारी रोज जनता दरबार लगाएंगे ताकि किसानों व गरीब जनता की शिकायतों को सुना जा सके। जब कभी मन्त्रीगण रैस्ट हाउसिज में जाते थे तो सारे जिले के अधिकारी एक–एक घंटे तक उनका इन्तजार किया करते थे और सारा सरकारी काम ठप्प पड़ जाता था और लोग अफसरों की प्रतीक्षा किया करते थे कि कब वह वहां पर आएं और उनके काम हों। सरकार ने इस परम्परा को भी समाप्त कर दिया है। ऐसा करके उसने एक नया उदाहरण पेश किया है। पहले मन्त्रियों की रैस्ट हाउसिज में सलामी की व्यवस्था थी। पुलिस वहां पर मन्त्री की इन्तजार करती रहती थी। इस सरकार ने फैसला किया है कि भविष्य में मन्त्रीगण सलामी नहीं लेंगे। पहले मन्त्रियों का नाश्ते और भोजन का प्रबन्ध रैस्ट हाउस में होता था, वह भी बन्द कर दिया है। उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं कई महत्वपूर्ण सुझाव इस सरकार को देना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस सरकार ने बहुत से गांवों की जमीन को ऐसे गलत ढंग से ऐक्वायर किया है कि वहां के लोगों का जीवन दूभर हो गया है। मैं कुछ गांवो के नाम लेना चाहता हूं जैसे डूढाहेड़ा, मोलाहेड़ा, सरहोल और

चकरपुर। ये ऐसे गांव हैं जहां पर जमीन बहुत ही गलत ढंग से ऐक्वायर की गई है। वहां पर आने जाने का रास्ता कोई नहीं है और शमशान तक ऐक्वायर कर लिया गया है। इन गांवों में तालाब तक ऐक्वायर कर लिया है जहां से पीने का पानी लिया जाता था। ऐसा एक गांव कार्टरपरी है। चौधरी देवी लाल को वहां पर बुलाया थो और दिखाया था कि इस तरह से जमीन ऐक्वायर करने से लोगों को कितनी दिक्कत हो रही है। आज किसानो का नेता इस राज्य का मुख्य मन्त्री है और लोगों को आशा है कि इस प्रयशर से जो जमीनें ऐक्वायर की गई हैं, उनको छाया जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा के अन्दर जो पुराने गांव या पुरानी बस्तियां हैं, वहां पर खारा पानी मिलता है और उनके लिए पानी की व्यवस्था बहुत दूर से की गई है। बहुत लम्बी लाइन होने के कारण पानी का प्रैशर नहीं होता और पानी ठीक नहीं मिल पाता। मैं चाहूंगा कि खारे पानी को मीठे पानी में बदलने की व्यवस्था की जाए जिससे कि लोगों को पानी की सुविधा हो सके। उपाध्यक्ष महोदय, जितने बड़े नगर लूँ और विशेषकर दिल्ली की सीमा के पास वहां अनऐप्रूब्द कालोनीज बहुत ज्यादा बन गई हैं। कालोनाइजर्ज ने किसानों से सस्ते भाव पर जमीनें खरीद कर छोटे–छोटे प्लाट बनाकर गरीब लोगों को बेच दिए हैं। वे ऐप्रूव्ड कालोनीज नहीं हैं। कमेटी उनका नक्शा पास नहीं करती। उन्होंने अपने हिसाब से सड़कें और गलियां बना ली हैं और अपने हिसाब से मकान बना लिए हैं। इस कारण वहां सफाई का कोई प्रबन्ध

नहीं है और वे स्लम एरिया बनते जा रहे हैं। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि कोई विशेष राशि रखी जाए जिससे कि स्लम एरियाज में जो गन्दगी हो गई है उसकी सफाई और ठीक प्रकार से रखने का इन्तजाम किया जा सके तथा इन काही को सुन्दर बनाया जा सके। मेरी प्रार्थना है कि सरकार इस ओर विशेष ध्यान दे।

उपाध्यक्ष महोदय, छोटे से छोटे आदमी को सरकारी काम के लिए ऐफीडेविट देना पड़ता है और ऐफीडेविट के लिए तीन रुपए के कागज की जरुरत पड़ती है लेकिन वह तीन रुपए का कागज नहीं मिलता। तीन रुपए का क्या दस रुपए का भी कागज नहीं मिलता और कई बार तो तीन रुपए के कागज के लिए बीस रुपए की स्टाम्प खरीदनी पड़ती हैं। मेरा सुझाव है कि इसकी व्यवस्था की जाए जिससे लोगो को तीन रुपए का कागज आसानी से मिल सके।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं स्कूल शिक्षा की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। स्कूली शिक्षा के साथ शारीरिक शिक्षा भी दी जाती है जिससे बच्चे स्वस्थ रहें। मेरा सुझाव है कि सरकार नैतिक शिक्षा देने की ओर भी ध्यान दे। आज के युग में नैतिक शिक्षा की बहुत आवश्यकता है। उपाध्यक्ष महोदय, जिन गुरुओं ने चांदनी चौक में गोली के सामने सीना तान दिया और जिन गुरुओं ने अपनें बच्चे दीवार के अन्दर चिनवा दिए आज उन्हीं की सन्तान उग्रवादी हो रही है। इसका कारण सिर्फ यह है

कि बच्चों को नैतिक शिक्षा नही मिल रही है देश भक्ति की शिक्षा नहीं मिल पी है और इस कारणे बच्चों के अन्दर देशभक्ति के संस्कार पैदा नहीं हो रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारे देश को आजाद हुए चालीस हाल हो गए हैं लेकिन हमारे देश का इतिहास आज तक नहीं बना है। आज भी हमारे बच्चों को पढ़ाया जाता है कि आर्य लोग बाहर से आए थे। मैं कहना चाहता हूं कि जब आर्य ही बाहर से आए थे तो इस मुल्क में कौन रहता था। मेरा निवेदन है कि नैतिक शिक्षा और देश भक्ति की शिक्षा का सिलेबस बच्चों के लिए योजनाबद्ध तरीके से बनाया जाए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि कुछ लोगों ने शिक्षा को व्यवसाय का सा धन बनाया हुआ है। बड़े–बड़े नगरों में गलियों के अन्दर इस प्रकार के स्कूल खोल दिए हैं जिनमें पांच सौ या चार सौ बच्चे होते हैं। बड़ी लम्बी चौड़ी फीसें उनसे ली जाती हैं और बहुत कीमती किताबें सिलेबस में रखी जाती हैं। उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे स्कूलों में वच्चों का शोषण होता है और कर्मचारियों का भी शोषण होता है। सौ रुपए या दो सौ रुपए महीना उन टीचरों को दिया जाता है जो वहां पर पढ़ाते हैं। मेरी प्रार्थना है कि ऐसी दुकानों को जिन्होंने शिक्षा को प्रोफैशन बना लिया है, फौरन बन्द कराना चाहिए और केवल मान्यता प्राप्त स्कूलों को ही खोलने की इजाजत होनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रदेश में जनता के स्वास्थ्य की ओर भी काफी ध्यान दिया जा रहा है। सरकार ने काफी प्राथमिक

स्वास्थ्य केन्द्र खोले हैं। राज्य में 408 आयुर्वेदिक यूनानी डिस्पैसंरियां हैं और बीस डिस्पैसरियां और खोलने का सरकार का विचार है। उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं होम्योपैथिक डिस्पैसरीज के बारे में कहना चाहता हूं। गुडगांव में 21 होम्योपैथिक डिस्पैसंरीज रैडक्रास के माध्यम से चल रही थीं। कई लाख लोग इन डिस्पैसंरीज से फायदा उठा रहे थे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं होम्योपैथिक उपचार के बारे में बताना चाहता हूं कि यह बहुत सस्ता इलाज है। किसी प्रकार की ऐलर्जी इन दवाइयों से नहीं होती जै से कि अंग्रेजी दवाइयों से होती है। इन दवाइयों के लेने से कोई नई बीमारी पैदा नही होती जैसा कि ऐलोपैथिक दवाई लेने से होती है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि इन 21 डिस्पैसरियों को सरकार अपने हाथ में ले, अपने अधिकार में ले जिनको कि पिछले महीने बन्द कर दिया गया था। डी०सी० महोदय इसके लिए मान गए हैं। इन डिस्पैंसरियों के बन्द किए जाने से जनता को तो परेशानी हुई ही है लेकिन इनमें काम करने वाले कर्म चारी भी सड्कों पर आ गए हैं। वे बेचारे भी बे कार हो गए हैं। इसलिए सरकार इस की ओर विशेष ध्यान दे ताकि इन डिस्पैसरियों का काम सुचारू रूप से चलता रहे और लोगों को भी कुछ राहत मिल सके।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं बिक्री कर के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं कि जहां सरकार ने बिक्री कर में राहत दी है वहां इसके सरलीकरण की ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए।

इस बिक्री कर के सरलीकरण में काफी गुंजाइश है क्योंकि दिल्ली नजदीक होने के कारण हरियाणा के व्यापारियों पर इसका काफी असर पडता है। दिल्ली और हरियाणा के टैक्स में काफी अन्तर है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि दिल्ली की तरह ही हरियाणा में भी सेल्स टैक्स एक जैसा करू दिया जाए ताकि लोग हरियाणा के अन्दर ही बैठकर अपना व्यापार भली भांति और सुचारू रूप से चला सकें।

उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने एक अग्रोहा विकास बोर्ड का गठन किया है और इसके लिए सरकार सचमुच में बधाई की पात है। अग्रसेन जी ने ही सब से पहले समाजवाद की बात की थी। उनके राज में लोग बड़े प्रसन्न थे। उनके राज्य में पहले ही रोज में आदमी लखपति बन जाता था। वे कहते थे कि मेरे राज के अन्दर कोई भी व्यक्ति आए और पहले रोज ही लखपति बन जाए। प्रति घर मे से एक रुपया और एक ईंट ली जाती थी। एक एक रुपए से लाख रुपया और लाख ईटों से वह अपना मकान बना सकता था। इस तरह का राम राज्य उनके युग में था लोग सचमुच में बड़े ही प्रसन्न थे। ऐसे समाजवादी नेता का हरियाणा की धरती पर जन्म हुआ और आज उस की याद में सरकार ने जो विकास बोर्ड बनाया है, उसके लिए हम सब सरकार के आभारी हैं। सरकार सचमुच में बधाई की पात है। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक बात यह भी अवश्य यहां पर कहना चाहता हूं कि इस बोर्ड के अन्दर जो सदस्य हैं उनके बारे में हमें आपत्ति है क्योंकि जो

जैनुअन आदमी इस बोर्ड में होने चाहिए थे, वे इस से वंचित रह गए हैं। जिन्होंने हमारे साथ जेलें काटीं जिन्होंने स्वतन्त्रता की लड़ाई में जमकर संघर्ष किया, ऐसे आदमी इस बोर्ड के अन्दर होने चाहिए थे लेकिन इस बोर्ड के अन्दर ऐसे आद– मियों को नहीं लिया गया है। जो आदमी इस बोर्ड के अन्दर लिए गए हैं, वे बिछल हरियाणा की आम जनता के लिए अपरिचित हैं। हमसे उनकी विचार– धाराएं बिल्कुल नहीं मिलती। इसलिए सरकार से हमारी प्रार्थना है कि इस बोर्ड के मैम्बरों के बारे में जरा फिर से विचार किया जाए और सही आदमी इस बोर्ड के अन्दर भर्ती किए जाएं।

उपाध्यक्ष महोदय कर्मचारियों ने भी कुछेक मांगे रखी थीं। उन में से काफी कुछ तो मान ली गई हैं लेकिन फिर भी मेरी सरकार से प्रार्थना है कि जिन कर्म– चारियों का हमारी इस सरकार को जिताने में पूरा हाथ है, उनकी ओर खास तवज्जह दी जाए ताकि उन में कोई रोष न हो। इसलिए कर्मचारियों के साथ टेबल पर बैठकर सम्मानपूर्वक बातचीत कर ली जाए तो बेहतर रहेगा। इसके साथ साथ एक और निवेदन है कि कर्मचारियों के अन्दर ट्रांसफर के मामले में काफी परेशानियां होती हैं और हर कर्मचारी अपनी ट्रांसफर शहर में ही करवाना चाहता है। 8 किलोमीटर के दायरे में आना चाहता है ताकि उसको हाउस रैन्ट मिल सके। जो कर्मचारी देहातों में रहते हैं उनको आर्थिक हानि होती है क्योंकि उनको शहर वालों की तरह हाउस रैन्ट नहीं

मिलता है। शहर में रहने वाला कर्मचारी अपने बच्चों के पास रहता है और शाम को घर आ जाता है लेकिन जो गांवों में काम करने वाले कर्मचारी हैं वे इन सब सहूलियतों से वंचित रह आते हैं। इसलिए मेरी यह प्रार्थना है कि शहर और गांव में काम करने वाले कर्मचारियों के साथ आक्स में इस प्रकार का भेदभाव नही होना चाहिए। सभी एक समान होने चाहिए। जिस प्रकार से शहर वालों को हाउस रैन्ट और दूसरे भत्ते मिलते हैं उसी प्रकार से गांव में काम करने वाले कर्मचारियों को भी हाउस रैन्ट और दूसरे भत्ते मिलने चाहिए। ऐसा करने से गांवों से जो शहरों के अन्दर ट्रांसफर करवाने की कर्मचारियों की होड़ लगी हुई है, वह भी समाप्त हो जाएगी और सरकार को भी किसी प्रकार की परेशानी नही होगी। सरकार का खर्चा भी कम होगा। इन्ही सुझावों के साथ यह जो गवर्नर ऐड्रैस पर धन्यवाद का प्रस्ताव यहां पर जेरे गौर है, मैं उसकी पुरजोर ताईद करता हुआ आपका धन्यवाद करता हूं क्योंकि आपने मुझे बोलने का समय दिया। जय हिन्द।

श्री रघु यादव (रिवाड़ी): उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभि– भाषण पर डाक्टर मगल सैन ने जो धन्यवाद का प्रस्ताव पेश किया है और जिसको श्री रण सिंह मान ने अनुमोदित किया है, मैं उसका समर्थन करने और उस पर, अपने विचार व्यक्त करने के लिए खड़ा हुआ हूं। उपाध्यक्ष महोदय, इसमें कोई सन्देह नही कि हरियाणा की पिछली तमाम सरकारों से वर्तमान सरकार बेहतर है। यह सरकार, हरियाणा के अस्तित्व, हरियाणा की सान

मान को बचाने के लिए जो संघर्ष हुआ उस के परिणाम स्वरूप सत्ता में आई है। उपाध्यक्ष महोदय, दिल्ली के कायर और कमजोर हुक्मरानो ने अपनी जान बचाने के लिये हरियाणा को पक्ष बनाए बिना आतंकवाद के सामने अपने घुटने टेक दिए थे। हरियाणा को पक्ष नही बनाया गया था। यह हरियाणा की हल्का को चुनौती थी। जल और जमीन के विवद में, जिसके साथ हरियाणावासियो के आर्थिक हित जुड़े हुए हैं, एक अन्याय– पूर्ण फैसला किया गया। उससे हर हरियाणवी आन्दोलित हो उठा। हरियाणा के लोभों ने एक बार फिर क्सी दिया कि यह वह हरियाणा है जहां पर महाभारत की समर भूमि कुरुक्षेत्र मौजूद हे, जो युगों युगों से पूरे विश्व के लोगों को अनदेखी और अन्याय के खिलाफ संघर्ष के लिए प्रेरित करली आ रही है। आप सबको मालूम है कि हमारे अभूतपूर्व संघर्ष में हजारों लोगों ने जुल्म सहे और लाठियां खाई और कुछ लोग अपनी जान पर भी खेल नए। 17 जून, 1987 को हरियाणा विधान सभा का जो चुनाव हुआ, वह कोई मामूली चुनाव नहीं था। उस चूनाव में गांधीवादी तरीके से लोकतांत्रिक प्रक्रिया का उपयोग करते हुए हरियाणवियों ने अपने मताधिकार के प्रभावी व सफल प्रयोग से इस देश के तमाम राजनैतिक दलों को यह साफ कह दिया कि अगर भविष्य में हरियाणवियों के साथ अनदेखी कौ कई, हरियाणवियों के सम्मान चर चले की गई अथवा हरियाणा को बिना पक्ष बनाए उसके हितों की बलि चढाने की कोई साजिश की गई तो हरियाणवी जनता उनका वही हश्र करेगी, उस साजिश

के वही परिणाम होंगे जो 17 जून, 1987 को हरियाणा में कांग्रेस पार्टी को भुगतने पड़े हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, इस लोकप्रिय सरकार की नीतियों और नीयत पर कोई शक नहीं किया जा सक्ता। इस सरकार की नीति बहुत अच्छी– है और इसकी नीयत बिछल साफ है। वैसे तो यह सरकार समाज के तमाम वर्गों के सहयोग से बनी है लेकिन मैं कहूंगा कि इस सरकार को बनाने में सर्वाधिक सहयोग किसानों के साथ साथ दलितों, पिछड़ों बेरोजमारो और कर्मचारियों का है। उपाध्यक्ष महोदय, केवल घोषणाओं और योजनाओं से काम चलने वाला नही है, हर सरकार का फर्ज होता है कि वह देखे कि जो योजनाएं जन कल्याण के लिए बन रही हैं उसका लाभ उस व्यक्ति तक पहुंचे जिसको लाभ पहुचाने के लिंए योजनाएं बनाई जा रही हैं। कुछ अच्छी व क्रान्तिकारी पहल हरियाणा में हुई है जिनका अनुसरण इस देश के अन्य राज्यों में भी होना चाहिए। इससे पहले कि मैं किन्हीं और बातों का जिक्र करूं, सबसे पहले मैं अपनी सरकार को बधाई देना चाहूंगा कि उसने 85 साल की उम्र से बड़े सभी बुजुर्गों को 100 रुपए महीने की वृद्धावस्था पैंशन देनी शुरु की है। लेकिन मैं यह भी कहूगा कि सरकार ने बूढ़ों पर यह कोई अहसान नही किया है। जिस व्यक्ति ने अपना सारा जीवन समाज को बनाए रखने के लिए, समाज को जारी रखने के लिए होगा हैं, उसके प्रति समाज और सरकार का यह दायित्व है, जिसे इस देश में सर्वप्रथम हरियाणा सरकार ने निभाया है। सरकार का बूढ़ों को

वृद्धावस्था पैशन देना एक स्वागत योग्य कदम है। इसके साथ मैं एक बात यह भी कहना चाहूंगा कि गांवों में जो सरपंच बैठे हैं, उन्होंने गलत बात तसदीक करके काफी लोगों को जो पैशन के हकदार नहीं थे, उनको पैंशन दिलवा दी। सरकारी मशीनरी में आज भी कुछ काली भेड़ें बैठी हुई हैं जो नहीं चाहती कि यह सरकार कामयाब हो। जब ये लोग गांवों में सर्वे करने गए तो अपात्र अधेडों को पैशन दे दी और जो पात बुजुर्ग थे उनको वृद्धावस्था पैशन देने के लिए सूची में शामिल नहीं किया गया, यह शिकायत हरियाणा के तकरीबन सभी गांवों से आई है। यह ठीक बात है कि अब हमारी सरकार इस गल्ती को सुधारने के लिए काम कर रही है लेकिन जिन लोगों ने यह गलती की है उनको बख्शा– नहीं जाना चाहिए। जिन लोगों ने गलत पैन्शन ली है उनके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए। इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जिस सरपंच ने गलत तसदीक की है उसे भी नही छोड़ा जाना चाहिए। अब भी कुछ ऐसे तत्व हैं जो हमारी मौजूदा सरकार को कामयाब नहीं होने देना चाहते। इस बारे में मैं एक बात का जिक्र रोहतक जिले के बारे में करना चाहूंगा। रोहतक जिले की कोसली तहसील में एक गांव है सुधराना। इस गांव के श्री हीरा लाल सुपुत्र श्री प्रभु दयाल को तो पैशन दे दी गई जबकि उसी के बड़े भाई श्री सरदार सिंह

सुरज श्री प्रभु दयाल को पैन्शन नहीं दी गई, जबकि श्री सरदार सिंह श्री हीरा लाल से चार साल बडा है। मैं पूछना

चाहता हू कि उसको पैन्शन क्यों नहीं दी गई। हमारी सरकार ने वृद्धावस्था पैन्शन देने की एक–मिसाल कायम करनी है। जिन लोके से अनजाने में काम गलत हो जाए. तो अलग बात है लेकिन अगर कोई जान– बूझ कर गलत काम करे तो उसे छोड़ा नही जाना चाहिए। 40– 40 साल के लोगों को तो पैन्शन दे दी गई लेकिन जो 85 साल या इससे अधिक उल के व्यक्ति थे उनको छोड़ दिया गया। सुधराना गांव की तो मैंने एक मिसाल दी थी। ऐसे बहुत से केसिज है। कई जगहों पर पत्नी को पैन्शन दे दी गई लेकिन उससे बड़े उसके पति को पैन्शन नहीं दी गई। हमने वृद्धावस्था. पैन्शन से यह माहौल ध्याना है कि जिससे हमारे समाज में बुजुर्ग पूरे सम्मान के साथ जी सकें। इस बारे में है यह कहना चाहूंगा कि बूढ़े व्यक्तियों को पैन्शन देने को महज एक नारा न बनाया जाए बल्कि इस्के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार किया जाए ताकि रैगुलर बेसिज पर जो व्यक्ति 65 साल के होते हैं उन्हें पैन्शन मिलती रहे और जो बूढ़े व्यक्ति, पैन्शन लेने वाले, मर जाए उनके नाम से कोई दूसरा व्यक्ति पैन्शन न लेता रहे। इस बारे में मेरा सरकार को एक सुझाव है कि यह वृद्धावस्था पैन्शन हमारे जो सहकारी बैक्स हैं, यानी गांवों में जो मिनी बैक्स हैं, उनके जरिए दी जाए। जिस प्रकार से इन बैंकों से लिया गया लोन वापस लेने के लिए इन बैक्स के कर्मचारी गांव गांव सें और घर घर में जाते हैं, उसी प्रकार से वे पैन्शन बांटने का काम भी घर –घर जाकर अच्छी प्रकार से कर सकते हैं। वे ही रजिस्टर में सारा रिकार्ड

रखें। ऐसा करने सें डाक पर पैन्शन भेजने का जो खर्चा होता है वह भी बचेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने तीन सड्कों के नाम उन तीन नौजवानों के नाम पर रखे हैं जो हरियाणा संघर्ष समिति के आन्दोलन के दौरान हरियाणा के हितों के लिए शहीद हुए हैं। इस आन्दोलन में शहीद होने वाले ये नौजवान श्री कालू राम गोयल श्री धर्म सिंह गैर श्री बलबीर सिंह थे। सरकार ने यह बहुत अच्छा काम किया है कि जो लोग अपने प्रानन के हितों के लिए देश के हितों के लिए शहीद हों उनकी याद में स्मारक स्थापित किए जाएं ताकि उनसे आने वाली पीढ़ीं प्रेरणा ले सके। मैं यहां पर एक बात और कहना चाहूंगा कि जब बंसी लाल को दुबारा हरियाणा पर थोपा गया था तो उन्होंने आते ही 23 सितम्बर को, हमारे हरियाणा के जो स्वतन्त्रता सेनानी शहीद हुए थे, उनके सम्मान में एक अवकाश हुआ करता था, उसे बन्द कर दिया था। ऐसा करके उन्होंने हरियाणा के स्व– तन्त्रता सेनानियों का अपमान किया था और हरियाणा के लोगों की भावनाओं पर कुठाराघात किया था। इस सरकार के सत्ता में आने के बाद हरियाणा विधान सभा का एक विशेष अधिवेशन 9 अगस्त को हुआ था। उस अधिवेशन में मैंने यह मांग की थी कि 23 सितम्बर का जो अवकाश रद्द किया गया है उसे बहाल किया जाए और 23 सितम्बर को रिवाड़ी में सरकारी स्तर पर शहीदों के सम्मान में समारोह किया जाए। मैं यहां पर यह भी बताना चाहूंगा कि सच तुला राम

1857 के स्वतन्त्रता संग्राम के हरियाणा के संबसे अग्रणी स्वतन्त्रता सेनानी थे। हमारी इस सरकार ने मेरे अनुरोध पर 2 .3 सितम्बर का रद्द किया हुआ अवकाश बहाल किया है और हरियाणा के स्वतन्त्रतो सेनानियों की भावनाओ का सम्मान करते हुए इस बारे 23 सितम्बर को सरकारी स्तर पर एक समारोह भी आयोजित किया। हरियाणा के मुख्य मन्त्री चौधरी दैवी लाल ने विधाय सभा में किए नए मेरे अनुरोध को स्वीकारते हुए 23 सितम्बर को रिवाड़ी के नाईवाली चौक पर राव तुलाराम की एक कांस्य प्रतिमा का शिलान्यास भी किया। ऐसा करने से अहीरवाल के लोग बहुत खुश हैं और हरियाणा के तमाम लोग इस शहीद के सम्मान से बड़ा फख्र महसूस करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात का यहां पर और भी उल्लेख करना चाहता हूँ। हरियाणा प्रदेश में एक मुख्य मन्त्री हुए हैं जो राव तुला राम का नाम न केवल इस्तेमाल करते रहे बल्कि अपनी राजनैतिक रोटियां भी सेंकते रहे। उन्होंने शहीद राव तुला राम कैं नाम से न केवल वोट खोर नोट लिए बल्कि उनके नाम को सरे बाजार बेचा। वे राव तुला राम के खानदान का होने का फर्जी दावा करते रहे और करोड़ों रुपया चन्दे का उनके नाम से बटोरते रहे।

चौधरी तैयब हुसैनः आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। पहली बात यह है कि जो लक्स हाउस मैं मौजूद नहीं है उसका नाम नहीं लिया जा सकता। दूसरे यह कहना कि वे उनकी औलाद

में से नही है, यह भी गलत है। इस तरह की बातें कहना मुनासिब नहीं है।

श्री उपाध्यक्षः यह प्वायंट आफ आर्डर नही है। उन्होंने किसी कां नाम नहीं लिया है।

श्री रघु यादवः उपाध्यक्ष महोदय, मैंने किसी की नीम नहीं लिया। तैयब जी सभी चोरो और फरेबियों को जानते हैं। वे जानते हैं कि गुनोहगार कौने है। उपाध्यक्ष महोदय मेरा इतना ही निवेदन है कि हमारी सरकार रिवाड़ीं मे नाईबाली चौक पर शहीद तुला राम की कास्य की प्रतिमा लगा रही है लेकिन जो शख्स राव तुला राम के नाम को बाजार में बेचता रहा और उनके नाम से राजनैतिक रोटियां सेंकता रहा वह आज तक भीं हिन्दुस्तान में कहीं भी उस अमर शहीद की एके पत्थर की मूर्ति, करोड़ों रुपया चन्दा ले करें भी, नहीं लगा सका। यह बड़ी खर्म की बात है लेकिन यह सरकार उस शहीद की कास्य कीं प्रतिमा लगा रही है जो हरि– याणवियों के लिए बड़े गौरव की बात है। सरकार को तमाम अहीरवाल के लोग इस बात के लिए बधाई देते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, दरियापुर में भीष्ण हत्याकांड आतंकवादियों द्वारा किया गया, वह बड़ा ही शर्मनाक कांड था। उस हत्याकांड में 16 अपराधियों को इस सरकार ने पकड़ा और सारी स्थिति पर काबू पाया। इस बात के लिए मैं हरियाणा पुलिस को बधाई देता हूं। लेकिन मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं

कि हरियाणा में टैरोरिस्ट ऐक्ट लागू है और ऐन्टी टैरोरिस्ट सैल भी बनाया जा खा है। साथ ही एन० डी० पी० एस० ऐक्ट भी लागू है। जो लोगों को तंग और परेशान करने का पुलिस के पास सब से बड़ा हथियार है। तैयब साहब इस बारे में मुझ से ज्यादा जानते हैं क्योंकि रिवाड़ी में जब भ्रष्टाचार के खिलाफ जिहाद शुरू किया था उस समय चौधरी बंसी लाल ने महेन्द्रगढ़ जिले के युवा जनता के प्रधान श्री हंसराज ग्रोवर को झूठा चाकू दिखा कर टैरोरिस्ट ऐक्ट में बन्द कर दिया था। जब कि उन्होंने कभी भी चाकू या बम्दूक पकड़ी भी नहीं थी। भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम के दौरान जालिम बंसी लाल सरकार ने मुझ पर भी दफा 307 का झूठा केस बना कर महेन्द्रगढ जेल में डाल दिया था। उपाध्यक्ष महोदय, उस समय मेरे साथ जेल में अजरुदीन नाम का एक आदमी था। उसका गांव में कोई मामूली सा झगड़ा था। उसके घर के सामने वाली पार्टी ने पुलिस को पैसे दे दिए और पुलिस ने उस पर तमंचे का केस बना कर उसे टैरोरिस्ट ऐक्ट में बन्द कर दिया। वह आदमी दो साल से जेल काट रहा था। वह मेरे से यह कहा करता था कि भाई साहब मेरी एक आख नही है और आख भी वह नही है जिस आख से बन्दूक का निशाना साधा जाता है। मैं उससे कहा करता था कि आप काने नहीं हैं, यह सरकार अन्धी है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बारे में यह कहना चाहता हूं कि पिछले दिनों जो बलकार सिंह की हत्या पुलिस से हुई है, यह बड़ी गलत बात हुई है। टैरोरिस्ट सक्वैड ने क्यूका पीछा किया और उसे गोलियों से भून दिया। यह केस अम्बाला जिले– में यमुनानगर और जगाधरी के

पास का है। उपाध्यक्ष महोदय, मुनुष्य पर गोली तभी चलानी चाहिए जब अन्य कोई उपाय न रहे। उपा– ध्यक्ष महोदय, मैं यह चाहता हूं कि टैरोरिस्ट ऐक्ट और टैरोरिस्ट सैल? के बारे में बड़ा सोच–समझ कर निर्णय लिया जाए और पुलिस को अंकुश में रखा जाए। लोगों को नाजायज तंग करने के लिए इस को हथियार न बनाया जाए। इसी तरह एम० डी० पी० एस० का ऐक्ट है जिस के तहत पहले 10 ग्राम अफीम लगा कर और अब शायद माध्य किलो अफीम लगा कर 10 साल की सजा और एक लाख रुपए तक जुर्माना हो जाता है। रिवाडी का जो रेलवे स्टेशन है, वहां पर रात को पुलिस घूमती है और किसी भी अनजान आदमी को चाहे वह सिरसा का हो, राजस्थान का हो या पंजाव का हो उठा कर अने में ले जाती है और उसके सारे पैसे लूट लेती है 1 उस आदमी को बुरी तरह से पीटते हैं और जबरदस्ती दारू पिला कर दूसरे दिन कोर्ट में झूठा मुकदमा बना देते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, दारू ही नहीं बल्कि टैरोरिस्ट ऐक्ट भी लगा देते हैं। न जाने क्या–क्या जुल्म रिवाड़ी रेलवे स्टेशन पर पुलिस द्वारा किए जा रहे हैं। ऐसी कई कहानियां अखबारों में छप चुकी हैं, सरकार संवेदनशील होनी चाहिए और उसे ऐसी कहानियों का बड़ा सीरियस नोटिस ले कर सख्त से सख्त ऐंक्शन लेना चाहिए। पुलिस को इस तरह से जुल्म करने के लिए इजाजत नहीं दी जा सकती। उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार वह सरकार है जो ठीक कहती है

श्री उपाध्यक्षः यादव साहब, आप वाईन्ड अप करें।

श्री रघु यादवः उपाध्यक्ष महोदय, मुझे तो अभी बोलना है।

श्री उपाध्यक्षः आपको बोलते हुए पन्द्रह मिनट से ज्यादा हो चुके हैं।

श्री रघु यादवः उपाध्यक्ष महोदय, मुझे टाईम चाहिए। सब लोग खुल कर बोले हैं। मैंने भी काफी कुछ कहना है।

श्री उपाध्यक्षः और सदस्यों ने भी बोलना है, मेरे पास बहुत लम्बी लिस्ट है

श्री रघु यादवः उपाध्यक्ष महोदय, अब तक सब लोप आधा–आधा, घण्टा ओर एक–एक घण्टा बोले हैं, मुझे भी आप मौका दें।

श्री उपाध्यक्षः आधे घण्टे तक कोई नही बोला।

श्री रघु यादवः डाक्टर मंगल सैन, श्री रण सिंह मान और उनके बाद श्री हीरा नन्द आर्य काफी देर तक बोले हैं। आप आर्य साहब का टाईम नोट कर लीजिए, उतना ही समय मुझे दे दीजिए। कृपया मुझे बोलने दीजिए, हमारे पास और मंच ही क्या है जहां हम बोल सकते हैं।

श्री उपाध्यक्षः सैशन 8 अप्रैल तक चलना है, आपको फिर मौका मिलेगा। आप वाईन्ड अप करें।

श्री रघु यादवः उपाध्यक्ष महोदय, आप वाईन्डअप करने की बात कह रहे हैं, मैंने तो अभी शुरू ही किया है। आप हमारे अधिकारों के रक्षक हैं और आप से हमें बड़ी अपेक्षा है।

श्री उपाध्यक्षः आप दूसरों के अधिकारों के बारे में भी जानें, आप वाईन्ड अप करें।

श्री रघु यादवः उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ठीक कहती है कि लोकराज लोकलाज से चलता है। उसमें पुलिस का कम से कम उपयोग होना चाहिए। यह ऐतिहासिक तथ्य है कि मार्कोंज टैन्को और तोपों की ताकत से फिलिपीन को नहीं बचा सका, इन्दिरा गांधी ऐमरजैन्सी मैं डण्डे का नंगा इस्तेमाल करने के बावजूद रोगों के तूफान को नही रोक सकी, राजीव गांधी अपने सारे सेनाबल के बावजूद पंजाब पर काबू नहीं पा रहे हैं। इसी तरह बन्सी लाल नादिरशाही तरीकों से पुलिस का गैर जरूरी और गैर कानूनी इस्तेमाल करके भी हरियाणा के उभरे हुए सैलाब को नहीं रोक सके थे। उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस शमशान की खामोशी ला सकती है लेकिन बस्ती की शांति नहीं ला सकती। हमारी सरकार कों, पुलिस के द्वारा जो गलत और ओछी हरकतें होती हैं, लोगों को नाजायज तय किया जाता है उसका कड़ा नोटिस लेना चाहिए और जो पुलिस कर्मी दोषी पाए जाएं उनके खिलाफ सख्त कार्य वाही करनी चाहिए। मेरे विधायक बनने के बाद से अब तक रिवाड़ी में कम से कम आठ पुलिस वाले थाने में दारू पिए हुए पकड़ गए हैं। खैर, उन के खिलाफ ऐक्शन लिया गया और उन्हें

सस्पैण्ड किया नया। लेकिन ऐसी कार्यवाही होनी चाहिए कि जो कानून का रक्षक है वह भक्षक बनने की जुर्रत न करे। पुलिस का हमें कम–से–कम इस्तेमाल करना चाहिए। यहां सम्पत सिंह जी बैठे हुए हैं, वीरेन्द्र सिह जी और बनारसी दास गुप्ता जी भी बैठे हुए हैं। इमं लोग तो वे हैं जिन्होने कांग्रेस राज में पुलिस के जुल्म को, पुलिस की गैर कानूनी हरकतों को देखा है। मुझे उम्मीद है कि कम से कम इन 6 सालों में ऐसा देखने को नही मिलेगा। मैं तो कहता हु कि हमारी सरकार अब कभी जाएगी ही नहीं, हमेंशा बार–वार लौटकर आएगी और इस वक्त ये जो पांच कांग्रेसी है ये चार, तीन और दो होते हुए साफ हो जाएंगे। (हंसी)उपाध्यक्ष महोदय, मेरे मिल सम्पत सिंह जी आज गृह मन्त्री हैं। चण्डीगढ में रोजगार के अधिकार कैं लिए लड़ते हुए पुलिस द्वारा जिस तरह से इन को सरे आम सड्कों पर पीटा गया था, उसे आज तक हरियाणा के युवा भूल नही सके हैं। सम्पत सिंह जी मौका आया है कि इस पुलिस को ऐसा दुरुस्त कर दो कि वह. सपने में भी किसी के खिलाफ साजिश करने की, किसी को नाजायज तंग करने की जुर्रत न करे।

श्री उपाध्यक्षः पिटकर तो सब आए हैं, मैं भी यहां पिट कर आया हूं (विघ्न)

श्री रघु यादवः आपकी बात ठीक है। उपाध्यक्ष महोदय, मेवात हरियाणा का एक पिछड़ा क्षेत्र है। उसके लिये एक विकास बोर्ड बना है और उसके विकास हेतु विशेष कार्य वाही भी हुआ

करती है। इस सरकार ने मेवात विकास बोर्ड को और ज्यादा कारगर बनाने का एक प्रयास किया है जो कि बहुत सराहनीय। बात है। पिछड़े क्षेत्रों की तरक्की के लिये हमारी सरकार ध्यान दै रही है, यह स्वागत योग्य है।

श्री उपाध्यक्षः यादव साहब, अब आप बैठ जाइये।

श्री रघु यादवः उपाध्यक्ष महोदय, मैंने तो अभी और बाते कहनी हैं।

श्री उपाध्यक्षः आपको फिर समय मिलेगा, अब श्री मनी राम बोलगे। आपको बोलते हुए 20 मिन्ट से भी ज्यादा हो गए हैं। मैंने हाउस का समय देखना है और बाकी बोलने वाले सदस्यों का भी ध्यान रखना है।

श्री रघु यादवः उपाध्यक्ष महोदय, मैं अगर कोई गलत बात कहूं तो आप मुझे रोक दीजिए।

श्री उपाध्यक्षः गलत बात का सवाल नही है, मैंने दूसरे सदस्यों को भी बोलने के लिये समय देना है।

श्री रघु यादवः उपाध्यक्ष महोदय, कल हीरा नन्द जी एक घण्टा बोले हैं।

श्री उपाध्यक्षः आप बैठिए, अब श्री मनी राम बोलेगे।

सिंचाई तथा बिजली मन्त्री (श्री वीरेन्द्र सिंह): डिप्टी स्पीकर साहब, यह हीरा नन्द आर्य जी को कोड कर रहें हैं, वे थोड़ा अटक–अटक कर बोलते हैं इसलिये उन को टाईम ज्यादा लग गया। उपाध्यक्ष महोदय, आप इन को दो मिनट और दे दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष: ठीक है यादव साहब आप अपनी बात दो मिनट में समाप्त करें।

श्री रघु यादव: उपाध्यक्ष महोदय, मेवात, मोरनी हिल्ज और अग्रोहा के, विकास बोर्ड बनाए गए हैं। यह स्वागत योग्य कदम है लेकिन अंग्रेजों के समय से, अपनी देशभक्ति के कारण हमारा इलाका सरकार की उपेक्षा का चिरकाल से शिकार है। हमारा इलइका पिछड़ा हुआ है। अर्से से हमारे लोगों की मांग रही, है कि हमारे सर्वागीण विकास के लिये अहीरवाल विकास बोर्ड बनाया जाए। मैं सरकार दे इस मौके पर गुजारिश करूंगा कि सरकार ने जिस तरह से अन्य विकास बोर्ड बनाए हैं, उसी तरह से राज्य में क्षेत्रीय असमानता मिटाने के लिये, अहीरवाल विकास बोर्ड का गठन करे ताकि हमारे लोग जो देशभक्ति के कारण 1857 से पिछड़ेपन के कलफ की बेड़ियां पहने हुए हैं उनको भी विकास देखने. का मौका मिले, उनको भी कुछ राहत मिले। मैं बधाई दूंगा चौधरी देवी लाल जी को कि उन्होंने 23 सितम्बर को रिवाड़ी में यह घोषणा की थी कि रेवाड़ी भर्ती दफ्तर और सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। उस वायदे को पूरा किया जाए। अभी सुनने में

आया है कि जो सैनिक स्कूल पाली कें लिये मन्जूर हुआ था वह मातनहेल जा रहा है। मै आज इस मौके पर कहना चाहूंगा कि वह सैनिक स्कूल जो पाली के लिए मन्जूर हुआ था उसे पाली में ही खोले। अगर महेन्द्रगढ़ जिले का पाली स्थान पसन्द नहीं आता तो कोसली में खोल दीजिए जो रोहतक जिले का गाँव है। यह एक मिसाल गांव है जिसके हिन्दुस्तान की सेना में सबसे ज्यादा सैनिक हैं और आज भी. उस गांव में सब से ज्यादा भूतपूर्व सैनिक हैं। इसी तरह भर्ती दफ्तर के बारे में कल बात आई थी। मैं आग्रह करूंगा कि ऐमरजैन्सी कैं दौंरान बन्सीं लाल ने गुड़गांव से जो हमारा भर्ती दफ्तर उखाड़ करके कहीं और भेज दिया था उसकी जगह अगर नया भर्ती दफ्तर नहीं खुल सकता तो हमारा भर्ती दफ्तर वापिस अहीरवाल को लौटा दिया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात आती है बेरोजगारों की। मैं हरियाणा सरकार को बधाई देता हू कि उसने हरियाणा के बेरोजगारों को साक्षात्कार के लिये आने–जाने के वास्ते निःशुल्क व्यवस्था की है। यह एक अच्छा पहलू है जिस का अनुसरण इस देश की तमाम राज्य सरकारों को और रेल भाड़े के लिये केन्द्रीय सरकार को करना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे राज्य में एक अजीब स्थिति हो गई है कि जिस लड़के की इंटरव्यू कॉल निकलती है, चाहे चपडासी के लिये निकले या एच०सी०एस० अफसर के लिये निकले। काल निकलने के बाद वह परीक्षा की, इन्टरव्यू की तैयारी नही करता बल्कि एम०एल०एज० और मन्त्रियों

के चक्कर काटता है यानी वह सिफारिश ढूढता है। आज बेरोजगारों की यह सोच हो गई है, उन्हे विश्वास नहीं कि योग्यता के आधार पर भी उनका चयन हो सकता है। उन्हें लगता है कि जब तक सिफारिश नहीं मिलेगी हम चुने नहीं जायेंगे। यह सिफारिश की संस्कृति आजाद भारत में कांग्रेस के राज के दौरान पड़ी है। हमारे राज्य को देख ना चाहिए कि यह जो बेरोजगारों कों अपनी योग्यता पर से विश्वास उठ गया है और वे लोग सिफारिश ढूंढते हैं इस माहौल को हमें तोड़ना होगा। हमें बेरोजगारों में यह विश्वास पैदा करना होक कि सिफारिश तुम्हारे खिलाफ जायेगी, केवल योग्यता तुम्हारे काम आएगी। यह तभी हो सकता है कि हमारे जो रोजगार कार्यालय बने हुए हैं उन को बेरोजगार कार्यालय न रखा जाए, कारगर बनाया जाए। अब क्या होता है कि लड़की के नाम वहां दर्ज होते चले जाते हैं और रद्दी के ढेर इकट्ठे हो जाते हैं। लड़के दस–दस साल से हरियाणा में बै ठे हैं, इस देश में तो करोड़ों की संख्या में बैठे होंगे, जिन्हें इन्टरव्यू का कल्ले तक नही मिला है। नौकरियां सिफारिश के माध्यम से न दी जाएं बल्कि रोजगार कार्यालय के माध्यम से दी जाएं। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे प्रोफेसर सम्पत सिंह ने इस बार आबकारी की जों नई नीति बनाई है यानी दारू और बीयर के व्यापार की जो कुरीतियां हैं (विघ्न)ठीक है, जब इस का चौधरी रणजीत सिंह ने समर्थन कर दिया है तो मेरा तो विरोध करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। चौधरी रणजीत सिंह जी मेरे वरिष्ठ साथी है। मैं उपाध्यक्ष महोदय, सरकार सै यह अनुरोध करूंगा कि

दारु के व्यापार से जो ज्यादा लाम होने कला है, उस लाभ से जो चुनाव मे वायदा किया गया था कि हरियाणा के बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जायेगा, वह देना शुरु कर दें। उपाध्यक्ष महोदय, बुजुर्गों को पैन्शन देने मै जो दिक्कत आयी है, वह इसमें नहीं आयेगी। इनके नाम और पते नही ढूंढने पड़ेंगे। बेरोजगारी भत्ता देने के लिये उनके नाम और पते रोजगार दफ्तर से लिये जा सकते है। जैसे इन्टरव्यू में आने जाने के लिये उनको सुविधा दी गयी है, उसी तय से उनको बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाये। (घंटी)मुझे थोड़ा और बोलने दें।

12.00 बजे

श्री उपाध्यक्षः और वहुत से सदस्य बोलने थाले हैं, इसलिये अब आप बैठिए।

श्री रघु यादवः मैं एक मत और नौकरशाही के बारे में कहना चाहता हूं। कारों का किस तरह से दुरुयोग हो रहा है, यह भी देखने की बातू है। (घंटी)(व्यवधान व शोर)।

श्री उपाध्यक्षः आपको बोलते हुए 25 मिनट हो गये हैं। अब आप बैठिए।

श्री रघु यादवः आपका यदि यही आदेश हैं तो मैं आपका धन्यवाद करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री मनी राम (डबवाली अनुसूचित जाति): डिप्टी स्पीकर साहब, आपने जो गवर्नर ऐड्रैस पर मुझे बोलने के लिये टाईम दिया है, इस के लिये मैं आपका धन्यवाद करता हूं। डाक्टर मंगल सैन ने जो राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूं। वैसे तो रघु जी ने बोलने के लिये कोई बात छोड़ी ही नहीं है जो मैं कहूं लेकिन मैं भी अपने कुछ विचार रखूंगा,। स्पीकर साहब, हमारी सरकार ने इलैक्शन के दौरान लोगों से जो वायदे किये थे, उनमें से 90 प्रतिश्त तो पूरे कर दिये हैं। जैसे बुढ़ापे की पैन्शन की बात है या कर्जे को माफ करने की बात है या पढ़े–लिखे नौजवानों को इन्टरव्यू के लिये बसिज में फ्री ट्रैवलिंग की बात है। यह बड़ा ही सराहनीय काम है। जब चौधरी देवी लाल ने पहली बार सरकार बनायी थी, तब भी कुछ इस तरह के काम किये थे जैसे ओलों का मुआवजा दिया था या किसानों का, जिनके पास ट्रैक्टर्ज थे और उनमें वे सवारी नहीं बिठा सकते थे, टोकन टैक्स माफ किया था। कांग्रेस पार्टी के शासन का हमारा पार्टी की सरकार से यदि मुकाबला किया जाये तो यह पता चल जाता है। हरियाणा की जनता इसीलिये दूसरी बार भी इनको सत्ता में लायी है क्योंकि पहली बार जब चौधरी देवी लाल की सरकार थी तब इन्होंने जन हित के काम किये थे। चौधरी देवी लाल का कहना था भ्रष्टाचार बन्द और पानी का प्रबन्ध। कांग्रेस पार्टी का एक ही नारा था इनका तो 20 सूत्रीय कार्यक्रम था। यहां पर बैठे हुए मेरा ख्याल है कोई भी सदस्य उनके 20 सूत्रीय कार्यक्रम को नहीं समझ पाया होगा। फिर संजय

गांधी का 4 सूत्री कार्यक्रम था। दोनों फिगर्ज को एक साथ लिख दिया जाए तो 420 सूत्री कार्यक्रम बन जाता है। जहां तक भ्रष्टाचार की या करप्शन की बात है, लोग हमसे पूछते हैं कि क्या अब करप्शन कम हुई है? हम कहते हैं कि यह तो 40 साल की देन है। यह हमारी देन तो है नहीं, यह तो कांग्रेस पार्टी की देन है इसको खत्म करने में कुछ टाईम लगेगा। जैसे बीमारी जितनी पुरानी होगी उतनी ही ज्यादा देर तक दवाई खानी पड़ेगी। उसी तरह से करप्शन को दूर करने केलिये भी टाईम लगेगा। कांग्रेस पार्टी के एक एम० पी० साहब ने तो यहां तक कह दिया था कि जो करप्शन है, उसको किसी हद तक जायज करार दे दिया जाये। आप ही बतायें कि यह करप्शन कैसे ठीक हो सकती है। एक बार जैन मुनि का कोई सत्संग हो रहा था। वहां पर जब बिजली की बात आयी तो वहां पर अन्धेरा हो गया। वे कहने लगे कि बिजली के बल्व के ऊपर अन्धेरा होता है जबकि कहावत यह है कि दीये तले अन्धेरा। देश का ढांचा ही खराब है। 40 साल की आजादी के बाद तक यह हालत है। अगर पटेल को प्रधान मंदी बनने का मौका मिलता तो आज गांवों की यह हालत न होती। अंग्रेजों ने एक बार सर्वे करवाया था कि क्या हिन्दुस्तान में ऐसा गांव है जहां पर मानव रह सकता है। उस सर्वे की रिपोर्ट में यह लिखा हुआ है कि एक भी ऐसा गांव नहीं है जहां पर हयूमैन बीइंग रह सकता हो। आज भी 40 साल की आजादी के बाद यही हालत है। डिप्टी स्पीकर साहब, फतेहाबाद हल्के में हजरावां कला और खुर्द गांव हैं जहां पर बड़े–बड़े खड्डे हैं। उन खड्डों को भरा

जाना चाहिये। वहां की हालत यह है कि वहां एक कत्ल हो गया था और चार दिन तक लाश नहीं मिली। जब कांग्रेस की सरकार थी तो बंसीलाल ने यह ऐलान किया था कि हरियाणा में सारे गांवों को सड्कों से जोड़ दिया गया है और हर गांव को बिजली दे दी गई है। उपाध्यक्ष महोदय, आज भी मेरे हल्के में ऐसे गांव हैं जहां अभी तक सड़क नहीं पहुंची है। मारुखेड़ा से चुटाला चार किलोमीटर का एरिया है जहां पर सड़क नहीं है। शेरगढ़ से लखवाना सात–आठ किलोमीटर है वहां पर भी सड़क की जरुरत है। गंगा गांव से मुन्नावाली छः सात किलोमीटर है, ओरीवाला से झुट्टी दो किलोमीटर है। पन्नीवाला– मोरिका से देसूजोदा की सड़क भी अभी तक नहीं बनी है। उपाध्यक्ष महोदय, ऊपर मैंने जितनी सड्कों का जिक्र किया है वे अभी तक नहीं बनी हैं। इसलिये मेरी प्रार्थना कि इन सब गांवों को सड़क से जोड़ दिया जाए। उपाध्यक्ष महोदय, मेरी कांस्टिचुऐंसी में गंगा गांव है जिसकी आबादी काफी ज्यादा है लेकिन इस गांव को मुन्नावाली गांव से वाटर सप्लाई होती है जो नाम माल है। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि गंगा गांव को अलग से वाटर वर्कस दिया जाना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के डबवाली में पचास बैड का अस्पताल होना चाहिए। वहां पर कोई लड़कों का कालेज नहीं है। इसलिये मेरी सरकार से प्रार्थना है कि वहां पर कालेज जल्दी से जल्दी बनाया जाना चाहिए। मुझे बताया गया है कि कालांवाली मण्डी में अस्पताल सैंक्शन हो चुका है। मेरी कमला वर्मा बहन जी से प्रार्थना है कि इस अस्पताल को बहुत जल्दी बनाया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, गंगा, मोड़ी, गीदड़ खेड़ा गांवों में हजारों एकड़ जमीन बेकार पड़ी हुई है। अगर वहां पर कोई माइनर बना दिया जाए तो काफी आबपाशी हो सकती है। उपाध्यक्ष महोदय, हम टेल पर बैठे हुए हैं। टेल पर होने के कारण पानी की दिक्कत रहती है। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि माईनर्ज को और खालों को पक्का किया जाए। अगर वहां पर माइनर्ज और खालें पक्की हो जाएं तो डेढ़ गुणी आबपाशी हो सकती है। अगर कोई खाल टूट जाता है और हम एम० आई० टी० सी० महकमा वालों को उसे ठीक करने के लिये कहते हैं तो वे कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि एम० आई० टी० सी० को ज्यादा पैसा दिया जाना चाहिये जिससे कि वह काम पूरा कर सके। बंसी लाल के जमाने में सारा पैसा भिवानी में ही लगता रहा है लेकिन अब ऐसा नही होना चाहिए। जहां पैसा खर्च करने की जरूरत है वहीं पर खर्च होना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के में पचास गांव हैं लेकिन केवल आठ नौ हाई स्कूल हैं। इसलिये मेरी सरकार से प्रार्थना है कि ज्यादा से ज्यादा स्कूल वहां खोले जाने चाहिये 1

उपाध्यक्ष महोदय, मेरी कास्टिचुऐंसी में कपास बहुत ज्यादा होती है। लेकिन वहां पर कोई जिनिंग या स्पिनिंग मिल न होने के कारण किसान को उसकी उपज का पूरा मूल्य नहीं मिलता। 197 7— 78 में जब चौधरी देवी लाल मुख्य मन्दी थे उस वक्त वहां पर स्पिनिंग मिल लगाने की प्रोपोजल थी जो बाद में

ड्रोप कर दी गई। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि वहां पर एक स्पिनिंग मिल बनाई जाए जिससे किसानों को उनकी जिन्स का उचित भाव मिल सके। मेरी कास्टिचुऐसी डबवाली में कोई आई० टी० आई० और पौलिटैक्निक नहीं है। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि ये दोनों संस्थाएं वहां पर बोली जानी चाहियें जिससे कि वहां के लड़के ट्रेनिंग प्राप्त कर सकें और रोजगार प्राप्त कर सकें।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं बहन कमला वर्मा जी का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि मंडी डबवाली के अन्दर पोस्ट मार्टम की व्यवस्था होनी चाहिये। चौटाला में आलरैडी है। अगर वहां का डाक्टर छुट्टी पर चला जाये तो 80– 90 किलोमीटर दूर का रास्ता तय करके जाना पड़ता है जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पडता है। इसलिये मैं बहन कमला वर्मा जी से यहां हाउस में आश्वासन चाहूंगा कि मण्डी डबवाली में कब तक पोस्ट मार्टम की व्यवस्था सरकार की ओर से कर दी जाएगी.? राम बाग के पास जमीन पड़ी है किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं आयेगी। आशा है कि मेरे इस सुझाव पर सरकार गौर करेगी।

इससे अगली बात, उपाध्यक्ष महोदय, मैं बिजली के बारे में कहना चाहता हूं। मेरे इलाके के अन्दर बहुत से लोग ढानियों में रहते हैं और वहां पर बिजली का कोई प्रबन्ध नहीं है जिससे लोगों को काफी दिक्कत होती है। अतः मेरी सरकार से आपके माध्यम से यह प्रार्थना है कि इस तरह की जगहों पर जैसे कि साथ में फार्म हाउसिज भी हैं, वहां पर बिजली पहुंचाने की

व्यवस्था की जाए। अपने इन सुझावों के साथ मैं आपका धन्य–बाद करता हुआ अपना स्थान लेता हूं।

श्री टेक चन्द (नरवाना): डिप्टी स्पीकर साहब, आज देश में सभी पार्टियां किसानों की बात करती हैं, किसानों के भले की बात करती हैं लेकिन सही मायनों में हमारी इस लोकप्रिय सरकार ने, चौधरी देवी लाल जी की सरकार ने किसानों के लिये, गरीब मजदूरों के लिये जो भलाई के काम किये हैं वह सचमुच में ही सराहनीय हैं। खेती के लिये, विजनी एवं पानी के लिये हमारी सरकार ने 66 परसैन्ट से ऊपर बजट का हिस्सा किसानों के लिये, खेतीहर मजदूरों के लिये अलौट किया है। चौधरी देवी लाल जी पहले ही व्यक्ति हैं कि जिन्होंने ओलावृष्टि के कारण हुई तबाही के लिये किसानों को राहत ही है, मुआवजा दिया है और अगर किसी भी किसान का खेतिहर मजदूर का धै शर से हाथ कट गया तो उसको 10 हजार, 15 हजार का मुआवजा मार्किटिंग बोर्ड से दिल–वादा गया है। इस से बड़ा काम किसी और पहली सरकार ने आज तक नहीं किया था। इसके लिये चौधरी देवी लाल जी बधाई के पात्र हैं। आज से पहले जितनी भी सरकारें आई, वे केवल थोथे नारे ही लगाती रहीं और किसानों के साथ मुफ्त की हमदर्दी जताती रहीं कि हमने किसानों के लिये यह किया, खेतिहर मजदूरों के लिये यह किया लेकिन सही मायनों में किसानों के लिये हमारी सरकार ने, हमारे नेता ने जौ कर दिखाया है वह एक बहुत बड़ी मिसाल है। किसानों का और दूसरे गरीब तबके के

लोगों का कर्जा माफ किया गया और इसके लिये तो वे बधाई के पाव हैं। साथ ही साथ दूसरे वर्ग के जो लोग हैं, उन को और आम लोगों को बुढ़ापा पैन्शन भी दी गई है। इसके इलावा बहुत से ऐसे काम भी इस सरकार ने किये हैं जिससे हरियाणा की डिवैल्पमैन्ट हो सकेगी। सरकार की ओर से चाहे कोई हस्पताल हो, चाहे कोई स्कूल या चौपालें बनानी हों, मैचिंग ग्रान्ट्स भी दी गई हैं जिससे हरियाणा भरपूर तरक्की कर सकेगा। उपाध्यक्ष महोदय, सही मायनों में मैं यह कहूंगा कि चौधरी देवी लाल जी एक बहुत बड़े समाजवादी नेता हैं जिन्होंने कि किसानों की और दूसरे गरीब वर्गो के लोगों की भलाई के लिये बहुत कुछ किया है। किसानों के कर्जे माफ किये हैं, बुढ़ापा पैन्शन दी है, बेरोज–गारो को रोजगार दिया गया है। इससे बढ़कर समाजवादिता की और क्या मिसाल हो सकती है? आज यहां पर दूसरी पार्टियां समाजवाद की बातें करती हैं लेकिन चौधरी देवी लाल जी ने चाहे किसी भी वर्ग से कोई सम्बन्धित क्यों न हो, सभी को राहत दी है। प्रैक्टीकल काम करके दिखाये हैं। यह सचमुच सराहनीय हे। चौधरी देवी लाल जी ने गन्ने का भाव यहां के किसानों को सभी दूसरे प्रदेशों से ज्यादा दिया है। बढ़िया गन्ने को भाव 32 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से दिया गया है और इससे जो थोड़ा घटिया गन्ना था, उसका रेट 28 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से दिया गया है। सभी जो साथ लगती हमारी स्टेट्स हैं, चाहे यू०पी० हो, चाहे राजस्थान हो, सभी चे ज्यादा गन्ने का भाव इस सरकार ने दिया है लेकिन पिछली सरकार जो अपने आप को समाजवादी

कहती थी, किसानों की शुभ चिन्तक थी, उन्होंने किसानों की भलाई के लिये कुछ नहीं किया। केवल यही कहा कि यमुनानगर शूगर मिल मालिकों ने किसानों को काफी प्रोत्साहन दिया है और इसी बात को लेकर पांच करोड़ रुपए से ऊपर का जो परचेज टैक्स था, उनको माफ कर दिया गया। उपाध्यक्ष महोदय जिन–जिन लोगो का इस घोटाले में हाथ है चाहे वह सरकारी कर्मचारी है, चाहे कोई औफिसर है और चाहे वह कोई, मंत्री है उन सबके खिलाफ इन्क्वायरी कमिशन बिठाया जाए क्योंकिं उस समय उन्होने 5 करोड़ रुपए का घोटाला किया था। जो पैस्टिसाइड्ज किसानों को दी गई बताई गई है, वह वास्तव में किसानों को नहीं दी गई। इसके अलावा यह भी कहा गया था कि किसानों को प्रोत्साहन दिया गया है लेकिन वास्तव में किसानों को कोई प्रोत्साहन नहीं दिया गया। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि यह जो 5 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया था इसकी जांच करवाई जाए और इसके अन्दर जो भी कसूरवार पकड़ा जाए चाहे वह कोई सरकारी कर्मचारी है चाहे कोई सरकारी आफिसर और चाहे कितना ही बड़ा आदमी है उसको सजा दिलाई जाए। इसके साथ साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हमारी जो मौजूदा सरकार है इसने पिछले साल पैस्टिसाश्ड्ज और अल्डरिन की परचेज की थी और उस खरीद में काफी निकम्मी किस्म की दवाइयां खरीदी गई। अल्डरिन को लैबोरेटरी में टैस्टिंग के लिये भेजा गया तो वहां पर वह रिजैक्ट हो गई क्योंकि वह दवाई स्टैन्डर्ड की नहीं थी। इसलिये मैं कहना चाहूंगा कि इस मामले में हमारी सरकार के जो

भी अधिकारी हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए। कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। इस बारे में इन्क्वायरी होनी चाहिए। मैं तो यह कहूंगा कि इस तरह का काम चाहे हमारी मौजूदा सरकार के अधिकारियों ने किया है और चाहे पिछली सरकार ने किया है, उन सबके खिलाफ इक्वायरी की जानी चाहिए। कितना ही बड़ा जिम्मेदार आदमी क्यों न हो, चाहे वह पिछली सरकार का है। या मौजूदा सरकार का है, सबके खिलाफ इस तरह के मामलों की इन्क्वायरी होनी चाहिए।

इसके अलावा, मैं कहना चाहूंगा कि जहां तक गन्ने की पिड़ाई की बात है सूखा होतै हुए भी इस साल हमारे शूगर मिल्ज ने गन्ने की रिकार्ड तोड़ पिड़ाई की है। यह ठीक बात है कि इस साल गन्ने की खेती बहुत कम है। हमारे शूगर मिल्ज में जो ऐड मिनिस्ट्रेटर लगे हुए हैं और वहां पर जो ईमानदार कर्मचारी काम कर रहे हैं उन्होंने अपना जो योगदान दिया है, वहं सराहनीय है। उनकी ईमानदारी के कारण इस साल गर्म की पिछले सालों से ज्यादा पिड़ाई हुईहै। पहले चीनी में जो लौल होता था उसमें भी कमी आई है। पहले शूगर में लगभग 3 परसैन्ट तक लौसिज थे अब वे घट कर 2 परसैन्ट रह गए हैं। इस बात के लिये हमारे कोआप्रेशन मिनिस्टर वाकई में बधाई के पास हैं। इसके अलावा मैं यहं भी कहना चाहूंगा कि हमारे आदरणीय मुख्य मंत्री चौधरी देवी लाल जी ने यह फैसला भी किया है कि किसान के खेत के साथ लगती हुई पेड़ों की पहली पंक्ति से हुई आमदनी का आधा हिस्सा

उसको दिया जाएगा क्योकि पेड़ों से किसान की फसल को नुकसान होता है। उन्होंने यह कहा कि पहले मैं किसान हूं बाद में मुख्य मंत्री हूं। उन्होंने इस बात को महसूस करते हुए कि पेड़ चूंकि किसान की फसल को नुकसान पहुंचाते हैं इसलिए उनसे होने वाली आमदनी को आधा हिस्सा किसानो को दिया जाएगा। इसके अलावा इस बात का जिक्र गवर्नर साहब के अभिभाषण में भी आया हैं कि किसानों की जमीन के साथ लगते हुए पेड चाहे वह नहर के किनारों पर हैं और चाहे सडकों के किनारे–किनारे हैं उनसें होने वाली आमदनी का आधा हिस्सा उन किसानों को दिया जाएगा। इस फैसले के लिए यह सरकार बधाई की पात्र है। इसके अलावा हमारी सरकार ने एक फैसला यह भी किया है कि जो बेरोजगार नौजवान इन्टरव्यू के लिए आते हैं उनको हरियाणा रोडवेज की बसों में इन्टरव्यू पर हमने जाने के लिए फी पास दिया जाएगा। इसके लिए भी हमारी सरकार बधाई की पाव है। हमारी सरकार ने एक वायदा किया था कि बेरोजगारों को बेरोजगारी भला मिलेगा इस बारे में मैं यही कहूंगा कि अभी हमारी सरकार को बने कुछ महीने ही हुए हैं मैं उम्मीद करता हूं कि इन पांच साल के दौरान आदरणीय मुख्य मंत्री चौधरी देवी लाल जी द्रारा दिए गए इस वायदे को हमारी सरकार पूरा करेगी। जहां तक बैकवर्ड क्लासिज और हरिजनों की बात है, इस बारे में मैं कहना चाहता हूं कि पिछली सरकार ने इन बैकवर्ड क्लासिज और हरिजनों की भलाई के लिए केवल 14 करोड़ रुपए दिए थे लेकिन हमारी इस लोकप्रिय सरकार ने उस राशि को बढ़ा कर 52 करोड

रुपए कर दिया है और उससे अगले साल यह राशि 95 करोड़ रुपए करने का हमारी सरकार का विचार है। एक बात मैं हरिजनों के बारे में और कहना चाहूंगा कि हरिजनों के लिए जो ट्रक वगैरह खरीदने के लिए सर्कार ने योजना बनाई हुई है, वह केवल नाम माल है क्योंकि जो ट्रक बगैरह उनके नाम से खरीदे जाते हैं, उनको बड़े बडे सरमाएदार इस्तेमाल करते हैं और उनसे होने वार्ली मुनाफा भी उनको ही मिलता है लेकिन ट्रक हरिजनों के नाम से होते हैं। मैं इस बारे में अपनी सरकार को एक सुझाव देना चाहूंगा कि हरिजनों के लिए थी व्हीलर खरीदने के लिए योजना बनाई जाए जोकि 20 या 25 हजार तक मिल जाते हैं और जिनको वे बड़ी आसानी से खरीद सकते हैं और अपना काम चला सकते हैं। इस प्रकार की योजना हमारी सरकार को हरिजनों के लिए वनानी चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, ट्रक तो हरिजनों के नाम से खरीदा जाता है लेकिन उनका मुनाफा बड़े–बड़े लोगों की जेबों में जाता है। मेरी इस बात पर सरकार को अवश्य गौर करना चाहिए कि जो हरिजन लड़के, बैकवर्ड क्लासिज के लड़के या दूसरे गरीब लड़के बेकार घूम रहे हैं, उनको काम मिल सके। थी व्हीलर्ज के लिए अमांउट देना कोई बड़ी अमांउट नहीं है। ट्रक का लोन दिया जाना, मैं समझता हू, ठीक नहीं है क्योंकि इससे उन लोगों को कोई लाभ नहीं होता।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं कुछेक बातें कर्मचारियों के बारे में कहना चाहता हूं। हमारी सरकार को कर्मचारियों के

प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करनी चाहिए। यह ठीक है कि हमारी सरकार ने कर्मचारियों की मांगों को कंसिडर करने के लिए एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई हुई है। सर्व कर्मचारी संघ की तरफ से जो मांग पत सरकार को आया है उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार सरकार को करना चाहिए। यह भी ठीक है कि सरकार ने काफी कुछ राहतें कर्मचारियों को दी भी हैं। इस बारे में मेरी मुख्य मंत्री जी से और चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी से यह प्रार्थना है कि आप दोनों समय निकाल कर उनके साथ बैठ कर बातचीत करें ताकि आपस में जो गलतफहमी है, वह दूर हो सके।

श्री वीरेन्द्र सिंहः डिप्टी स्पीकर साहब, मैं एक मिनट इस बारे में कहन? चाहता हू। पहली बार इस सरकार ने कर्मचारियों की जितनी यूनियनें थीं, उनकी शिकायतों को लगातार दो दिनों तक सुना है। कर्मचारियों की 50 के लगभग एसोसिएशन्ज थी, जिनको हमने सुना है। हमने उनको पूरा मौका अपनी बातें कहने के लिए दिया था और यह भी कहा था कि यदि आप और कुछ कहना चाहते हैं तो आपको और भी मौका देते हैं। उन्होंने अपने सारे प्वायंटस रखे और हमने उनकी बातें बड़े ध्यान से सुनी। उनकी मांगे सरकार के विचाराधीन है। कमेटी की फिर मीटिंग जल्दी ही होने वाली है। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हमने न केवल रजिस्टर्ड यूनियनों से बातचीत की बल्कि जो यूनियनें रजि– स्टर्ड नहीं थीं, उनसे भी बातचीत की है।

श्री टेक चन्दः मेरी सरकार से इस बारे में यह भी प्रार्थना है कि कर्मचारियों के ऊपर जो धारा 311 (2)है, उसको न लागू किया जाये। यह धारा कमचारियों के सिर पर तलवार की तरह लटक रही है। कर्मचारियों को यह भय रहता है कि न जाने कब उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाये। यदि सरकार यही आश्वासन दे दे कि केन्द्र के बनाये हुए इस कानून को हरियाणा के गलत काम न करने वाले कर्मचारियों पर लागू नहीं किया जायेगा तो उन्हें इससे भी काफी राहत मिलेगी।

श्री वीरेन्द्र सिंहः उपाध्यक्ष महोदय, मैं इन्हें बताना चाहूंगा कि पिछले सैशन में मुख्य मंत्री महोदय ने स्पष्ट रूप से यह कहा था कि हरियाणा के कर्मचारियों पर संविधान की धारा 311 में जो अमैंडमैंट की है, लागू नहीं की जायेगी।

श्री टेक चन्दः यह बड़ी खुशी की बात है कि मुख्य मंत्री ने यह आश्वासन दिया हुआ है कि हरियाणा के कर्मचारियों पर संविधान की धारा 311 (2)को लागू नहीं किया जायेगा। इसके साथ ही साथ मैं यह भी सरकार से प्रार्थना करना चाहूंगा कि जिन कर्मचारियों को काम करते हुए 240 दिन से अधिक हो गए हैं उन्हें रैगुलर कर दिया जाये क्योंकि ऐसा करने से पैसे का तो कोई अतिरिक्त बोझ सरकार पर पड़ने वाला नहीं है। मुझे विश्वास है कि सरकार कर्मचारियों का हित ध्यान में रखते हुए इस बात पर सहानुभूति पूर्वक विचार करेगी। डिप्टी स्पीकर साहब सभी पार्टियां समाजवाद का जिकर करती हैं। लेकिन आज तक हमारी सरकार

के अलावा सही मायनों में किसी भी सरकार ने समाजवाद की तरफ कदम नहीं बढ़ाया है। हमारी सरकार ने कर्जे भी माफ किए है और हरिजनों, पिछड़े वर्गों और गरीब लोगों को मैचिंग ग्रान्ट भी काफी माता में कई स्कीमों के तहत दी है। हमारी सरकार ने स्टुडैन्टस के लिए भी काफी कुछ किया है। मैं यह कहता हूं कि सही मायनों में हमारी सरकार ने समाजवाद की तरफ कदम बढ़ाया है। अब मैं एक बात ऐजूकेशन के बारे में कहना चाहूंगा। किसी भी समाज के उत्थान के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। कई स्थानों पर तो सरकार ने शहरों में मौडल स्कूल खोले हुए हैं लेकिन देहात की तरफ एजूकेशन के मामले में उतना ध्यान नहीं दिया जितना दिया जाना चाहिए था। भाई। जगननाथ जी, ठीक ही कह रहे थे कि जो सुविधा शिक्षा के लिए शहरों में प्रदान की जा रही हैं यदि वही शिक्षा की सुविधाएं देहात के बच्चों के लिए दे दी जाएं तो फिर पता चल पायेका कि धनी लोगों छ कितने बच्चे आई० ए० एस० आदि बन पाते हैं और गरीब लोगों के कितने बच्चे आई० ए० एस० आदि बन पाते हैं। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि देहात के बच्चों को और शहर के बच्चों को बराबर की सुविधाएं शिक्षा के संबंध में मिलनी चाहिए। यदि ऐसा कर दिया जाये तो बच्चों में हीन भावना भी नहीं आयेगी और वे अपनी पढ़ाई भी अच्छी प्रकार से कर पायेगे। सभी बच्चों के लिए एक जैसे ही स्कूल होने चाहिएं। उपाध्यक्ष महोदय, दिमाग किसानों और मजदूरों के बच्चों में भी होता है। उन्हें भी अवसर दिया जाये क्योंकि उनके बच्चे मेहनतकश ज्यादा होते हैं। अमीरों की बजाए

उन गरीबों के बच्चे अच्छी पोजीशन हासिल कर सकते हैं। आज बड़ी–बडी पोस्टों पर बड़े वर्ग के लोग बैठे हुए हैं। यह किसान और मजदूरों के वच्चों के साथ बड़ी डिस्क्रिमिनेशन है। आज राज अफसरशाही का चल खा है। गरीब लोगों, किसानों और मजदूर व मेहनतकशों को भी राज करने का मौका मिलना चाहिए। उनके लिए शिक्षा की भी अपर्चुनिटी होनी चाहिए। शिक्षा की अपर्चुनिटी एक जैसी होगी तो वे भी आगे आ सकेंगे। उपाध्यक्ष महोदय इन शब्दों के साथ मैं इस अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव आया है उसका समर्थन करता हूं।

चौधरी महेन्द्र प्रताप सिंह (मेवला महराजपुर): उपाध्यक्ष महोदय, दो दिन पहले माननीय गवर्नर साहब ने जो अभिभाषण सदन में दिया था और जिस पर डाक्टर मंगल सैन जी ने धन्यवाद का प्रस्ताव रखा था, उस पर हाउस में चर्चा हो रही है। सब से पहले मैं अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से और हरियाणा की जनता की तरफ से बरारी साहब का धन्यवाद करता हूं क्योंकि उन्होंने हरियाणा की सेवा करने का अवसर मिलने पर हरियाणा प्रदेश की खुशहाली व विकास की कामना की है।

उपाध्यक्ष महोदय, जनता का फैसला ईश्वर का फैसला होता है, मैं ऐसा मान कर चलता हूं। जनता ने प्रजातांत्रिक ढांचे में कई बार फैसला दिया है। आगे भी जैसा समय आयेगा वैसा फैसला जनता देगी। (शोर एवं व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, दो दिन से गवर्नर साहब के अभिभाषण पर चर्चा चल रही है। इस अभिभाषण में सरकार की पिछले वर्ष की उपलब्धियां और अगले वर्ष की नीति निर्धारण या प्रोग्राम का वर्णन होता है या उसका लेखा–जोखा होता है। दो दिन की बहस में एक खास बात जो सामने आई है वह है जैसे देहाती औरतों की मिसाल है कि मेरा अच्छा या तेरा अच्छा। इस प्रकार से वे अपनी –अपनी गाथायें सुनाती हैं। उपाध्यक्ष महोदय, जिस पार्टी या व्यक्ति के हाथ में सत्ता होती है उससे जनता अपने विकास और अच्छे समाज की अपेक्षा करती है और सरकार बैसा करने की अपनी तरफ से कोशिश भी करती है। सत्त में रहते हुए कई कमियां भी आती हैं। इसलिए सरकार हर व्यक्ति की अपेक्षा पूरी नहीं कर सकती और न ऐसा मुमकिन भी है।

सत्ता पक्ष की ओर से बोलने वालो ने यहां ज्यादातर सिर्फ एक ही बात पर जोर दिया हे कि चु नाव के बाद 8– 9 महीने के अर्से में ही सरकार ने सब कुछ कर दिया। जो जनता से वायदे किये थे, जनता की जो तकलीफें थी, उन सब को हल कर दिया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसके खिलाफ तो नहीं कहना चाहता क्योंकि जन सेवा व प्रदेश का विकास तो सरकार का कर्तव्य भी है। उसने समाज कें लिए कुछ अच्छे फैसले भी लिए होगे। हर सरकार अपने वायदे के मुताबिक जो जिम्मेदारिया जनता उसे सौंपती है, उन्हें पूरा करने की कोशिश करती है। जैसे हमारे साथी कह रहे थे कि जो अच्छे काम हैं, उनको मान्यता मिलनी

चाहिए। इस बारे में मैं भी अगर कुछ अच्छे कामों की हिमायत कर दूं तो कोई गलत बात नहीं होगी। अखबार में पढ़ा कि सरकार ने एक फैसला किया है कि प्रदेश में जो थी व्हीलर और फोर व्हीलर चल रहे थे, पहले उनके लाईसैन्स की व्यवस्था नहीं थी और वे प्र शा सन की तरफ से तकलीफ झेल रहे थे। अब जो उनको लाईसैन्स देने की व्यवस्था की गई है, हमें उसकी हिमायत करनी चाहिए। इस के बाद मैं पैशन के बारे में कहना चाहता हू। इसमें अपवाद हो सकता है। पैंशन व ऋण माफी का वायदा लोगों को लुभाने का बहुत बड़ा वायदा था। पैशन सम्बन्धी वायदे को पूरा करने की कोशिश इस सरकार की तरफ से की गई है। स्वाभाविक एं कि जो भी काम शुरू किया जा ता है उसमें कुछ अड़चने भी आती हैं। (शोर)उपाध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त जो भी उपलब्हिग्यों का राग अलापा गया है उससे जर्मन के गोबल्ज की याद आ जाती है। उनका कद्रुना था कि यदि एक झूठ को सौ बार रिपीट किया जाए तो वह सत्य प्रतीत होने लगता है। अतः मेरे साथी उसका अनुसरण कर रहे हैं और इस कहा वत को चरितार्थ कर रहे हैं। (शोर)

श्री कैलाश चन्द शर्माः उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायन्ट आफ आर्डर है। मैं यह जानना चाहता हूं कि यह कौन से झूठ की बात कर रहे हैं। (शोर)

श्री उपाध्यक्षः आप बैठें, यह कोई प्वायंट आफ आर्डर नहीं बै।

उपमुख्य मन्त्री (श्री बनारसी दास गुप्ता): उपाध्यक्ष महोदय, झूठ शब्द अन– पार्लियामैन्टरी है।

चौधरी महेन्द्र प्रताप सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, गोवल्ज ने जो कहा था मैंने केवल वही कहा है। मैंने कोई अनपार्लियामैंट्री बात नहीं कही। इसलिए इस शब्द को कार्यवाही से न निकाला जाए। उपाध्यक्ष महोदय, कल डाक्टर साहब ने दरिया पुर काण्ड का जिक्र किया। मैं इस बात का इस लिए जिक्र कर रहा हूं किं पिछले सैशन में जब यह दुखद घटना घटी थी तो सत्तापक्ष की तरफ से इतना गलत इल्जाम लगाया गया था कि यह सारा काण्ड कांग्रेस ने या कांग्रेस के कुछ मन्त्रियों ने करवाया है। लेकिन शुक्र है कि इस ऐड्रैस में वह चीज छोड़ दी गई है। ठीक है इस बारे में पुलिस की कार्यकुशलता को दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने बड़ी तत्परता व खूबी के साथ मुलजिमों को पकड़ा है। अगर यह केस ट्रेस नहीं होता तो शायद आज भी झूठ को दोहराया जाता कि यह सब कुछ कांग्रेस करवा रही है। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह खुशी होती है कि सत्तापक्ष शर्म तो महसूस करता है लेकिन देर से। (विघ्न)मेरे साथी श्री वीरेन्द्र सिंह जी पंजाब की बात कर रहे हैं। वीरेन्द्र सिंह जी, आप तो काबिल आदमी हैं। उस वक्त सरकार का जो असली कर्त्तव्य था, उस तरफ से आख बन्द कर ली गई और इसको एक तरफ मोड़ने की कोशिश की गई। यह इतना अहम क्राण्ड है जिसका वास्ता देश की सुरक्षा से है है यह एक शर्म की बात है। आज पंजाब के हालात सब के सामने हैं। इस पंजाब की

हालत के पीछे क्या साजिश है, दुनिया के कुछ देशों की इस देश के साथ क्या साजिश हो रही है? उसको कभी नहीं कहा गया बल्कि उसको राजनैतिक रूप दे कर बिगाड़ा यया। इस का सबूत इससे ज्यादा कोई नहीं हो सकता कि स्वर्गीय श्रीमती इन्दिरा गांधी ने इस देश की अखण्डता के लिए अपना बलिदान दे दिया। (शोर)यह सिर्फ आपका स्वार्थपूर्ण ख्याल हो सकता है लेकिन इससे इन्कार नहीं किया जा सकता।

श्री वीरेन्द्र सिहः उपाध्यक्ष महोदय, सैन्टर में इनकी सरकार है। इन को पता होनो चाहिए कि किस विदेशी ताकत को हाथ है और कौन लोग इस देश को तोड़ने जा रहे हें। ये उनेका नाम क्यों नहीं लेते?

चौधरी महेन्द्र प्रताप सिंहः पंजाब में उस समय कांग्रेस सरकार नहीं थी लेकिन तत्कालीन सरकार ने विदेशी ताकत का हाथ माना है। मुझे इस बात का जिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह चीज अखबारों में आ चुकी है। इसका सबूत इससे ज्यादा और कोई नहीं हो सकता क्योंकि उस समय में बरनाला सरकार नें, जो कांग्रेस की सरकार नहीं थी, भी अपने व्यानों में कहीं था कि इसके पीछे विदेशी ताकत का हाथ है। तो इससे बड़ा और कोई सबूत नहीं हो सकता (शोर)मुझे अफसोस है कि आप इसके महत्व को स्वार्थ वश नहीं समझ रहे। (शोर)

श्री वीरेन्द्र सिंहः लोक सभा के चुनाव आ जाने दो, फिर देखेंगे।

चौधरी महेन्द्र प्रताप सिंहः चुनाव तो 1977 में भी आये थे, 1982 मे भी आये थे 1987 में भी आए थे और आगे भी आते रहेंगे और जनता जनार्दन अपना फैसला भी करती रहेगी। (शोर एवं विघ्न)

श्री वीरेन्द्र सिंहः आप तो नहीं चाहते कि चुनाव हों, लेकिन जनता लाएगी।

चौधरी महेन्द्र प्रताप सिंहः हम तो प्रजातन्तूर में विश्वास रखते हैं।

श्री बीरेन्द्र सिंहः आप प्रजातन्त्र में नहीं आप तो ऐमरजैन्सी में विश्वास रखते हैं।

चौधरी महेन्द्र प्रताप सिंहः ऐमरजैन्सी का जहां तक ताल्लुक है, हो सकता है वह देश के हित में लगाई गई हो और आप जैसे लोग जो देश के हित को नहीं समझते, हो सकता है उनके लिए ऐसा किया गया हो। (शोर)

श्री तैयब हुसैनः उपाध्यक्ष महोदय, इनको मैम्बर साहब की बात सुनने का कुछ मादा होना चाहिए।

श्री बनारसी दास गुप्ताः उपाध्यक्ष महोदय, श्री तैयब साहब ने कहा कि इन में सुनने का मादा होना चाहिए। हम तो इन

की बात बड़े आराम से सुन रहे थे। हम हैल्दी क्रिटिसिज्म भी सुनना चाहते हैं। लेकिन ये देशभक्ति का ठेका खुद लेना चाहें और हमें कहें कि हमें देश का ध्यान नहीं है, इस बात को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। डिप्टी स्पीकर साहब, हम इनकी बात को जरूर सुनना चाहेंगे लेकिन यह ठीक ढंग से बोलें, इन की बात सुनने में किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी।

चौधरी महेन्द्र प्रताप सिंहः उपाध्यक्ष महोदय, मैं जो भी बोल रहा हूं, अपने विवेक से सत्य ही बोल रहा हूं। मैं यह दावा नहीं करता कि मैं बहुत सत्यवादी हूं। ऐमरजैंसी की बात का जहां तक ताल्लुक है, गुप्ता जी भी उन दिनों हमारे साथ थे और मुख्य मन्त्री थे। उनको इस मामले में ज्यादा मालूम होगा।

श्री बनारसी दास गुप्ताः उपाध्यक्ष महोदय, हालात बदलते रहते हैं। जो कांग्रेस आजादी से पहले थी, वह बाद में नहीं रही। जो नेहरु जी के वक्त में थी, वह आगे नहीं रही। जो कुछ रही सही थी, उसकी कसर चौधरी महेन्द्र प्रताप सिंह जैसे लोगों को शामिल करके पूरी कर दी गयी।

श्री वीरेन्द्र सिंहः यह तो समय–समय की बात है। उस वक्त वह इधर थे और अब उधर हैं।

चौधरी महेन्द्र प्रताप सिंहः उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर कर्जों की माफी का राग अलापा गया और यह कहा गया कि सरकार ने कर्जो का वायदा पूरा कर दिया है।

श्री मंगल सैनः उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बोलने को राग अलापना कह रहे हैं। इनके बोलने को क्या हम सारंगी बजाना कहेंगे। (हंसी)..

चौधरी महेन्द्र प्रताप सिंहः उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर बहुत ढिंढोरा पीटा गया। अगर मैं यह बात केहू तो गलत नहीं होगा कि हरियाणा की जनता ने .... इनको सला सौंपी है। मैं यह बात दावे के साथ कह सकता हूं। जनता आज महसूस कर रही है। (व्यवंधान व शोर)

श्री वीरेन्द्र सिंहः आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। डिप्टी स्पीकर साहब, हरियाणा प्रदेश की जनता को या इस देश की जनता को ऐसा हल्का समझना या जैसे मेरे दोस्त ने समझा है और उसैको बदनाम करना बहुत ही बुरी धात है। जनता संघर्ष पर उतरी। बेइन्साफी के खिलाफ संघर्ष पर उतरी। पानी छिन रहा था हमारा इलाका छीना जा रहा था। उस पर जनता ने संघर्ष किया। बगावत की और इनको ठिकाने लगा दिया। इनकी यह बात ऐक्सपंज होनी चाहिये कि जनता ने .... में आकर सरकार को बदला है। यह जनता की बेइज्जती है।

श्री उपाध्यक्षः ठीक है, वे शब्द ऐक्सपंज कर दिये जायें।

चौधरी महेन्द्र प्रताप सिहंः मेरे विचार में जनता ने इनके नारों की वजह से इन पर विश्वास किया। मैंने कोई यहां पर अन–पीलियामैंट्री वाहे नहीं कही है। ऐसा कुहना कि जनता ने .....

..... इनको सत्ता सौंपी है, अनपार्लियामैंट्री नहीं है। मैंनें जनता का कोई अपमान नहीं किया है बल्कि आपने जनता के साथ विश्वासघात किया है। यह सत्य है और जनता यह महसूस कर रही है। (व्यवधान व शोर)

श्री मंगल सैनः आन ए प्वांवट आफ आर्डर, सर मैं आपकी रूलिंग चाहूंगा कि एक आनरेबल मैम्बर इस हाउस मैं यह कह रहा है कि जनता के साथ ..... किया गया है। अगर मैं भूलता नहीं हूं तो वही आनरेबल मैम्बर 1982 में हल जोतते किसान के निशान पर जीत कर आये थे लेकिन बाद में खूनी पंजे में शामिल हो गये। यह विश्वासघात उन्होंने किया था या हमने विश्वासघात किया है?

चौधरी महेन्द्र प्रताप सिंहः जो कुछ डाक्टर साहब ने कहा है उस बारे में मैं यह कहना चाहूंगा कि जहां तक दल–बदल का ताल्लुक है, वह तो आपकी ही पैदावार है। उसके लिये मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। (व्यवधान व शोर)मुझे सुन लो कि मैं क्या कहने जा रहा हूं।

श्री वीरेन्द्र सिंहः अगर आप इतने ही सत्यवादी हो तो कहो कि मैं दोषी हूं।

चौधरी महेन्द्र प्रताप सिंहः मैं यह कहीं नहीं कहता कि मैं पूर्ण सत्यवादी हूं। लेकिन ज्य का पक्षधर हूं। जहां तक दल–बदल का ताल्लुक है, सूझे इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं

कहना है। सन 1977 में भी मैंने इलैक्शन लड़ा था। 1982 में मैं आजाद उम्मीदवार कैं रूप में इलैक्शन लड़ने जा रहा था। मुझे इन साथियों ने स्पोर्ट किया। इस में कोई दो राय नहीं हैं। जहां तक 1982 का ताल्लुक है, उस समय कांग्रेस की हवा थी, इसके बावजूद मुझे जनता ने जिता दिया। आज हवा कांग्रेस के विपरीत थी। लेकिन जनता ने फिर कांग्रेस को जिताया है। आप अच्छी तरह से फैसला कर सकते हो कि मेरा फैसला सही था या गलत। जनता का फैसला सर्वोपरि होता है और यह जीत जनता की जीत थी। उपाध्यक्ष महोदय, आप विधान सभा भंग करवा कर फिर चुनाव करवा लो, अगर आप आधी भी सीटें ले जाओ तो बड़ी हिम्मत होगी। (शोर एवं व्यवधान).

श्री वीरेन्द्र सिंहः आप पार्लियामैंट भग करवा दो। हरियाणा में दो सीटें खाली हैं। उनके चुनाव ड्यु हैं, वे चुनाव करवा लो। (शोर एवं व्यवधान)

चौधरी महेन्द्र प्रताप सिंहः उपाध्यक्ष महोदय, मैं कर्जो के माफ करने की बाबत कह रहा था। आन दि फ्लोर आफ दि हाउस पिछली बार भी माना था और अथ भी माना है कि तकरीबन 44–45 करोड रुपया सहकारी विभाग का माफ किया गया है। (शोंर एवं व्ययधान)

श्री वीरेन्द्र सिंहः 244 करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया गयी है।

चौधरी महेन्द्र प्रताप सिंहः उपाध्यक्ष महोदय, उस वक्त जनता से कहाँ गया था कि इलैक्शन जीतने के बाद 1200 करोड रुपए की कर्जा का किया जाएगा और बाद में करीब 500 करोड़ माफ करने के लिए कहा। (शार एवं व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र सिंहः हमने नही कहा था। (शोर एवं व्यवधान)हम सब का माफ करेंगे सिर्फ भजन लाल और बुल्ले शाह का नहीं करेंगे। (शोर एवं व्यधधान)

श्री बलबीर पाल शाहः आप आप मुझे बताना कितना कर्जा मेरे जिम्मे है? मैं आज ही पेमैन्ट करकें जाऊगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र सिंहः आ जाना। तीन बजे ले लूंगा। आज हिसाब करके जाना। (शोर एवं व्यवधान)

श्री बलबीर पाल शाहः भजन लाल कीं बात न करो। मेरी शत करो। मैं सारा देकर जाऊंगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र सिंहः आपने तो कम्पनसेशन लैने के लिए झूठी ऐप्लीकेशंज दी हुई हैं। सारा रिकार्ड है। सारी पोल खोल दी जाएगी। (शोर ऐब व्यवधान)

चौधरी महेन्द्र प्रताप सिंहः मुझे तो अपनी बात कहने दे। अगर कोई सही बात है तो बेशक हाउस में कहें। लेकिन मुझे तौ

बोलने दें (शोर एवं व्यवधान)। मुझे तो थोड़ा सा ही टाईम मिलॉ है। मुझे अपनी बात तो कहने दे।

श्री उपाध्यक्षः आप बोलिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र सिंहः फर्जी जमीन का मालिक बन गया और कम्पनशसेन के लिए ऐप्लीकेशंज दे दी। मेरे पास बहुत सारा मसाला है। मैं सारी बातें बताऊंगा कि कांग्रेस पार्टी कैसी होगी जिसका प्रेजीडैन्ट ऐसा है।

राजस्व मन्त्री (श्री सूरज भान): इस फाईल में सारा कुछ है। जमीन के कम्पनसैशन के लिऐ झूठी ऐप्लीकेशन दी। आपने झूठे बयान दिए हुए हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र सिंहः उपाध्यक्ष महोदय, इनका नाम धै बलबीर शाह लेकिन इनको लौग बुल्ले शाह कहते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणजीत सिंहः आन ए प्वायंट ओफ आर्डर 1 डिप्टी स्पीकर साहब, अभी चर्चा चल रही थी और श्री वीरेन्द्र सिंह ने कहा कि झूठे ऐफीडैविट दे रखे हैं और यही बात सूरज भग्न जी ने भी कही। हमें इन बातों से कुछ लेना देना नहीं कि किसी ने क्या दे रखा है। (शोर एवं व्यवधान)लेकिन इस सदन में अगर अननरेबल मैम्बर इस ढंग से बात करें तो उससे हम पीड़ित हैं। इस ढंग की प्रैक्टिस बन्द होनी चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)झूठे

ऐफीडैविट नहीं दिए जाने चाहिए। बाकी बातों से हमें कुछ लेना देना नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र सिंहः जमीन का मालिक कोई और और ये झूठा ऐफीडैविट देकर मालिक बनते हैं और कम्पसेशन के लिए ऐप्लीकेशन देते हैं। फाईल मेरे पास है सब पोल खोल दूंगा। (शोर एवं व्यवधान)

चौधरी महेन्द्र प्रताप सिंहः मुझे तो चोलने दीजिए। जिससे जो लेना खोलना है, वह लेते खोलते रहना। मुझे अपनी बाते तो कहने दो (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्षः आप बोले।

चौधरी महेन्द्र प्रताप सिंहः आप इनको चुप कराइए।

श्री उषाध्यक्षः आर्डर प्लीज।

श्री हीरा नन्द आर्यः उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि चौधरी सूरज भाल और श्री वीरेन्द्र सिंह ने बलबीर पाल शाह के बारे में कहा कि हम यहां सब कुछ बता देंगे। मैं कहता हूं कि वेदा क्या देंगे इनके काले कारनामों का यहां पर पर्दाफाश करना चाहिये। (शोर)

चौधरी महेन्द्र प्रताप सिंहः उपाध्यक्ष महोदय, काले कारनामों का फैसव्य तो जनता के हाथ में ..है। जनता ने आपको कई बम्र हिखाये और आगे भी देखते जाओगे इस बात का फैसला

आपको जनता के– ऊपर छोड़ देना चाहिये। मेरे विचार में इस पर ज्यादा डिस्कलन की आवश्कक्ता नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि इन्होंने कहा 227 करोड़ या 240 करौड रुपये के कर्जे माफ किये गये हैं। यह बिल्कुल गल्त कह रहे है। आज हम अगर जनता मैं जाकर देखें तो पता लगेगा। जनता हताश व भ्रामक स्थिति में है। इधर नोटिस दिये जा रहे है और उधर दूसरी तरफ बैंकस लोगों को कर्जा नहीं दे रहे हैं। जहां तक 227 करोड़ रुपये कें कर्जे का सवाल है, उसमें से 45 करोड रुपया कोआप्रेटिव बैकों का है। 12 करोड़ रुपया, जैसा कि मैंने अखबरों में पढ़ा है, वह हरिजन कल्याण निगम या जो हरिजन बोर्ड हैं, उनकी तरफ से हरिजनों को मिला है और 12 करोड़ रुपया ट्रैक्टज का हए जोकि कोआप्रेटिव बैंक्स या दूसरे बैंकों से मित्रा है और 162 करोड़ रुपया व्यवसायिक बैंक्स का मिला है। यह पैसा इनका नहीं है बल्कि देश की जनता का है और उसी को यह पैसा माफ करने का हक है। प्रदेश सरकार को हक ही नहीं है? जनता को भरमा रहे हैं और फिर ये लोग इस तरह के बहाने लगा रहे हैं कि सैन्टर इस काम मैं अड़चन डाल रही है औंर कई बार यहां पर भी कहा गया कि इसके लिये राजीव जी से इजाजत दिलवा दीजियेगा। उपाध्यक्ष महोदय, राजीव जी ऐसे गल्त कामों के लिये, जिससे देश की व्यवस्था ही बिगड़ जाए, सारे देश का विकास ही रुक जाए, खत्म हो जाए, यह फैसला कैसे कर सकते हैं? (शोर

एवं व्यवधान)उपाध्यक्ष महोदय, इनको मेरी बातें ध्यान से और आराम से सुननी चाहिये। हमने भी इनकी सारी बातें आराम से सुनीं हैं। साथ में अब ये लोग यह नारा भी दे रहे हैं कि हमें केन्द्र में हकूमत दो, हम सब कुछ कर दिखायेंगे इन्हें भी माफ कर देंगे। यह कभी होने वाला नहीं है। फिर ये कहते हैं कि देश की आर्थिक व्यवस्था ठीक नहीं है उसे भी सरकार ने बिगाड़ कर रख दिया है और कुछ बाहर की हम मदद चाह रहे हैं और वह मिल नहीं रही है। तो इस तरीके से कहने के लिये एक न एक हथियार, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए ये छोड़ते रहते हैं ताकि लोगों को, इस हरियाणा की भोली भाली जनता को गुमराह कर सके। (शोर एवं व्यवधान)मैं इसके खिलाफ नहीं हूं लेकिन मुझे बड़े दु:ख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज किसान और मजदूर की हालत हरियाणा के अन्दर जितनी अच्छी होनो चाहिये थी, वह नहीं है। किसान बूरी तरह से इस सरकार के राज में परेशान है, दु:खी है और कर्जों के नीचे दबा पड़ा णै। केवल इस थोथी सरकार के गल्त कामों के कारण, आश्वासनों के कारण आज गरीब किसान और मजदूर की यह हालत हो रही है कि वह अपने को असहाय महसूस कर रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी बात यहां पर एस० वाई० एल० के पानी के बारे मैं कही गई और यह भी कहा गया कि इसके लिये सरकार अपनी तरफ से भरसक कोशिश कर रही है और सीथ में 1970 के एवार्ड का भी जिकर किया न या। उपाध्यक्ष महोदय, मैं अखबारों की बात कह रहा हू जोकि मेंने पढा है। जहां तक नहर का ताल्लुक है, हरियाणा सस्कार, केन्द्र सरकार इसके

पानी के लिये हमेशा ही कोशिश करती रही है और इस बात की डिसकशन फलौर औफ दि हाउस पर भी होती रही है कि जो पानी जाया जा रहा है वह. हरियाणा की प्यासी धरती को मिलना चाहिये जो कि हरियाणा के किसान की लाईफ लाइन है और इसके लिये हमारी काग्रेंस सरकार भरसक प्रयत्न करती भी रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है। इसका एक सबूत आप सब लोगों के सामने, हरियाणा की जनता के सामने था जबकि श्रीमती इंदिरा गाली ने नहर खोदने के लिये कस्सी से कट लगाया था। उपाध्यक्ष महोदय, जिस वक्त पं जाव और हरियाणा का बंटवारा हुआ उस वक्त पानी और टैरीटरी के मुतल्लिक शाह कमिशन मुकरर्र हुआ था। उसने अपने फैसले में चण्डीगढ हरियाणा को हिया था। उस फैसले पर काफी आन्दोलन शु रू हुए। मैं यह बात अखबारों से पड़ी हुई कहता हूं और ये बड़े बडे लीडरों के बयान हैं। उस फैसले के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने जो अवार्ड दिया था उस अवार्ड को जो मेरे साथी आज उधर बैठे हैं इन्होंने नहीं माना लेकिन अइज मेरे वही सा थी यह बात कहते हैं कि श्रीमती इंदरा गांधी जी के अवार्ड को लागू किया जाए यह रिकार्ड की बात है। यहां पर इस नई सरकार ने जो कार्य किए है उनके बारे में भी काफी चर्चा की गई है और जो पिछली सरकार ने कार्य किए हैं उनकी भी काफी चर्चा की गई है यानी दोनों सरकारों के कायों की काफी हद तक तुलना की गई है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जिस वक्त हरियाणा बना उस वक्त हरियाणा की क्या हालत थी? उस समय यह कहा जाता था कि

हरियाण अपने अस्तित्व को कैसे कायम रख पाएगा और अपने कर्मचारियों की तनख्ताह भी नही दे पाये गा। यहां पर न इंडस्ट्रीज थी, न बिजली थी, न ही सडके थीं और व ही कोई खास ऐजूकेशन थी यानी हरियाणा उस समय हर क्षेत्र में पिछड़ा हुआ था। लेकिन आज वही हरियाणा है जो पहले 11 वे नम्बर पर होता था आज वह दूसरे नम्बर पर है। हरियाणा आज डिवैल्पमैंट के हिसाब से दूसरे नम्बर पर इसलिए णै क्योंकि चौधरी बंसी लाल जी ने हरियाणा की तरक्की के लिए डिवैल्पमैंट के बहुत काम किए और उसके बाद आने वाले मुख्य मंत्रियों ने उन डिवैल्पमैंट के कार्यो को बरकरार रखा है। आज हरियाणा प्रान्त के हर गांव में बिजली है, हर गांव को सड़क के माथ जोड़ा हुआ है। इस सरकार ने यहां आन दि फलौर आफ दि हाउस यह माना है कि आज हरियाणा के अन्दर 98 परसैंट यच्च सउको से जु डे हुए हैं और 77700 छोटी इंडस्ट्रीज भी हरियाणा के अन्दर मौजूद हैं। इन सभी बातों का श्रेय चौधरी बंसी लाल जी और उनके बाद आने वाले मुख्य मन्त्रियों को जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, यह कहना कि पिछली सरकार ने क्या किया, क्या नहीं किया, इस बारे में तो इस देश और प्रदेश की जनता जानती है कि हरियाणा ने कितनी तरक्की की है और किस मुख्य मंत्री के समय में की है। (घंटी)उपाध्यक्ष महोदय, भै एक सुझाव देना चाहूंगा और दो मिनट में ही अपनी बात समाप्तं कर दूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, यह किसानो की हितैषी कहलाने वाली सरकार है इसने किसानो को बिजली और पानी के लिए केवल 285 करोड़ रुपए रखे हैं जबकि पिछली

सरकार ने 285 करोड रुपए की बजाय 357 करोड रुपए रखे थे। इस बात का गवर्नर साहब के ऐडैरस सें पता लगता है। अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते है कि कौन सी सरकार किसानों की हमदर्द हैं और कौन सी नही है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात यह कहना चाहेगा कि पिछली बार यहां पर स्वतंत्रता संग्राम की 40वी वर्षगांठ मनाई गई थी और उसमें देश और प्रदेश को मुख्तीलफ जगहों से शहीदो के स्थानों से मिट्टी लाई गई थी। इस बारे में मैं माननीय वित्त मंत्री श्री गुप्ता जी से कहना चाहूंगा क्योंकि उस समय हमें इस बारे में कुछ कहने को मौका नही मिल सका। जाने अनजाने में कुछ जगह ऐसी रह गई हैं जहा से मिट्टी नहीं लड़ाई गई। यदि मुझे उस समय कहने का मौका मिलता तो मैं आपको उन जगहों के बारे में बता देता जहां से शहीदों की मिट्टी यहां पर नही लाई गई। मैं अब बता देना चाहता हूं न डिस्ट्रिक्ट गजटियर मे देखें। उसमें उनके नाम मौजूद है। सोहनी व मेवाती फेल के ऐसे गांव है जहां पर उन लोगों को फांसी लगाई गई थी दफनाया नया था या दाह संस्कार किया गया था। उनके स्थानों की मिट्टी यहां पर नहीं लाई गई। मैं माननीय गुप्ता की से दरख्वास्त करूंगा कि आप इसके लिए एक कमेटी बनाए जो इस बारे में जांच बारे और उन शहीदों को पूरी तरह से मान दें और जिनकी जाने–अनजाने में उपेक्षा हुई हैं उनके भी स्मारक आदि बनाये जायें।

श्री बनारसी दास गुप्ताः आप इस वारे मे लिखे करके दो दें हेंमें विचार कर लेंगे वैसे इस काम के लिए कमेटी पहले ही बनी हुई है।

13.00 बजे

चौधरी महेन्द्र प्रताप सिंहः उपाध्यक्ष महोदय, आखिरी बात कहते हुए मैं अपनी जगह लूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, चुनावों के समग्र चौधरी बंसी लाल जी कहा करते थे कि किसी की भैस गुम हो गई। वहू आदमी अपने बच्चे को साथ ले जा कर किसी देवता की समाध सा पास पहुचा और कहने लगा कि यदि मेरी भैस मिल जाएगी तो मै एक थन का दूध तुम्हारे पर चढ़ा दूंगा। दूसरे देवता के पास गया तो कहने लगा कि मेरी भैस मिल जाये तो मैं एक थन का ढूध तुम्हारे ऊपर चढा दूंगा। इसी प्रकार से तीसरे देवता और चौथे देवता के पास जा कर कहने लगा। जब यह होता नजर आया तो बच्चा अपने बाप से बोला यदि आपने चारों थनों का दूव इनको ही देना है तो सिर भैस तलाश करने की क्या आवश्यकता है? इस पर बच्चे कार बाप कहने लगा कि पहले भैंस मिल जाने दे उसके बाद दूध देना न देना तो मेरा काम है। (विघ्न)यह कहावत आज हरियाणा की जनता पर लागू हो रही है। जनता ने इन्हें सत्ता सौंपी है। कटनी–छटनी को छोड़ कर जनहित व विकास में अपनी शक्ति का उपयोग करें। इसके साथ अपनी बात समाप्त करते हुए अपनी

श्री कुन्दन लाल भाटिया (फरीदाबाद): आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। साथ ही साथ मैं अपने आदरणीय मुख्य मंत्री महोदय चौधरी देवी लाल जी को भी इस बात की बधाई देता हूं कि उन्होंने चुनावों के दौरान बूढ़ों को पैन्शन देने और कर्जे माफ करने का जो वायदा किया था, उसको पूरा कर दिया है। हमारी सरकार ने किसानों को बहुत सी सहायता दी है। जिन किसानों के खेतों में से सड़क निकली हुई है यदि उसके साथ साथ पेड लगे हैं तो उसकी आमदनी का आधा हिस्सा अब किसानों को भी मिला करेगा, जबकि पहले ऐसा नहीं था। डा० मंगल सैन जी ने काफी कुछ बातें अपने भाषण में बोलते हुए कह दी हैं। उन बातों को मैं दोहराना नहीं चाहता। उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं अपने हल्के फरीदाबाद के बारे में कुछ एक बातें कहना चाहूंगा। मेरे हल्के फरीदाबाद के अन्दर 30–35 साल से एक थर्मल प्लांट लगा हुआ है। उसकी चिमनी सें धुआ निकलता है जो लोगों की सेहत के लिए नुकसानदायक है। इसके अतिरिक्त उसके कोयले से जो राख निकलती है वह भी वहीं पड़ी रहती है जिस की वजह से वहां हमेशा बीमारी फैलने का अन्देशा बना रहता है। इस बारे में मेरी सरकार से प्रार्थना है कि वहां पर जो राख इकट्ठी होती है उसकों भी हटवाने का और चिमनी से जो धुआ निकलता है उसका भी प्रबंध करें ताकि जो बीमारी का अन्देशा बना रहता है वह दूर हो सके। इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि फरीदाबाद में बहुत सी इण्डस्ट्रीज लगी हुई हैं। ईस्ट इण्डिया

कम्पनी और कुछ दूसरी इण्डस्ट्रीज कोयले की बजाये चावल के भूसे को इस्तेमाल करती हैं जिसकी वजह से वहां का वातावरण दूषित होता जा रहा है। इस बारे में मेरी सरकार से प्रार्थना है कि इस बात की तरफ ध्यान दिया जाये और यदि उन्हें कोयले की आवश्यकता है तो कोयला प्रदान किया जाये। पहले फरीदाबाद में 35 वर्ष पहले दो मंजिल तक पानी अवेलेबल हो जाता था लेकिन आज आबादी बहुत बढ़ गई है जिसकी वजह से वहां पर पानी की अति समस्या हो गई है एवं अब यह दो फुट नीचे मिल रहा है। पहले की अपेक्षा आज फरीदाबाद की आबादी 15 गुणा के आसपास बढ़ चुकी है जिसकी वजह से पानी की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इस संबंध में मेरी सरकार से प्रार्थना है कि वहां के लोगों के लिए पीने के पानी का उचित प्रबंध किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं शिक्षा के बारे में कहना चाहूंगा। वहां पर सरकारी स्कूल बहुत कम हैं। प्राईवेट स्कूलों को सरकार मान्यता प्रदान करती जा रही है। इन प्राईवेट स्कूलों में फीस भी बहुत अधिक होती है जिस कारण गरीब परिवारो के बच्चे उनमें पढ़ नहीं पाते। इस संबंध में मेरी सरकार से प्रार्थना है कि वहां पर सरकारी स्कूल भी अधिक से अधिक खोले जायें। जो स्कूल पहले के चल रहे थे वे ही आज चल रहे हैं जबकि शहर की आबादी कई गुणा बढ़ चुकी है। मेरी यह भी प्रार्थना है कि यदि वहां पर प्राईवेट स्कूलों को मान्यता प्रदान की जाती है तो इस बात का भी ध्यान रखा जाये कि वे फीस अधिक न लें ताकि गरीब

परिवारों के बच्चे भी वहां पर पढ सकें। दूसरे जो पुराने स्कूल हैं उनकी छतें गिरने को हो रही हैं इसलिए उनकी रिपेयर की तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। सरकारी स्कूलों में कमरे कम होने की वजह से वहां पर बच्चे सड्कों पर बैठ कर पढ़ते हैं। अतरू सरकार को चाहिए कि जहां पर कमरे कम हैं वहां पर और बनाये जायें ताकि बच्चे आराम से पढ सकें। उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार के नोटिस में लाना चाहता हूं कि प्राईवेट स्कूलों में काम करने वाले अध्यापकों को 200–400 रुपये दिए जाते हैं जबकि उनसे हस्ताक्षर 1000– 1200 रुपये प्रति मास के हिसाब से कराये जाते हैं। सरकार को इस बात की तरफ विशेंषकर ध्यान देना चाहिए और जहां कही ऐसी बात पकड़ी जाये उनके खिलाफ सख्त ऐक्शन लिया जाये। (इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए।)इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि फरीदाबाद में स्कूलों के बारे में पिछली सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। मैं सरकार को बताना चाहूंगा कि वहां के स्कूलों के पास दो अढ़ाई लाख रुपये तो फण्डज के पड़े हैं। अतरू सरकार को चाहिए कि वहां पर सरकार अपनी तरफ से कुछ पैसा और दे कत कमरे अधिक से अधिक बना दिए जायें ताकि बच्चों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े और प्राईवेट स्कूलों से गरीबों के बच्चों को छुटकारा मिल सके। दूसरे स्कूलों के अन्दर बच्चों के लिए पीने के पानी का प्रबंध भी नहीं है। सरकार को चाहिए कि वह हरेक स्कूल में बच्चों के लिए पीने के पानी का उचित प्रबंध करे। फरीदाबाद के अन्दर बी० के० हस्पताल आजं से 37 साल पहले

बना था। वहां पहले के ही कमरे बने हुए हैं, नया कोई कमरा नहीं बना है। कांग्रेस राज में वहां पर पत्थर जरूर लगाया गया लेकिन कोई नया कमरा नहीं बनाया गया। यह बी० के० हस्पताल बादशाह खां के नाम पर बना हुआ है। यह हस्पताल नहीं है बल्कि बूचड़खाना बना हुआ है। जिस प्रकार से प्राईवेट स्कूलों को महत्व दिया जाता है और सरकारी स्कूलों को नहीं दिया जाता, उसी प्रकार से सरकारी हस्पताल को भी महत्व नहीं दिया जाता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि फरीदाबाद के बी० के० हस्पताल में कमरे बनाये जायें और पानी का प्रबन्ध किया जाये। डाक्टरों के रहने के लिए भी कमरे बनाये जायें। फरीदाबाद में जो ई० एस० आई० डिस्पेंसरी है उसकी भी आज तक चारदीवारी नहीं बनाई गई है। इतने दिनों तक कांग्रेस राज रहा परन्तु उस डिस्पेंसरी की चारदीवारी नहीं बनी। इसलिए मेरा निवेदन है कि उसकी चारदीवारी बनाई जाये। जहां मरीजों के बैठने की जगह है वहां पर सूअर घूमते हैं। इसलिए उस तरफ ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जाये। फरीदाबाद में तारा चन्द सलूजा कें नाम से एक पैट्रोल पम्प है। वह पैट्रोल और डीजल में पचास परसैन्ट मिट्टी का तेल मिला कर बेचता है। इसलिए पेट्रोल पम्प की चौकिंग की जाये और उस के मालिक को मिट्टी का तेल मिलाकर बेचने से बन्द किया जाये। जब उसका कोई सैम्पल भरा जाता है तो वह उसकी कोई परवाह नहीं करता है। जो आदमी हजारों रुपये पैट्रोल और डीजल में तेल मिला कर कमाता है वह अपना सैम्पल पास करवाने के लिए हजार पांच सौ रुपये दे दे तो उसको कोई फर्क पड़ने

वाला नहीं है। इस पैट्रोल पम्प को वहां से उठकने की भी स्कीम थी। उसे पहले दूसरी जगह पैट्रोल पम्प लगाने के लिए जगह अलौट कर दी गई थी लेकिन उसने जगह अलौट होने के बाद भी वह पैट्रोल पम्प वहां से नहीं हटाया थी। अब उसे दुसरी जगह अलौट त्हर दी गर्द है। अगर उसे कोई दूसरी जगह अलोट कर दी है जोकि ग्रोन बेल्ट है तो पहले वाली जगह को वापिस लेना चाहिए। अगर सरकार वहां पर पुल बनाना चाहती है तो दूसरी दुकानदारों को भी जगह मिलनी चाहिए। दूसरे दूकानदारों को जगह नही मिती तो उसे क्यों दी गई? अगर उसे जगह दे दी है तो पुराने वाली वापिस लेनी चाहिए एक इसका मिट्टी के तेल का लाइसैंस कैन्सिल किया जाए।

मैं एक बात और भी अर्ज करना चाहता हूं। हमारे यहां फरीदाबाद में जवाहर औंर डबा कालोनी हैं। जवाहर कालोनी में डिवैल्पमैट चार्जिज 11 रुपये 40 पैसे प्रति वर्ग गज देने हिसाब से चार्ज किये कते हैं और डबा कालोनी मैं 30 रुपये के हिसाब से चार्ज किये जाते है। मैं आपके जरिए यह कहना चाहूंगा किं डबा कालोनी के डिवैल्पमैंट चार्जिज भी कम चार्ज किये जाये या जवाहर कालोनी के बराबर पेन चार्ज किये जाये। दोनों कालोनियों की जनता टैक्स बराबर का दे रही है तो वहां पर डिवैल्पमैंट चार्जिज भी बराबर के चार्ज किये जाये। इसी प्रकार से संजय कालोनी जींवन कालोनी और परवती कालोनी को भी डिवैल्प किया जाये। उन कालोनियों में बिजली ओर पानी का प्रबन्ध किया जाये।

इसी तरह से फरीदाबाद के अन्दर कुछ फैक्टरियां हैं जिनके आफिस फरीदाबाद की बजाए दिल्ली में हैं। फरीदाबाद से कलवीनेटर का फ्रिज अगर दिल्ली में आता है और उसके बाद वही विश्व फरीदाबाद में ले जाये तो हरियाणा सरकार को उसका कोई टैक्स नहीं मिलता। वह टैक्स दिल्ली की सरकार को मिलता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि उन फैक्टरियों के आफिस या तो फरीदाबाद में बनाये जायें या उनके साथ कोई मुहाइदा किया जाये ताकि हरियाणी सरकार को भी टैक्स मिल सके। कुछ बातें सेल्ज टैक्स के बारे मे भी कहना चाहता हूं। ये लोग एक तरफ तो कहते हैं कि गरींबों की सरकार है, लेकिन जब कोई गरीब आदमी पंखा खरीदता है तो उसे 12 परसैन्ट टैक्स देना पड़ता है और अगर अमीर आदमी एयर कन्डीशनर या रैफ्रीजरेटर खरीदता है तो 10 परसैन्ट टैक्स देता है। अगर यह टैक्स कम नही किया सकता है तो बराबर का कर दिया जाये ताकि गरीब आदमी को भी राहत मिल सके। गरीब आदमी तो पंखा भी किश्त पर खरीदता है। इसी तरह से फरीदाबाद के अन्दर सेल्ज टैक्स फर्स्ट प्वायंट पर चार्ज किया जाता है और इसके लिए सेल्ज टैक्स फार्म में नं० 14 तथा 15 भरना पड़ता है। उसके बारे में मैं यह कहूंगा कि फार्म 14 और 15 को खत्म किया जाये क्योंकि 90 परसैन्ट सेल नम्बर दो में होती है। टैक्स कम हो जायेगा तो टैक्स की चोरी भी कम होगी और टैक्स की मात्रा भी ज्यादा आयेगी। एक व्यापारी चोर या छः परसैन्ट कमाता है तो वह 12 परसैन्ट टैक्स कैसे भरेगा? इसी तरह ट्यूबलाइट है, उस पर भी 12 परसैन्ट टैक्स है, उस पर 8 परसैन्ट

टैक्स होना चाहिए। उसे भी कम किया जाये। वैसे तो फरीदाबाद को सोने की चिड़िया कहा जाता है लेकिन दूसरी तरफ फरीदाबाद कें अन्दर कोई भी भाई आराम से नही सो सकता है। वहां पर मच्छर बहूत ज्यादा हैं। जो भाई फरीदबाद में रहते हैं वै आराम से नहीं सोते हैं। अब मैं फरीदाबाद में झुग्गी झोपडियों के बारे में कहना चाहता हूं। उन झोपडियों में पिछले 30–35 सालों से हमारे भाई रहते आ रहे है। नीलम वाटा कालोनी नागा बाबा खोका और शिवाला कालोनी है, वहां पर ये लोग बड़ी देर से रह रहे हैं। मैं सरकार से कि इन झोपडियों से सरकार को कोई आमदनी तो नहीं होती इसलिए इस जमीन को अलाटमैंट उन लोगों को कर दी जाए। इससे सरकार को पैसा भी आएगा सर उसका खर्चा भी कम हो होगा इसके बाद मै यह कहना चाहता है कि फरीदाबाद में सब्जी मण्डी बनाने के लिए भी जल्दी ही फैसला किया जाए। इसी तरह से वहां पर 37 साल पहले नेहरु ग्राउंड नाम की मार्किट बनी थी लेकिन तक वहां पर कोई पार्क नही बनाया गया और न ही कोई सडक बनाई गई है। मेरी प्रार्थना है कि इनको भी जल्दी बनाया जाए। इसके साथ–साथ कुछ गांवों की सडके हैं। मैंने पिछली बार भी लिख कहा दिया था कि वे सडक बनाया जाए और अब मेरा सरकार से फिर अनुरोध है कि उन सड़कों को जल्दी से बनाया जाए। इन शब्दों के साथ मैं सब भाईयों का धन्यवाद करता हूं।

श्री गुरदयाल सिंह सैनी (थानेसर): अध्यक्ष महोदय, सदन में मुझे राज्यपाल महोदय के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव पर ओलने का समय देने के लिए आपका अति धन्यवाद। हरियाणा की जनता ने एक ऐतिहासिक संघर्ष किया और भ्रष्ट लोगों को सत्ता से हटाने में गोलियां खाई, जेल गये। नर–नारी, जवान–बूढ़े सभी लोगों ने इतना बड़ा संघर्ष किया जिस की मिसाल संसार में शायद ही कहीं मिलेगी। तीन शहीद मे में से मेरे जिले के श्री धर्म सिंह प्यौंदा को भी राज्यपाल महोदय के अभि– भाषण में, याद किया है। जिसके लिए सरकार को मैं बधाई देता हूं। अध्यक्ष महोदय हरियाणा के संघर्ष में मेरे जिले के लोग जन–धन में सबसे आगे रहे और यही जिला एक ऐसा रहा जहां और तो ने भी गोलियां खाई और जेल भी काटी।

अध्यक्ष महोदय, सरकार, ने गरीबों, पिछडे लोगों व मेहनतकश किसानों की भलाई के काम किये। उनके लिए सरकार धन्यवाद की पात्र है। हमारा संघर्ष नैतिकता पर आधारित, अंधिकारों की रक्षा और पेट की भूख खे जुड़ा हुआ संघर्ष था। इस इख्ताक की लड़ाई में लोगों ने अपनी ओर से पूरा तन–मन–धन से संघर्ष किया था। हुमारे नेता चौधरी देवी लाल ने लोगों की मान–मर्यादा व इज्जत को बचाने की लडाई की रहनुमाई की। आज इसकी जरूरत और भी ज्यादा है। देश में जात–पात, फिरका–परस्ती, फूट–परस्त ताकतों का ज हर फैल. रहा है। इसके सिए देश की निगाहें और आशाएं इस सदन के

नेता हिन्द केसरी चौधरी देवीलाल पर टिकी हुई हैं। इसलिए हमें अपने इख्लाक की लड़ाई के जरिये अनैतिक, गैर– जिम्मेदार, भ्रष्ट लोगों? के खिलाफ अपना यह संघर्ष देश को बचाने के लिये और भी मजबूती से लड़ना होगा ताकि जात–पात, साम्प्रदायिकता व कुनबा–परस्ती का जहर देश के अन्दर से मिटाया जा सके।

अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में अनेक कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र किया है जिसके लिए सरकार धन्यवाद की पात्र है। संघर्ष के दिनों में हमने लोगों से उनकी कई समस्याओं को हल करने के लिए विश्वास दिलाया था। बेशक आज सूखे के कारण और भारत सरकार की तगदिली व भेदभाव के कारण पैसे का अभाव है फिर भी हमें लोकहित की योजनाओं को ध्यान में रखना होगा। मेरे क्षेत्र में भूमिगत वाटर लैवल बहुत नीचे चला गया है जहां से मोनोब्लाक मोटरें पानी उठाने से जवाब देने लगी हैं। 70–80 फुट गहरे गढ़े मोटरों के चले गये हैं। सैकड़ों किसान मजदूर इन गढ़ों में दब कर मर चुके हैं। हरियाणा का यह उपजाऊ यह ऐरिया रेगिस्तान बनता जा रहा है। यदि यहां की इस समस्या की ओर सरकार ने तत्काल ध्यान नहीं दिया तो अन्न की समस्या भी पैदा हो सकती है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि मेरे इस क्षेत्र में ताजेवाला से यमुना नहर का पानी नहरी सिंचाई के रूप में पहुंचाया जाए। इस क्षेत्र के लोगों की खेती इतनी महंगी व जोखिमपूर्ण हो चुकी है कि किसान कर्ज के नीचे दबते जा रहे हैं। सरकार इस को युद्ध स्तर

पर ले, सर्वे कराये और नहर की योजना को लागू करके मेरे इस क्षेत्र को रेगिस्तान होने से बचाये। इससे हरियाणा का ही नहीं, बल्कि देश का भी भला होगा। अध्यक्ष महोदय, सरकार की ओर सै बहुत कुछ किया गया है पर इससे ही हमें सन्तुष्टि नही कर लेनी है। हमारे नेता का यह नारा लोकतन्त्र की जानु है कि लोकराज लोकलाज से चलता है मेरा यह विश्वास है कि यदिं हम इस नारे को जीवन में ढाल लें तो कोई बात नहीं कि हमारा समाज और देश सच्चे अर्थ में लोकतन्त्र का मजबूत आधार न बने। आज देश को, समाज को उन लोगों से कहीं ज्यादा खतरा है जिनके अन्दर लोकलाज नहीं रह गई है। अगर लोकलाज रहेगी तब ही भय–शर्म रहेगी कि लोग उसे क्या कहेंगे। जब ऐसे लोग आगे होंगे जिनका जीवन ऐसा हो गया है किं जिसने तार दी लोई, उस का क्या करेगा कोई स्पीकर साहब, लोकलाज ही एक ऐसा मूलमन्त्र है जिसके मानने और उसको जीवन में अपनाने से ही इन्सान जात–पात, फिरका–परस्ती, कुनबा–परस्ती व समाज विरोधी गैर–इख्लाकी कामों से बाज आ सकती है अंकुश लग सकता है। आज इस मूलमन्त्र को समाज में उतारने की सख्त जरूरत है, तभी भ्रष्टाचार पर रोक होगी, भाईचारा बढ़ेगा।

अध्यक्ष महोदय, अच्छे लोगों की सरकार की तरफ से बड़ाई नहीं होगी तरक्की नही होगी, बुरे लोगों को दण्ड नहीं मिलेगा, बुराई भलाई में पहचान नहीं रहेगी, अच्छे–माड़ धर्मी–पापी, जिस समाज में एक समान व्यवहार पर होगें, तब

समाज का गिरावट की ओर जाना स्वाभाविक है। इसीलिये सदन के नेता हिन्द केसरी, चौधरी देवीलाल के इस नारे को आज के हालात में और भी ज्यादा अहमियत है कि लोकराज–लोकलाज से चलता है।

मेरे इलाके में सोन्टी गांव के पास 500 एकड़ का एक जंगल है जिस में नील गाय और बन्दर वगैरा रहते हैं जो कि गांव की आस पास की फसलों को तवाह करते हैं। मेरा निवेदन है कि इस जंगल के चारों तरफ कांटेदार तार लगवा दी जाए। स्पीकर साहब, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि कुरूक्षेत्र युनिवर्सिटी में वाईस चान्सलर और रजिस्ट्रार रैगुलर तौर पर लगाए जाने चाहिएं। हमारे जिला में नर्सी का एक ट्रेनिग सैन्टर जरूर खोला जाना चाहिए। इसके इलावा मैं कहना चाहूंगा कि किसानों के लिए खरपतवार व कीडे मार दवाइयों का भी इन्तजाम किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त स्पीकर साहब, मैं कहना चाहता हू कि 20 के करीब करनाल जिला के गांव ऐसे हैं जो कुरुक्षेत्र से केवल 2 किलोमीटर से 5 किलोमीटर के एरिया में पड़ते हैं, वे गांव कुरुक्षेत्र जिले में आना चाहते हैं। सरकार ने जिलों के पुर्नगठन के विषय में परामर्श देनें के लिए एक कमेटी बनाई है। मेरा निवेदन है कि वह कमेटी इन गांवों को जिला कुरुक्षेत्र में मिलाने की सिफारिश करे। स्पीकर साहब, एक बार मैं फिर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं तथा आपने मुझे जो समय बोलने के लिये

दिया हे, उसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद करता हूं और अपना स्थान लेता हूं।

श्री भगवान सहाय रावत (हथीन): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मेरा यह कर्त्तव्य बनता है कि आफने जो मुझे बोलने के लिये समय दिया है उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करूं। साथ ही महामहिम राज्यपाल महोदय के अभि– भाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव डाक्टर मंगल सैन जी ने रखा है और जिसका अनुमोदन श्री रण सिंह जी ने किया है, मैं उसका समर्थन और अनुमोदन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। सर्वप्रथम आज जहां हम हरियाणा प्रान्त की जनता की आवाज को पहुंचा रहे हैं वहां पर अगर हम इस सरकार के कृत्यों को गिनने लग जायें तो आदमी की जबान थक जाती है लेकिन इस सरकार के जो जन–कल्याण के क्रिया–कलाप हैं, उनका अन्त नहीं आता। सर्वप्रथम तो इस सदन के नेता माननीय चौधरी देवी लाल जी और दूसरे जन–प्रतिनिधि जो इस संघर्ष के बाद चुनकर आयें वह वह सभी धन्यवाद के पाए हैं जो मेरे साथियों ने एक–एक करके काम गिनाये है, वे प्वायंट्स निश्चित रुप से महामहिम राज्य पाल महोदय के अभिभाषण में सरकार के नीति निर्देशक सिद्धांता के रूप में दिये गये हैं। इस अल्प संमय में किये गये विकस कार्यो को वैसे तो गिना दिया गया है लेकिन मैं भी संक्षेप मै उनका विवरण देना चाहता हू और उन पर अपने मतानुसार अपने विचार प्रकट करना चाहूग। मुझे पिछली बार एक आवश्यक कार्य के लिये

मद्रास जाना पड़ा। मेरे काग्रेसी भाई जहां हरियाणा के अस्तित्व और विकास के लिये पूर्व मुख्य मन्त्री श्री बंसी लाल और दूसरों का नाम गिनाते हैं, वहां उस बारे में मेरे अपने प्रात से ही नही बल्कि, दूसरे प्रान्तों में भी सब जगह अगर हरियाणा का नाम गिर जाता है तो वह बसी लाल से नही, भजन लाल से नहीं इनका अगर कभी कम होता था तो आया राम गया राम की वजह से नाम होता था लेंकिन उच्च आप हरियाणा का नाम लेते हो तो लोग पूछते है कि कहां से हो, मैं कहता है कि हरियाणा से तो वह कहते हैं हैं कि चौधरी देवी लाल के हरियाणा से हरियाणा का अस्तित्व हरियाणा का विकास, हरियाणा की मान मर्यादा के प्रतीक चौधरी देवी लाल हैं न, कि कोई और सज्जन जिनको पूर्ववर्ती के नाम से जोड़ा गया है। उनको सुधार करके नये प्रयास विकास के क्षेत्र में किये गये है। चौधरी देवी लाल ने नया मार्ग प्रशस्त किया है। हमारी उम्र के सब लोगों को इनका धन्यवादी होना चाहिये। हम अभी समझते थे कि आजादी से पूर्व हमे भी मौका मिला होता स्वतन्त्रता संग्राम में लड़कर लोगों की तरह कमने देश की रक्षा की होती। आज की बात के लिये चौधरी देवी लाल और जनता जनार्दन के हम सब कृतज्ञ हैं कि जिन्होने 1947 के बाद 1987–88 में राजनीतिक आजादी दिलाकर हमारे दोस्तों ने यह मौका दिया है कि जो हमारे नये बच्चे जन्म ले रहे है उन के नाम हर अपने नेता पर रख सकें। जिस तरह से काली ऐमरजैन्सी के दौरान लाभान्वित होने वालों के नाम ईवन छोटी सी दुकान का नाम संजय टी स्टाल और संजय हेयर कटिंग सैलून होता था।

आज हजारों बच्चे चौधरी देवी लाल के नाम पर जन्म ले रहे हैं और पिता उनके नाम चौधरी देवी लाल के नाम पर रख रहे है। इससे ज्यादा मैं इस बारे में और क्या कहूं। जो कानून और व्यवस्था की हालत है, इस बारे में भी यहां पर कहा गया है कि हरियाणा पंजाब के साथा लगता हुआ प्रान्त है जहां पर केन्द्र सरकार का शासन है और उसकी पूरी जिम्मेवारी है। वहां पर एक हद तक अमानुषकता का तांडव हो रहा है। उसके पडोसी राज्य लें उसकी जरा सी हवा भी नही लगने पायी है। अगर हवा दरियापुर में लगी भी थी तो चौधरी देवी लाल के नेतृत्व वाली सरकार ने अपने तमाम प्रयासो के बाद उस आधी को वहीं पर रोक दिया था। आज हमारे सम्मुख माननीय सदस्य और कांग्रेसी साथी चौधरी तैयब हुसैन जो बैठे हैं। मुझे 1972 की बात याद है। उस वक्त चौधरी बंसी लाल यहां पर मुख्य मन्त्री होते थे जिनकी प्रशंसा करते ये शब्दों की कमी नहीं रखते थे। यह उस वक्त हुमारे साथी हुआ करते थे। उस तानाशाही का विरोध करते हुए हमारा साथ दिया करते थे जिला परिषदों के 5 बार इलैक्शन पोस्टपोन किये गये थे। उस आधार पर चौधरी साहब ने उस अप्रजातात्रिंक कृत्यों का विरोध किया था और निन्दा की थी। मैं अपनी सरकार से एक मांग करता हूं। चौधरी बंसी लाल के टाईम पर जो जिला परिषदों को खत्म किया गया था, हमारी सरकार उसको जीवित करके एक उदाहरण पेश करे। जिस तरह से इसने नगरपालिकाओं के चुनाव करा करके एक प्रजातांत्रिक पद्धति स्थापित की है, उसी तरह से उसको भी जीवित करके उसके भी इलैक्शन कराये जायें।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं सूखा राहत के बारे में कहना चाहता हूं। मेरे पास कहने के लिए शब्द नहीं हैं। सीमित साधनों और अल्प साधनों के बावजूद इस सीमित समय में इस सरकार ने बहुत अधिक विकास कार्य किए हैं और विकास कार्यो को जारी रखे हुए है। केन्द्र की तरफ से बहुत ही अल्पमात्रा में सहायता मिलने के उपरान्त भी हरियाणा प्रान्त फलफूल रहा है। स्पीकर साहब, केन्द्र ने हमको एक तुच्छ राशि जो लगभग 37 करोड़ यानी 36 करोड़ 22 लाख है दी है। नागालैन्ड जैसा राज्य जिसकी आबादी हमसे बहुत कम है उसको भी हमसे जादा राशि दी है। इतनी अल्प माता में हरियाणा को राशि देना यह दर्शाता है कि इससे ज्यादा पक्षपात और कोई नहीं हो सकता। स्पीकर साहब, हमारे मुख्य मन्त्री हिन्द केसरी चौधरी देवी लाल, जबकि सदन चल रहा है, लोगों को मालूम नहीं है, उपायुक्तों को मालूम नहीं है, सारी गरिमा को ध्यान में रखते हुए और इस उम्र में किसानों को सान्तवना देने के लिए सोनीपत जिले का भ्रमण कर रहे हैं। जहां पर ओलों की वजह से फसल नष्ट हो गई है वहां पर एक किसान को चार सौ रुपया फी एकड के हिसाब से दिया जाएगा। जहां 75 प्रतिशत फसल नष्ट हुई है उस किसान को तीन सौ रुपया फी एकड़ के हिसाब से दिया जाएगा और जहां पचास फीसदी फसल नष्ट हुई है उनको दो सौ रुपया फी एकड़ के हिसाब से सहायता दी जाएगी। इसको कार्यान्वयन करने के लिये उन्होंने आदेश दिए हैं कि आधी राशि मौके पर ही दी जाए। यह बात सभी लोगों ने अखबारों में पढ़ी होगी। स्पीकर साहब, अब मैं एस० वाई० एल०

के बारे में कहना चाहता हूं। हमें बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इसके लिये केन्द्र जिम्मेदार है और पंजाब सरकार जिम्मेदार है। हरियाणा सरकार द्वारा अपना हिस्सा पूरा करने के पश्चात और सारा पैसा विकास कार्यों पर लगाने के बावजूद भी हम अपने हिस्से का पूरा पानी प्रयोग नही कर पा रहे हैं। इस पर मन्द गति से और चूहे की गति से कार्य चलने के कारण हम नही कह सकते कि इसका कार्य कब तक पूरा हो जाएगा। यह नहीं कहा जा सकता कि यह जनरेशन या अगली जनरेशन इसको प्रा करने के लिये उत्तरदायी होगी। जनता ने एस० वाई० एल० के लिये संघर्ष किया और उसका परिणाम यह निकला कि यह विधान सभा बनी और यह सरकार बनी। आज हमारे मुख्य मन्त्री और इरिगेशन एंड पावर मिनिस्टर केन्द्र से विभिन्न स्तरों पर बातचीत कर रहे हैं और केन्द्र सरकार पर जोर दे रहे हैं कि जल्द से जल्द इसका काम पूरा होना चाहिये। इससे पता लगता है कि केन्द्र की नियत हमारे प्रति क्या है।

स्पीकर साहब, अगली बात बिजली की है। विकास का आधार विद्युत होता है।

श्री अध्यक्षः अब केवल तीन मिनट बाकी हैं।

श्री भगवान सहाय रावतः मै तो आखिर में बोला हूं। अगर समय नही है तो मैं अगले दिन कंटीन्यू रखूंगा। अब बीच में कोई नही बोलेगा। मैं कन्टीन्यू रहूंगा, यदु मेरी आपसे रिक्वैस्ट है।

स्पीकर साहब, जहां तक हरियाणा का ताल्लुक है यह कृषि प्रधान प्रदेश है और यहां की जनता कृषि पर आधारित है मौर इस स्टेट की अर्थ व्यवस्था कृषि पर निर्भर करती है तथा सिंचाई साधनों पर निर्भर करती है। हमारे महामहिम गवर्नर साहब ने अपने ऐडैरस में यह स्पष्ट संकेत दिया है कि आगामी समय में विद्युत सप्लाई और उसके विस्तार करने के जिये हमारी सरकार कितना प्रयत्न करेगी। फरीदाबाद जिले का नाम भाटिया जी ने लिया और वे आमदनी के साधन गिना रहे थे। मैं यह कहना चाहूंगा कि फरीदाबाद शहर के अलावा वहां देहात की जनता भी बसती है। यहां सियासी और दूसरे बाहर कें प्रतिनिधि बैठे हुए हैं। उन्होंने कभी इस हरियाणा के शहर के देख होगा। मेरे महान साथों चौधरी रणजीत सिंह कह रहे थे कि पहले इंडस्ट्रिलिस्टस से और दूसरे लोगो से पैसा बटोरने के लिये पूर्ववर्ती सरकार के लोग फरीदाबाद जाते थे। आज हमारी लोक प्रिय सरकार है। हम उससे आशा करते हैं कि वह फरीदाबाद की जनता की जरूरतों को पूरा करेगी और बिजली की जो कमी है उसको भी पूरा करेगा। स्पीकर साहब होडल और पलवल के बीच में औरंगाबाद पड़ता है और हथीन ओर होडल के बीच में कहनि गांव पड़ता है। वहां 33 के० सी० का सब–स्टेशन लगा–शर वहां की स्थनीय आपूर्ति की पूर्ति को जांए। यहां पर विद्युत छी बैठे हैं, मेरी प्राथना है कि किसान को लाभ पहुंचने का वे कष्ट करेंगे। इसके अतिरिक्त बहुत ही जरूरी और बहुत ही अहम मुद्दा पैन्शन और कर्जा माफी का है। मैं केवल पैन्शन के विषय में एक ही शब्द कहना चाहूंगा। मेंरे सन्धा मित्र जानते होंगे दिये

बुजुर्गों का घरों में कितना सम्मान रहता है। काश कि आज हम बूढ़े होते तो समझ पाते। चौधरी देवी लाल की सरकार द्वारा सौ रुपए का मासिक पैन्शन देकर कोश अर्थ लाभ ही नहीं दिया गया है बल्कि बुजुर्गों की घरों में सम्मान की हालत बन गई है। यह उनको एक तरह से ग्लूकोस दिया गया है। जब वह बूढ़े माता पिता और वह वृद्धा अपनी अपनी पुत्री को विदा होते हुए देखते थे तो उनकी जेब है पैसा नहीं होता था। आज उस सौ रुपए में से दस रुपये का या पांच रुपए देकर उस बूढ़े माता पिता को बहुत प्रसन्नता होती है।

श्री अध्यक्षः रावत जी अब हाउस को समय हो गया है। आप कंटीन्यू करेंगे।

हाउस सोमवार, 21 मार्च, 1988 दोपहर 2.00 बजे तक के लिये ऐडर्जन किया जाता है।

(13.30 बजे)

(तत्पश्चात सदन सोमवार, 21 मार्च, 1988, को बाद दोपहर 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुआ)